आज का विचार
अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता उसका कार्य ही उसे सम्मान का पात्र बना देता है।

दैनिक सिटी दर्पण
आईना सच का

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ | वीरवार, 30 अप्रैल, 2026 | वर्ष 24, अंक 103, मूल्यः 3 रुपए, पृष्ठ 8 | RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 | www.citydarpan.com

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में बेहतर और अनुकरणीय प्रथाओं तथा नवाचारों पर चंडीगढ़ में 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में बेहतर और अनुकरणीय प्रथाओं तथा नवाचारों पर 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन 30 अप्रैल से 1 मई, 2026 तक चंडीगढ़ में करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और राज्य की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती आरती सिंह राव की गरिमामयी उपस्थिति में करेंगे। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (स्वास्थ्य), मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के वरिष्ठ नोडल अधिकारी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी) और क्षेत्रीय संसाधन केंद्र-पूर्वोत्तर (आरआरसी-एनई) के प्रतिनिधि भी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे।

राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, स्वास्थ्य मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए अपनाई गई नवोन्मेषी और प्रभावशाली पद्धतियों को प्रदर्शित करना, मान्यता देना और उनका दस्तावेजीकरण करना है। यह आपसी ज्ञानवर्धन के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है और देश भर में सफल और व्यापक रूप से लागू किए जा सकने वाले मॉडलों के अनुकरण को सुगम बनाता है। वार्षिक शिखर सम्मेलन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नवोन्मेषी, साक्ष्य-आधारित और परिणाम-उन्मुख कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करता है, जिनसे स्वास्थ्य परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं।

2013 में अपनी स्थापना के बाद से, इस पहल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण में अनुभवों और नवाचारों को साझा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ लाया है। शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण 28 फरवरी से 1 मार्च, 2025 तक पुरी में आयोजित किया गया था। मौजूदा वर्ष के लिए, 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की प्रक्रिया अप्रैल 2025 में शुरू हुई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा नवाचार पोर्टल (एनएचआईएनपी) के माध्यम से अपनी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और नवाचारों को प्रस्तुत किया। सभी प्रस्तुतियां मंत्रालय के संबंधित कार्यक्रम प्रभागों द्वारा सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और अंक प्रदान किए गए। इन मूल्यांकनों के आधार पर, कार्यक्रम प्रभागों से प्राप्त सुझावों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के सहायक एवं निदेशक मंडल की अध्यक्षता में विस्तृत समीक्षा के बाद शिखर सम्मेलन के लिए कुल 13 मौखिक प्रस्तुतियां और 32 पोस्टर प्रस्तुतियां चयनित की गई हैं।

प्रस्तुतियों के अलावा, शिखर सम्मेलन में नवंबर 2025 में 17 राज्यों में आयोजित 17वें संयुक्त समीक्षा मिशन (सीआरएम) की रिपोर्ट का प्रसार भी किया जाएगा। इस कार्य के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों, अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों, विकास भागीदारों और मंत्रालय के सलाहकारों से युक्त 17 बहु-विषयक टीमों का गठन किया गया था। सीआरएम के निष्कर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के कामकाज में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और भविष्य की नीति एवं कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों को दिशा देने में सहायक होंगे। इस शिखर सम्मेलन में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचारों और सेवा वितरण प्रणालियों में सुधार जैसे प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित पूर्ण सत्र, विषयगत चर्चाएं और प्रदर्शनियां होंगी। ये प्रयास आयुष्मान भारत और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसी प्रमुख पहलों के अनुरूप हैं।

प्रधानमंत्री ने हरदोई में 36,230 करोड़ की लागत से निर्मित 594 किमी लम्बे गंगा एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण किया

एक्सप्रेस-वे प्रदेश की समृद्धि का आधार बन रहे, गंगा एक्सप्रेस-वे यूपी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही : योगी

सिटी दर्पण संवाददाता
लखनऊ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज जनपद हरदोई में 36,230 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 594 किलोमीटर लम्बे गंगा एक्सप्रेस-वे (मेरठ-प्रयागराज) का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान गंगा एक्सप्रेस-वे से सम्बन्धित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गयी। इससे पूर्व, प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम स्थल पर पौधरोपण किया तथा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

प्रधानमंत्री जी ने नृसिंह भगवान की भूमि को नमन करते हुए कहा कि यहां माँ गंगा अपनी कृपा बहाती हुई गुजरती हैं। यह पूरा क्षेत्र किसी तीर्थ से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस-वे का वरदान माँ गंगा का आशीर्वाद है। अब लोग कुछ ही घण्टों में संगम पहुंच सकते हैं तथा काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन कर वापस आ सकते हैं। जिस प्रकार माँ गंगा हजारों वर्षों से देश व उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा रही हैं, उसी प्रकार आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरने वाला यह एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश के विकास की नई लाइफ-लाइन बनेगा।

प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस-वे प्रदेश के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने के साथ ही एन0सी0आर0 की सम्भावनाओं को समीप लाएगा। इस पर गाड़ियां तो दौड़ेंगी ही, साथ ही एक्सप्रेस-वे के किनारे नये औद्योगिक अवसर भी विकसित होंगे। इसके लिए हरदोई के साथ ही अन्य जनपदों में इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किये जा रहे हैं। इससे हरदोई, उन्नाव व शाहजहांपुर सहित सभी 12 जनपदां में नये उद्योग स्थापित होंगे। फार्मा, टेक्सटाइल जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में क्लस्टर्स विकसित होंगे। युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस-वे की रफ्तार से ज्यादा उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार है। यह एक्सप्रेस-वे केवल हाई स्पीड सड़क नहीं है, बल्कि नई सम्भावनाओं, नये सपनों और नये अवसरों का गेट-वे है।

प्र्रधानमंत्री जी ने कहा कि लगभग 600 कि0मी0 लम्बे गंगा एक्सप्रेस-वे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, बुलन्दशहर, हापुड़, अमरोहा, सम्भल और बदायूं, मध्य उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली, पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और प्रयागराज तथा इनके आस-पास के अन्य जनपदों के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। इन क्षेत्रों को माँ गंगा और सहायक नदियों की उपजाऊ मिट्टी का वरदान मिला है। इस एक्सप्रेस-वे के माध्यम से कम समय में बड़े बाजारों तक पहुंच आसान होगी। यहां खेती के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। इससे अन्नदाता किसानों की आय बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों से उनकी विराट सोच के अनुरूप गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन हो रहा है। हरदोई भगवान नृसिंह, वामन अवतार तथा श्रीहरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के अवतरण की पावन धरा है। यह भूमि माँ गंगा के आशीर्वाद से अभिसिंचित है। उन्होंने माँ गंगा स्तुति- ह्यदेवि सुरेश्वरि भगवति गंगे, त्रिभुवनतारिणि तरलतरंगेह्य करते हुए कहा कि माँ गंगा के समानान्तर उस विराट को छूने तथा उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को नई उड़ान देने के लिये गंगा एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने दिसम्बर, 2021 में किया था।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को आगे बढ़ाने तथा तय समयसीमा में पूरा करने का विजन दिया था।

गंगा एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके विजन को स्पष्ट नीति और साफ नीयत के साथ प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने का कार्य किया गया। आज देश में हम नये भारत का दर्शन कर रहे हैं। नये भारत के नये उत्तर प्रदेश में यह आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारे आवागमन को सरल व सुगम बनाएगा तथा अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई प्रदान करेगा।

राज्यसभा सदस्यों द्वारा पार्टी बदलने के संबंध में मान 5 को राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात

यज्ञांश शर्मा
चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि वे 5 मई को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और सात राज्यसभा सदस्यों, जिनमें पंजाब के 6 सदस्य भी शामिल हैं, द्वारा गैरकानूनी तरीके से पार्टी बदलने का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात के समान हैं।

- जनता के जनादेश से किए विश्वासघात का मुद्दा उठाएंगे
- रेलवे धमाके की जांच जारी; दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगाः मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, हमें राष्ट्रपति भवन से पुष्टि मिल गई है और 5 मई को हम भारत की राष्ट्रपति से मुलाकात करके सात सांसदों, जिनमें पंजाब के छह सदस्य भी शामिल हैं, द्वारा गैरकानूनी तरीके से पार्टी बदलने का मुद्दा उठाएंगे। ये सांसद जिन्होंने जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात किया है, वे किसी भी रहम के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे पंजाब और पंजाबियों के गद्दार हैं।

उन्होंने आगे कहा, जो लोग इस दल-बदल को आजकल का चलन या परंपरा बता रहे हैं, वे जनता के जनादेश के प्रति इस गंभीर उपेक्षा को जायज ठहरा रहे हैं। यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ऐसा लगता है, इस तरह की बयानबाजी करने वाले लोग अपनी वफादारी बदलने की तैयारी कर रहे हैं।

सरकार की मजबूती की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार को विधानसभा के अंदर और बाहर पूरा समर्थन है, जिसके कारण फ्लोर टेस्ट की कोई भी मांग अनावश्यक है। उन्होंने आगे कहा, जहां बजट सुचारू रूप से पास हुआ है, वहीं हर छोटे या बड़े बिल ने सफलतापूर्वक फ्लोर टेस्ट पास किया, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार के पास सदन में पूर्ण बहुमत है।

आलोचकों पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा, जो लोग विधानसभा सत्र बुलाने के तर्क पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें हम पर सवाल उठाने से पहले मोदी सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का जवाब देना चाहिए।

हाल ही में रेलवे ट्रैक धमाके की घटना पर एक सवाल के जवाब में, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार, केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने जोर देकर कहा, आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए जांच जारी है और इस अपराध में शामिल दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

पानी के बंटवारे के मुद्दे पर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हरियाणा ने इस साल अपने हिस्से के पानी का अधिक समझदारी से उपयोग किया है, जिससे विवादों से बचाव रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से मुलाकात के बाद, पंजाब से अनाज की उठाई को तेज कर दिया गया है। उन्होंने कहा, यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य से अनाज की ढुलाई के लिए 290 विशेष रेलगाड़ियां इस कार्य में लगाई गई हैं, जिससे चावल की फसल के लिए उचित भंडारण सुनिश्चित होगा।

पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण में छिटपुट हिंसा के बीच 91.41 प्रतिशत मतदान

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे एवं अंतिम चरण में भी छिटपुट हिंसा के बीच बंपर मतदान हुआ। राजधानी कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के सात जिलों की 142 सीटों के लिए 91.41 प्रतिशत मतदान हुआ। मतगणना चार मई को होगी और नतीजे भी दोपहर 12 बजे तक स्पष्ट हो जाएंगे कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक सुबह 07 बजे शुरू हुए मतदान के बीच 9 बजे तक करीब 18 प्रतिशत, 11 बजे तक 39.97 प्रतिशत, दोपहर 01 बजे

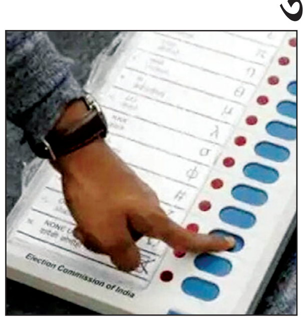

तक 61.11 प्रतिशत तथा दोपहर 03 बजे तक 78.68 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। पूर्व बर्धमान में सबसे अधिक 93.39 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया जबकि सबसे कम कोलकाता दक्षिण में 87.25 प्रतिशत मतदान हुआ है। इसके अलावा हुगली जिले में 91.41 प्रतिशत, हावड़ा में 90.93 प्रतिशत, कोलकाता उत्तर में 88.91 प्रतिशत मतदान हुआ है। नदिया जिले में 91.35 प्रतिशत, उत्तर 24 परगना में 91.39 प्रतिशत तथा दक्षिण 24 परगना में 91.45 प्रतिशत मतदान हुआ है।

दूसरे और आखिरी चरण में कुल 1,448 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। इस चरण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर सीट पर आमने-सामने हैं। इसके अलावा राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम, अरूप बिश्वास, जावेद खान, सुजीत बसु, शशि पांजा समेत सत्तारूढ़ तृणमूल सरकार के कई मंत्री, बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार, माकपा की मीनाक्षी मुखर्जी और दीप्शिता धर शामिल हैं। इसके अलावा आरजी कर अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या की शिकार हुई डॉक्टर की मां रत्ना देवनाथ एवं संदेशखाली आंदोलन का चेहरा रेखा पात्र भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं। दक्षिण बंगाल के सात जिलों कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली, नदिया और पूर्व बर्धमान की 142 सीटों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये थे।

जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली जरूरीः ओम बिरला

एजेंसी (हि.स.)
देहरादून

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सतत विकास व पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों - सरकारी संस्थानों, पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकायों, वन पंचायतों तथा नागरिकों की संयुक्त एवं सक्रिय भागीदारी का आान किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का सम्मान करना दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता और राष्ट्रीय प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। बुधवार को नैनीताल स्थित डॉ. रघुनंदन सिंह टोलिया प्रशासनिक

अकादमी में वन पंचायत प्रतिनिधियों व त्रिस्तरीय पंचायत व स्थानीय शहरी निकाय के निर्वाचित सदस्यों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि उत्तराखंड की वन पंचायतें सामुदायिक भागीदारी आधारित वन प्रबंधन का एक सफल मॉडल बनकर उभरी हैं, जो न केवल वन संरक्षण एवं संवर्धन में योगदान दे रही हैं, बल्कि रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी साकार कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने प्रतिनिधियों से सीधे संवाद कर उनके अनुभव, चुनौतियों और सुझावों को भी सुना। वन पंचायतों को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे सशक्त कड़ी बताते हुए बिरला ने कहा कि जमीनी स्तर की संस्थाएं संरक्षण और सुशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वन पंचायत से संवाद करना मेरे लिए लोकतंत्र की सबसे सशक्त कड़ी से मिलने जैसा है।

नायब सैनी से मिले किसान, आईएमटी के लिए किसानों ने सरकार द्वारा तय दरों पर भूमि देने पर जताई सहमति

भूपेंद्र शर्मा
चंडीगढ़

हरियाणा में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने नारायणगढ़ में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस पहल से न केवल क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी, बल्कि प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाने में भी मदद मिलेगी। इस संबंध में बुधवार को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से यहां नारायणगढ़ क्षेत्र के किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और बैठक में हिस्सा लिया। आईएमटी के लिए किसानों से भूमि की दरों में संबंध में विस्तार से चर्चा की गई और किसानों ने सरकार द्वारा तय की गई दरों पर सहमति जताई। इससे आईएमटी के लिए नारायणगढ़ में लगभग 450 एकड़ भूमि उपलब्ध होगी। आईएमटी स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ होने पर किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उनका मुंह मीठा कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने किसानों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम क्षेत्र के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबाला में पहले से ही आईएमटी विकसित करने का कार्य तेज गति से चल रहा है। अब नारायणगढ़ में भी आईएमटी विकसित होने से इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। गुरुग्राम की तर्ज पर अंबाला क्षेत्र को भी आधुनिक और विकसित औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आईएमटी से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्होंने बतौर वित्त मंत्री बजट में घोषणा की थी कि प्रदेश में 10

- नारायणगढ़ में स्थापित होगा आईएमटीः नायब सैनी
- आईएमटी स्थापना की प्रक्रिया शुरू होने पर किसानों ने मुख्यमंत्री का मिठाई खिलाकर जताया आभार

इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से मानेसर, बावल, रोहतक, फरीदाबाद, सोहना और खरखौदा में पहले ही आईएमटी विकसित किए जा रहे हैं। मिक्सी उद्योग एवं चिकित्सा उपकरण निर्माण के लिए प्रसिद्ध अंबाला अब 2 नए आईएमटी के माध्यम से अपनी औद्योगिक पहचान को और सुदृढ़ करेगा। नारायणगढ़ में आईएमटी की स्थापना के साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने 2025-26 के बजट अभिभाषण में की गई घोषणाओं को एक वर्ष के भीतर धरातल पर उतारकर यह सिद्ध कर दिया है कि उनकी नीतियां केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि क्रियान्वयन में भी उतनी ही प्रभावी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ह्यविकसित भारत 2047ह्न की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हुए हरियाणा सरकार भी विकसित हरियाणा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार स्पष्ट

विजन है हर क्षेत्र का संतुलित विकास सुनिश्चित करना। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक श्री सुशील सारवान, उपायुक्त अंबाला श्री अजय सिंह तोमर, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री यशपाल के अलावा, हरियाणा से आए किसानों में पूर्व चेयरमैन पवन गुर्जर, रणबीर सिंह सरपंच, राकेश, मुकेश कुमार, फकीर चंद, धनीराम, विक्की, गफ्फर नसीम, कृष्ण अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की मजबूती में मील का पत्थर साबित होगा ढगवार मिल्क प्लांट : मुख्यमंत्री सुक्खू

कहा, हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई उड़ान

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के ढगवार में निमार्णाधीन अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र (मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट) का निरीक्षण किया। 225 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा यह प्रोजेक्ट राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक 'गेम चेंजर' साबित होने वाला है। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि स्थानीय किसानों और युवाओं को इसका लाभ जल्द से जल्द मिल सके।

ढगवार में स्थापित किया जा रहा यह संयंत्र न केवल हिमाचल प्रदेश का बल्कि उत्तर भारत का एक प्रमुख दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र बनकर उभरेगा। इसकी शुरूआती क्षमता 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन (एलपीडी) दूध संसाधित करने की है, जिसे भविष्य की आवश्यकताओं

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए 'गेम चेंजर' साबित होगा यह प्रोजेक्ट: सीएम

और मांग को देखते हुए 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह संयंत्र कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और चंबा जिलों के हजारों दुग्ध उत्पादकों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है। अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में भौगोलिक चुनौतियों के कारण दूध का सही दाम और बाजार तक पहुँच न मिल पाना किसानों की एक बड़ी समस्या रही है। यह प्लांट इस चुनौती को समाप्त करेगा। यहां दूध के संग्रह से लेकर प्रसंस्करण तक की अत्याधुनिक व्यवस्था होगी, जिससे किसानों का दूध खराब नहीं होगा और उन्हें उनके उत्पाद का वाजिब दाम सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होगा। यह कदम राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 'दुग्ध क्रांति' लाने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। इस संयंत्र की सबसे बड़ी विशेषता इसका 'वैल्यू एडिशन'

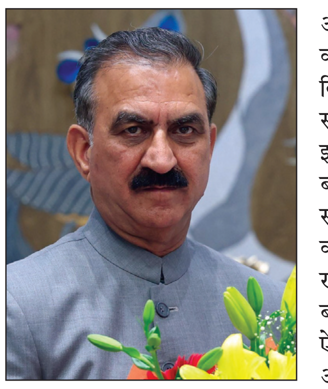

(मूल्य संवर्धन) मॉडल है। केवल कच्चा दूध बेचने के बजाय, इस प्लांट में दूध से पनीर, मक्खन, घी, आईसक्रीम और अन्य दुग्ध उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। बाजार में इन प्रसंस्कृत उत्पादों की मांग अधिक होती है, जिससे मुनाफा भी अधिक मिलता है। इसका सीधा लाभ अंततः उन किसानों को होगा जो दूध आपूर्ति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जोर देकर कहा कि यह संयंत्र स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करेगा। प्लांट के संचालन, प्रबंधन, वितरण और विपणन (मार्केटिंग) में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी, बल्कि उनके जीवन-स्तर में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनाना है। यह प्लांट स्थानीय स्तर पर एक ऐसी औद्योगिक चेन विकसित करेगा, जो अन्य सहायक उद्योगों (जैसे पैकेजिंग, परिवहन, कोल्ड स्टोरेज) को भी गति प्रदान करेगी। वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार दूध पर समर्थन मूल्य देने वाली देश की पहली सरकार है। इस दिशा में सरकार ने गाय के दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध के लिए 71 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। यह पहल पशुपालकों को बड़ी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसके साथ ही, प्रदेश सरकार 'प्राकृतिक खेती' को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रणनीति पर काम कर रही है ताकि उपभोक्ताओं को रसायनिक-मुक्त (केमिकल-फ्री) उत्पाद उपलब्ध करवाए जा सकें। सरकार ने प्राकृतिक रूप से उत्पादित फसलों के समर्थन मूल्य में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की इन पहलों का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है। जब किसान को अपनी फसल का उचित दाम मिलता है, तो वह आर्थिक रूप से सशक्त होता है और खेती की ओर अधिक प्रेरित होता है। ढगवार मिल्क प्लांट और फसलों पर बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य, राज्य सरकार के उस संकल्प का हिस्सा है, जिसके तहत वह हिमाचल को कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का प्रयास कर रही है। यह नीतियां न केवल किसानों की आर्थिकी को संबल प्रदान करेंगी, बल्कि प्रदेश के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

देश की बाह्य सुरक्षा के साथ आंतरिक सुरक्षा भी आवश्यक : डॉक्टर कृष्ण गोपाल

आंतरिक चुनौतियों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता

एजेंसी (हि.स.)
हमीरपुर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष की विचार यात्रा के उपलक्ष्य में हमीरपुर जिला के पूर्व सैन्य अधिकारियों की एक संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमीरपुर जिला के संघ चालक किशोर शर्मा ने की।

इस अवसर पर अपना वक्तव्य रखते हुए डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि जिस प्रकार देश की बाह्य सीमाओं पर सेना की मौजूदगी देशवासियों को सुरक्षा प्रदान करती है, उसी प्रकार देश के भीतर अनुशासित राष्ट्रभक्ति नागरिकों की संरचना करने में संघ जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान की भारत सेना विगत 2000 वर्ष की सर्वश्रेष्ठ सैन्य बलों में से है। विगत दो हजार वर्षों में भारतवर्ष ने कई प्रकार के आक्रमणों का सामना किया और उसे कालखंड के राजाओं के एकजुट ना होने के कारण समय-समय पर देश की परिस्थितियों बदलती रही। 1971 के युद्ध के पश्चात जिसमें रिकॉर्ड 93000 पाकिस्तानियों ने भारतीय सेवा के आगे घुटने टेके थे, उसके अगले 55 वर्षों में भारतीय सेवा विश्व की सबसे मजबूत सेना के रूप में उभरी है। सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पिछले 100 वर्षों की यात्रा भी कुछ इससे मिलते-जुलते कार्य के अनुरूप ही रही है, जहां सेना सीमा संभालती है और सीमा सुरक्षित होती है संघ भी देश के भीतर संगठित करने में जुटा हुआ है। संघ 1925 से देश में अनुशासित देशभक्त युवाओं के जागरण में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि 144 करोड़ देशवासियों को देश के सम्मान में एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, अपवाद के समय भले ही भारत के नागरिक इकट्ठे होते हैं यह बेहतर है परंतु यह स्थिति हर समय बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ की पूरे भारतवर्ष में 90000 से अधिक शाखाएं अपने-अपने क्षेत्र में 100 से लेकर 500 परिवारों को देशभक्त अनुशासित बनाए रखने में नित्य प्रतिदिन लगी हुई है। इस अवसर पर क्षेत्र प्रचारक प्रमुख बनवीर राणा, क्षेत्र सह व्यवस्था प्रमुख राजेंद्र शर्मा, प्रांत कार्यवाह डॉक्टर चंद्रप्रकाश सहित समाज के कई प्रबुद्ध व्यक्ति उपस्थित रहे।

राष्ट्रपति और राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर एरोस्पोर्ट्स गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

नेता विपक्ष (लोकसभा) राहुल गांधी के प्रस्तावित कांगड़ा दौरे के दृष्टिगत वीरवार को जिला कांगड़ा के कांगड़ा, धर्मशाला एवं शाहपुर उपमंडलों की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर पैराग्लाइडिंग, ड्रोन उड़ान, हॉट एयर बैलूनिंग सहित सभी प्रकार की एयरो स्पोर्ट्स एवं हवाई गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए हैं। यह निर्णय वीवीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए एहतियाती उपाय के रूप में लिया गया है।

जिला दंडाधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित दौरे के दौरान बड़ी संख्या में मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों के आगमन की संभावना है। ऐसे में किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि सुरक्षा के लिए संभावित चुनौती बन सकती है। इसी को देखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जिलादण्डाधिकारी कांगड़ा ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि जिला

पुलिस एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सुरक्षा, निगरानी तथा कानून-व्यवस्था संबंधी कार्यों के लिए ड्रोन अथवा अन्य हवाई निगरानी उपकरणों के उपयोग की छूट रहेगी, बशर्ते इसके लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा के माध्यम से जिला प्रशासन को पूर्व सूचना दी जाए। उल्लेखनीय है कि इसके अलावा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रस्तावित दौरे को ध्यान में रखते हुए भी कल वीरवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर एक बजे तक पालमपुर और बैजनाथ उपमंडलों में भी सभी प्रकार की एयरो स्पोर्ट्स एवं हवाई गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।

श्रम कानूनों और मनरेगा को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

मंडी। मंडी जिला भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला अध्यक्ष वाई.पी. कपूर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में संगठन की मजबूती के लिए नई नियुक्तियों की घोषणा करने के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों पर तीखा प्रहार किया गया। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष वाई.पी. कपूर ने संगठन की गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से नई नियुक्तियां कीं। उन्होंने सोहन सिंह ठाकुर को धर्मपुर ब्लॉक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, चेत राम (गांव मनवाणा) को मुख्य संगठन सचिव जिला मंडी और टेक चंद राणा को जिला कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। कपूर ने विश्वास जताया कि इन नियुक्तियों से जमीनी स्तर पर श्रमिकों की आवाज और बुलंद होगी। संगठन के भीतर की स्थिति स्पष्ट करते हुए वाई.पी. कपूर ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने डॉ. संजीव रेड्डी की अध्यक्षता वाली इंटक को ही वास्तविक और वैध संगठन माना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सोनिया गांधी ने भी इस निर्णय को अपनी स्वीकृति और अनुमोदन दिया है। इसके साथ ही, उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि इंटक की विधिवत मीटिंग बुलाई जाए।

भाजपा ने नए पुराने चेहरों पर खेला दांव मेयर-डिप्टी मेयर हुए दौड़ से बाहर

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

प्रदेश के दूसरे बड़े नगर निगम के चुनाव में भाजपा ने कुछ नए और पुराने चेहरों को मैदान में उतार कर बड़ा दाव खेला है। जबकि कांगेस अभी टिकट आवंटन को लेकर मत्था-पच्ची में उलझी हुई है, जबकि नामाकंन के पहले दिन ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर भाजपा ने संभावित बगावत को सर उठाने का मौका नहीं दिया है।

मंडी नगर निगम के सभी पंद्रह वार्डों में भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जिनमें अधिकांश नए चेहरे हैं तो पुराने खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है। सबसे रोचक बात यह रही है कि मंडी नगर निगम के मेयर रहे दीपाली जसवाल और वीरेंद्र भट्ट चुनावी दौड़ से बाहर हो गए हैं। दीपाली जसवाल का टिकट कट गया है। जबकि वीरेंद्र भट्ट शर्मा का वार्ड नंबर दो पुरानी मंडी महिला के लिए आरक्षित हो गया है। वहीं डिप्टी मेयर माधुरी कपूर भी

वार्ड ओपन होने की वजह से टिकट से वंचित रह गई है निगम के वार्ड नंबर एक से भाजपा ने पूर्व जिला अध्यक्ष एवं मनोनीत पार्षद रहे रणवीर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर दो से नगर परिषद की पूर्व पाषर्द सरिता हांडा को प्रत्याशी घोषित किया है। जबकि नंबर तीन पड्डल से समखेतर की पार्षद रही निर्मल वर्मा, वार्ड नंबर चार नेला से नए चेहरे के रूप में मंजू देवी को आजमाया जा रहा है। वहीं पर वार्ड नंबर पांच से मंगवाईं से भी नये चेहरे के रूप में कृष्णा ठाकुर भाजपा की प्रत्याशी होंगी। जबकि वार्ड नंबर छह सन्याहरड वीरेंद्र सिंह आर्य एक बार फिर भाजपा के प्रत्याशी होंगे। वहीं वार्ड नंबर सात तल्याहड़ से नया चेहरा जितेंद्र सिंह, वार्ड नंबर आठ पैलेस वन से पूर्व पार्षद हरदीप सिंह राजा की धर्मपत्नी गुरदीप कौर, वार्ड नंबर नौ पैलेस कालोनी-2 से पूर्व नप अध्यक्ष एवं महिला नेत्री सुमन ठाकुर पर विश्वास जताया है। उसी प्रकार वार्ड नंबर दस सुहड़ा से पूर्व पार्षद नेहा कुमारी को टिकअ दिया गया है। इसके अलावा वार्ड नंबर ग्यारह समखेतर से पूर्व नप पार्षद जितेंद्र शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है।

संक्षिप्त-समाचार

अमरनाथ यात्रा से पहले उपराज्यपाल ने की सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा

जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उपराज्यपाल ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को जम्मू के लोक भवन में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात सहित वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई यह बैठक कानून और व्यवस्था प्रबंधन और समन्वित सुरक्षा व्यवस्था पर केंद्रित रही। बैठक में जम्मू-कश्मीर में समग्र सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा की गई जिसमें वार्षिक अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि निवारक उपायों को मजबूत करने और संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी सतर्कता बनाए रखने पर जोर दिया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहज समन्वय और समय पर प्रतिक्रिया तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया है। बैठक में नशीले पदार्थों के खिलाफ तीव्र कार्रवाई और जागरूकता पहल पर ध्यान केंद्रित करते हुए नशा मुक्त समाज बनाने के प्रशासन के अभियान के तहत चल रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने क्षेत्र में मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने के लिए एक व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में नशीली दवाओं के विरोधी अभियानों और प्रवर्तन प्रयासों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की।

कठुआ पुलिस ने 17.71 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार

कठुआ। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कठुआ पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। थाना लखनपुर अधिकार क्षेत्र धनोड़ इलाके में कार्रवाई करते हुए लगभग 17.71 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) जैसी नशीली पदार्थ बरामद कर एक तस्कर को मौके पर गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार विश्वसनीय सूत्रों से मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना लखनपुर की टीम ने विशेष नाका लगाया। यह कार्रवाई एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा के नेतृत्व और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा डीएसपी डीएआर कठुआ की निगरानी में की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका जिसकी पहचान नवीन कुमार पुत्र हंस राज निवासी वार्ड नंबर 04 धनोड़ तहसील व जिला कठुआ के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से करीब 17.71 ग्राम हेरोइन जैसी नशीली पदार्थ बरामद हुई, जिसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया। आरोपी को तुरंत हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस संबंध में थाना लखनपुर में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर संख्या 40/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 8/21/22 के अंतर्गत केस दर्ज कर जांच जारी है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नशे से जुड़ी गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। इसके लिए 112 या 9858034100 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। कठुआ पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी इसी तरह सख्ती से जारी रहेगा, ताकि समाज को इस बुराई से मुक्त किया जा सके।

मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में चार दुकानें कीं ध्वस्त, अवैध संपत्तियां भी कीं जब्त

शोपियां। दक्षिण कश्मीर के शोपियन जिले में पुलिस ने बुधवार को जिला प्रशासन के समन्वय से मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाकर चार दुकानें ध्वस्त कर दीं और संदिग्ध मादक पदार्थों के अपराधियों से जुड़ी अन्य कथित अवैध संपत्तियों को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई सरकार समर्थित नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान‍ऱ के तहत की गई, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी पर अंकुश लगाना है। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान में वाची निवासी अब्दुल हामिद ने सरकारी जमीन पर निर्मित चार दुकानें ध्वस्त कर दीं, जिसका जैनापोरा पुलिस स्टेशन में 2022 में दर्ज मादक पदार्थों से संबंधित एक मामले में संबंध है। एक अन्य अभियान में अधिकारियों ने मेलहुरा निवासी एक अन्य आरोपित इनायत लोन के सरकारी जमीन पर लगाए गए चिनार के पेड़ों को काट दिया जिसका नाम उसी पुलिस स्टेशन में 2013 और 2026 में दर्ज मादक पदार्थों के मामलों में है।

मंडी नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने किया उम्मीदवारों का ऐलान

शिमला। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने मंडी नगर निगम के सभी 15 वार्डों के लिए अपने अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में वार्डवार प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। बीजेपी ने मंडी नगर निगम के 15 वार्डों के लिए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। खलियार वार्ड से रणवीर सिंह, पुरानी मंडी से सरिता हांडा, पड्डल से निर्मल वर्मा और नेला से मंजू देवी को टिकट दिया गया है। मंगवाई से कृष्णा ठाकुर, सनयारड़ (अनुसूचित जाति) से वीरेन्द्र सिंह आर्य और तल्याहड़ से जितेन्द्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह पैलेस कॉलोनी-1 से गुरदीप कौर, पैलेस कॉलोनी-2 से सुमन ठाकुर, सुहड़ा (अनुसूचित जाति महिला) से नेहा कुमारी और समखेतर से जितेन्द्र शर्मा को मैदान में उतारा गया है। भगवाहन से गगन कश्यप, थनेहड़ा से रजनी शर्मा, बैहना (अनुसूचित जाति) से गुरबचन सिंह और दोहंदी (अनुसूचित जाति महिला) से रीता देवी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया है।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का
न्वोन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा, स्व. गीता शर्मा
संस्थापक: स्व. सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

कांग्रेस सरकार आदर्श चुनाव आचार संहिता का कर रही खुला उल्लंघन : जयराम ठाकुर

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बुधवार को सराज के छतरी में देवता श्री नाग चपलांदु, पनाहार के सान्निध्य में आयोजित श्रीमद भागवत पुराण कथा में पहुंचे और कथा श्रवण किया। उन्होंने स्थानीय देवता का आशीर्वाद लेकर लोगों की समस्याएं भी सुनीं और भाजपा कार्यकताओं के साथ चुनाव को लेकर चर्चा कर उनका मार्गदर्शन किया।

जयराम ठाकुर ने प्रदेश ने आरोप लगाया है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रही है। वहीं अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने और मित्रों को संरक्षण देने में व्यस्त है। मंडी से जारी बयान में ठाकुर ने कहा कि जब पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल है और नियम प्रभावी हैं ऐसे में सरकार पर्दे के पीछे से गैर-कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रही है। जिसे भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं

करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के विभिन्न बोर्डों और निगमों में तैनात पदाधिकारी सरकारी संसाधनों और जनता के पैसे का दुरुपयोग कर चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। जो चुनाव के दौरान गलत परंपरा है। अधिकांश ऐसी एजेंसियां कांग्रेस के उन नेताओं की हैं जिन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का संरक्षण प्राप्त है। चुनाव में ये लोग बहुत सक्रिय हैं और खासकर युवाओं को रोजगार के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज का मतदाता बहुत समझदार है। कांग्रेस के झूठे वायदे और ऐसे पैंतरों से चुनाव में कोई लाभ इन्हें मिलने वाला नहीं है। सराज के छतरी दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के छुटभैया नेता तक सरकार की धौंस दिखाकर चुनाव में गलत हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि लोकतंत्र में आचार संहिता की गरिमा सर्वोपरि होती है। यदि सरकार इसी तरह 'मित्रों' को उपकृत करने के लिए संस्थानों का दुरुपयोग करती रही, तो भाजपा न केवल इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी, बल्कि जनता की अदालत में भी सरकार को बेनकाब किया जाएगा।

बारिश के कारण मुख्यमंत्री का दौरा रद्द, लोगों की उम्मीदों पर फिरा पानी

बनी। कठुआ जिले के बनी विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को प्रस्तावित मुख्यमंत्री के दौरे को भारी बारिश ने प्रभावित कर दिया, जिसके चलते कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और स्वास्थ्य मंत्री का सुबह लोहाई मल्हार में तथा इसके बाद बनी में जनसंपर्क और विकास कार्यों की समीक्षा का कार्यक्रम तय था। दौरे को लेकर प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई थीं। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर जनसभा स्थल तक हर स्तर पर इंतजाम पूरे कर लिए गए थे। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता सुबह से ही बनी में एकत्रित हो गए थे और मुख्यमंत्री के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि सुबह से ही क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश ने पूरे कार्यक्रम पर पानी फेर दिया। खराब मौसम और लगातार वर्षा के चलते मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, जिसके कारण अंततः दौरा रद्द करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम रद्द होने की खबर मिलते ही वहां मौजूद लोगों में निराशा फैल गई और उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं और क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दे रखना चाहते थे, लेकिन मौसम ने उनकी उम्मीदों को अधूरा छोड़ दिया।

लोकसभा की 543 सीटों पर महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करे केंद्र सरकार : सुरभि वर्मा

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

महिला आरक्षण के मुद्दे पर महिला कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। संगठन की प्रदेश प्रभारी सुरभि वर्मा ने बुधवार को शिमला में प्रेस वार्ता में कहा कि साल 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन बिल अब तक लागू नहीं किया गया है और सरकार इस मुद्दे पर महिलाओं को गुमराह कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में कांग्रेस ने कभी बाधा नहीं डाली, लेकिन मौजूदा सरकार इसे टाल रही है।

महिला कांग्रेस ने मांग की है कि लोकसभा की सभी 543 सीटों पर तुरंत 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए। सुरभि वर्मा ने कहा कि सरकार ने इस बिल को जनगणना और परिसीमन से जोड़कर लटका दिया है, जिससे महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने इसे महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय बताया। इस मुद्दे को लेकर महिला कांग्रेस ने बुधवार को अपने कार्यालय में ही धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संगठन का कहना है कि वे इस मुद्दे को गांव-गांव तक लेकर जाएंगे और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। इसके लिए कार्यकताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करें। सुरभि वर्मा ने यह भी कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद शिमला में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।

विकसित भारत 2047 के लिए संतुलित और सतत विकास की जरूरत: प्रो. विवेकानंद तिवारी

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला मेंविकसित भारत 2047: विकास की सनातन दृष्टिविषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में प्रो. विवेकानंद तिवारी ने कहा कि विकास को केवल भौतिक प्रगति तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उनके मुताबिक सनातन दृष्टि में विकास का अर्थ मानव और प्रकृति के बीच संतुलन और सह-अस्तित्व है, जिसमें नैतिकता और संयम को महत्वपूर्ण माना जाता है।

उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा प्रकृति को सर्वोपरि मानती है और मानव को उसका एक हिस्सा मानती है, न कि शोषण करने वाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के समय में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना जरूरी है और विकास ऐसा होना चाहिए जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चले। उनके अनुसार, यह दृष्टिकोण भोग के बजाय त्याग और संयम पर आधारित है। प्रो. तिवारी ने कहा कि विकास का उद्देश्य केवल कुछ लोगों की आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग का समग्र कल्याण होना चाहिए।

उन्होंने बताया कि भारतीय परंपरा में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की प्रगति को समान महत्व दिया गया है। इसीलिए विकास को केवल तकनीकी या औद्योगिक उन्नति के रूप में नहीं, बल्कि एक सतत और संतुलित प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान केवल एक आर्थिक या राजनीतिक शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक समृद्ध ज्ञान परंपरा के रूप में रही है। वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, योग और अर्थशास्त्र जैसी परंपराएं आज भी आधुनिक विकास मॉडल को नैतिक और समावेशी आधार प्रदान कर सकती हैं। उनके अनुसारविकसित भारत 2047का लक्ष्य भी इसी सोच को आगे बढ़ाता है, जिसमें आधुनिक ढांचे के साथ सांस्कृतिक विरासत को साथ लेकर चलने पर जोर दिया गया है।

मौसम | हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में हिमपात का सिलसिला जारी

मैदानी इलाकों में बारिश से मिली राहत, लौटी ठंड

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में मौसम के तेवर बदले हुए हैं। लगातार दूसरे दिन बादलों की सक्रियता ने जहां ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई, वहीं मध्य और निचले इलाकों में झमाझम बारिश ने अप्रैल के अंत में ठंड का अहसास लौटा दिया है। भीषण गर्मी से जूझ रहे मैदानी क्षेत्रों को राहत मिली है, लेकिन बदलते मौसम ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है।

शिमला व हमीरपुर सहित कई हिस्सों में सुबह से रुक-रुक कर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में आज ओलावृष्टि, बिजली कड़कने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, सोलन और सिरमौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया जिस

है। बीती रात कुछ क्षेत्रों में बिजली कड़कने की घटनाएं हुईं, हालांकि किसी नुकसान की सूचना नहीं है। तापमान में आई गिरावट ने मौसम को काफी सुहावना बना दिया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री, कल्पा में 6, ताबो में 6.2, सेओबाग में 10.6, मनाली में 10.9, सराहन में 11.2, सोलन में 12.7, भुंतर में 12.9, शिमला में 14.6, पालमपुर में 15, बरठीं में 15.5, जुब्बड़हट्टी में 15.8, नाहन में 16.7, मंडी में 16.7, कांगड़ा में 17.5, बिलासपुर में 18.5, ऊना व देहरा गोपीपुर में 19, धर्मशाला में 20.6 और पांवटा साहिब में 23 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि अधिकतम तापमान भी करीब 10 डिग्री तक लुढ़का है। बीते 24 घंटों में वर्षा के आंकड़े भी उल्लेखनीय रहे। सराहन में करीब 25.5 मिमी बारिश हुई, जबकि शिलारू, मनाली और कसौली में लगभग 5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा अन्य कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी ने ठंड को और बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के पूवार्नुमान के मुताबिक 30 अप्रैल से 2 मई तक मौसम खराब बना रहेगा, हालांकि इस दौरान कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। 3 और 4 मई को फिर से आंधी और बिजली को लेकर येलो अलर्ट रहेगा, जबकि 5 मई को भी बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। यानी अगले एक सप्ताह तक मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। बेमौसम बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं इसका असर कृषि पर पड़ता दिख रहा है। इन दिनों राज्य के कई हिस्सों में गेहूं की कटाई का काम चल रहा है। बारिश से कटाई प्रभावित हुई है और खेतों में पड़ी फसल के भीगने से नुकसान की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में किसानों के लिए यह राहत और चिंता दोनों का दौर बन गया है।

पीएम व सीएम के सपनों को साकार करने में लगे हैं हरियाणा की बुनियाद और सुपर-100 : ढांडा

देश में एकमात्र हरियाणा के सरकारी स्कूलों के 89 प्रतिशत विद्यार्थियों ने क्वालीफाई किया जेईई एडवांस

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा के शिक्षा विभाग की बुनियाद योजना और सुपर-100 के तहत विद्यार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सपनों को साकार करने में लगे हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने जेईई एडवांस में 89 प्रतिशत परिणाम हासिल कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसा देश में अन्य किसी भी प्रदेश के प्राइवेट और सरकारी संस्थान ने आज तक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जो अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है, उन संस्थाओं को बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा बुधवार को सरकार और विकल्प फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे हरियाणा सुपर 100 परिसर बारना में आयोजित यशोदीप सम्मान समारोह में बोल रहे थे। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जेईई एडवांस को उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विकल्प फाउंडेशन के डायरेक्टर नवीन मिश्रा ने बताया कि 235 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस को क्वालीफाई किया है। इनमें 16 ने 99 प्रतिशत से ज्यादा, 35 ने 98 प्रतिशत से ज्यादा, 57 ने 97 प्रतिशत से ज्यादा और 85 ने 95 प्रतिशत से ज्यादा अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है।

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि जिस परिसर में सुपर 100 की कक्षाएं चल रही है, यहां पर जो भी कमियों या जरुरत होंगी, उन्हें सरकार की तरफ से पूरा किया जाएगा। आज का दिन गौरव और शुभकामनाओं के साथ-साथ हरियाणा की प्रतिमा और संकल्प को नमन करने का दिन है। उन्होंने कहा कि पैसों के अभाव में बहुत परिवार अपने बच्चों को बड़े कोर्स में जाने की तैयारी तक नहीं करवा पाते थे। इस बात को हमारे केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महसूस किया और सुपर-100 जैसा स्ट्रक्चर तैयार किया। ये ढांचा सरकारी स्कूल के प्रति लोगों की सोच को बदल रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों को देश की आजादी और प्रदेश के बनने के बाद हमारे बुजुर्गों ने पैसे इकट्ठे करके अपने खून-पसीने से खड़ा किया था। उनमें से जो बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं, उनका प्रदेश सरकार की तरफ से निर्माण करवाया जा रहा है। पिछले 25-30 सालों में धीरे-धीरे सरकारी स्कूलों की हालत को शिक्षा को कम किया गया। प्रदेश में हमारी सरकार ने आते ही सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान दिया और दोबारा से पंचकूला-फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए सिफारिशें आने लगी हैं। ऐसी ही व्यवस्था आने वाले 5 सालों में प्रदेश के हर स्कूल की तैयार की जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी अपने परिवार और स्वयं को देखकर अपना लक्ष्य निर्धारित करें। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जिन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, उन्हें प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकारी पूरा करके देगी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कुशल बिजनेस कार्यक्रम चलाया है। इस योजना के हाल ही में हुए कार्यक्रम के लिए 1,23,000 विद्यार्थियों और 18000 टीचरों की टीम बनाई। इन 18000 टीमों में से प्रत्येक जिला की टॉप तीन यानी प्रदेश की कुल 66 टीमों का पंचकूला में कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसके साथ ही हिंदुस्तान में हरियाणा पहला राज्य बना, जहां की 66 टीमों पढ़ाई के साथ-साथ अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। सरकार की तरफ से इन्हें एक-एक लाख रुपया आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि विश्व में चारों तरफ देशों के बीच में आपसी झगड़े-लड़ाइयां चली हुई हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को शांति का संदेश देते हुए विकसित भारत बनाने की राह तैयार की है। युवाओं को नए आविष्कारों के साथ अपना योगदान देना है। दैनिक जीवन में प्रत्येक वस्तु लोकल फॉर वोकल प्रयोग की जानी है। आज के वर्तमान विद्यार्थी देश के आने वाला भविष्य है।

इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष तिजेंद्र सिंह गोल्डी, एसडीएम अमन कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी इंदू कौशिक, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान जितेंद्र खैरा, रिटायर्ड डीईओ कृष्णा फौगाट, प्रदीप, राजन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

आज स्व-गणना का अंतिम दिन; 1 मई से वास्तविक मकान सूचीकरण और जनगणना कार्य शुरू होंगे

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

गृह मंत्रालय के तहत जनगणना निदेशालय हरियाणा के निदेशक डॉ. ललित जैन ने हरियाणा के सभी निवासियों से अपील की है कि आज स्व-गणना ([illegible]) का अंतिम दिन है, और सभी नागरिकों को इसमें सक्रिय रूप से भाग लेकर अपनी जनगणना पूरी करवाना सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि हरियाणा में अब तक 2.45 लाख से अधिक परिवारों ने अपनी स्व-गणना पूरी कर ली है, जो एक नया रिकॉर्ड है और पूरे राज्य में जनता की मजबूत भागीदारी तथा जागरूकता को दर्शाता है। विशेष रूप से, स्व-गणना को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा गया है।

डॉ. जैन ने बताया कि स्व-गणना एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है और पोर्टल ([illegible]) पर जाकर इसे 5-7 मिनट में पूरा किया जा सकता है। इसके बाद, जनगणना करने वाले (एन्यूमरेटर) के साथ केवल वह जारी किया गया क्रमांक साझा करना होगा।

डॉ. जैन ने बताया कि पूरे राज्य में 1 मई से वास्तविक मकान सूचीकरण और जनगणना कार्य शुरू होंगे। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आने वाले सभी एन्यूमरेटरों और सुपरवाइजरों को पूरा सहयोग दें और उन्हें सही, सटीक तथा अद्यतन ([illegible]) जानकारी प्रदान करें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों द्वारा दी गई सभी जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा और किसी भी व्यक्ति या संस्था के साथ साझा नहीं किया जाएगा।

डॉ. जैन ने कहा कि जनगणना एक राष्ट्रीय दायित्व है, जिसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के विकास, नीति निर्माण और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण में योगदान देता है। उन्होंने आगे बताया कि जनगणना अधिकारियों को आवश्यक जानकारी देने से इनकार करना या उनके साथ असहयोग करना जनगणना अधिनियम के तहत एक दंडनीय अपराध है।

उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और यह सुनिश्चित करें कि उनकी जनगणना विधिवत रूप से दर्ज हो।

डॉ. जैन ने राज्य के जिला प्रशासन के अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक जिले ने जनगणना कार्यों के संचालन के लिए व्यापक और उत्कृष्ट तैयारियां की हैं, तथा अत्यंत कुशल व्यवस्थाएं लागू की हैं।

उन्होंने कहा कि एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर जनगणना प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। विभाग पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है।

यदि किसी एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर या नागरिक को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो वे अपने संबंधित सुपरवाइजर/तहसीलदार से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, जनगणना विभाग का हेल्पलाइन नंबर 1855 भी उपलब्ध कराया गया है, जिस पर कोई भी नागरिक, गणनाकार या पर्यवेक्षक अपनी समस्याओं की रिपोर्ट कर सकता है। प्रत्येक शिकायत/समस्या पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

ई-गवर्नेंस पर बढ़ेगा हरियाणा सरकार का फोकस

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

मुख्य सचिव 1 मई को करेंगे ई-ऑफिस, सीएफएमएस और एचआरएमएस की प्रगति की समीक्षा

हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी 1 मई को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में ई-गवर्नेंस से संबंधित प्रमुख प्रणालियों- ई-ऑफिस, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर), सेंट्रलाइज्ड फाइल मूवमेंट सिस्टम (सीएफएमएस) तथा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एचआरएमएस) के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा करेंगे।

बैठक के दौरान एचआरएमएस के विभिन्न मॉड्यूल्स का विभागवार प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक विभाग द्वारा अपनाए गए मॉड्यूल्स की स्थिति का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही सीएफएमएस में लंबित मामलों तथा ह्यापर्ड फाइल्सह्ण श्रेणी शुरू करने से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।

बैठक में सभी प्रशासनिक सचिवों को अपने-अपने विभागों में सभी स्तरों पर प्रभावी ढंग से ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के साथ-साथ सभी विभागों को सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए एसीआर टेम्पलेट्स को अंतिम रूप देकर उन्हें एचआरएमएस के साथ एकीकृत करने पर भी विचार किया जाएगा।

बैठक में एचआरएमएस के प्रभावी संचालन हेतु नियम-आधारित और विषय-विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध करवाने पर भी चर्चा की जाएगी ताकि तकनीकी एवं कार्यात्मक स्तर पर सतत मार्गदर्शन मिल सके।

हरियाणा सरकार ने मानसून सीजन से पहले आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज की

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सभी मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को अपने-अपने क्षेत्रों में कंट्रोल रूम सक्रिय करने के निर्देश

हरियाणा सरकार ने आगामी मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए राज्यभर में संभावित बाढ़, हीटवेव और सूखे जैसी आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कंट्रोल रूम सक्रिय करें तथा जिला एवं राज्य स्तर पर समन्वित प्रतिक्रिया प्रणाली ([illegible]) को मजबूत बनाएं।

उन्होंने बताया कि पंचकूला स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहले से ही 247 कार्यरत है। सभी जिलों को मई माह के मध्य तक विशेष बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने तथा रियल-टाइम समन्वय और रिपोर्टिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, जैसे संचार प्रणाली, इंटरनेट कनेक्टिविटी और पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। इसके अलावा, सिंचाई, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनमें बांधों की मजबूती, जल निकासी प्रणाली को सुदृढ़ करना, निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखना तथा चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा सेवाओं को तैयार रखना शामिल है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा एक विस्तृत कार्य योजना जारी की गई है, जिसमें मॉक ड्रिल का आयोजन, संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण, संभावित निकासी योजना तैयार करना तथा राहत सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। अधिकारियों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान करने, जलस्तर की निरंतर निगरानी रखने तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय संचार माध्यमों के माध्यम से समयपूर्व चेतावनी प्रणाली को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं।

सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियों पर विशेष जोर दिया गया है। त्वरित प्रतिक्रिया दल और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल इकाइयाँ की तैनाती के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। विशेष रूप से संवेदनशील ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अस्थाई आश्रय स्थल, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता एवं खाद्य आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

इसके साथ ही, बाढ़ के बाद संभावित बीमारियों की निगरानी, वेक्टर नियंत्रण तथा जलजनित संक्रमणों की रोकथाम के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। मेडिकल टीमों और आपातकालीन दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जबकि आमजन को जागरूक करने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि बाढ़ प्रबंधन के साथ-साथ राज्य सरकार ने सूखे जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी रणनीति तैयार की है, जिसमें जल संरक्षण, तालाबों का प्रभावी प्रबंधन तथा फसलों की वैकल्पिक योजना शामिल है। संबंधित विभागों को वर्षा के पैटर्न पर लगातार नजर रखने और प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने जिला प्रशासन को नियमित स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा मानसून अवधि के दौरान निरंतर निगरानी बनाए रखने को कहा है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि आगामी मानसून सीजन में जान-माल के नुकसान को न्यूनतम रखने के लिए सक्रिय योजना और विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा।

संक्षिप्त-समाचार

खादी ग्रामोद्योग संघ मिजार्पुर में पहुंचे उत्तराखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के खादी ग्रामोद्योग संघ मिजार्पुर में उत्तराखंड सरकार के ग्रामीण विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा खादी ग्रामोद्योग मंत्री भरत सिंह चौधरी के पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। उत्तराखंड सरकार के मंत्री भरत सिंह चौधरी का खादी ग्रामोद्योग संघ मिजार्पुर के मुख्य व्यवस्थापक व सचिव सतपाल सैनी ने फूल मालाओं एवं पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर स्वागत करने वालों में जुगलकिशोर, धर्मेंद्र शर्मा, विनोद कुमार, प. राजेश कौशिक, विशाल, बांका राम, रहीश, नदीम एवं अन्य खादी कर्मचारी भी मौजूद रहे। मंत्री भरत सिंह चौधरी ने खादी ग्रामोद्योग संघ इकाई का अवलोकन किया। साथ ही बिक्री केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहां की कार्यप्रणाली की सराहना की। उन्होंने खादी से ग्रामीण विकास पर जोर दिया। खादी और ग्रामोद्योग को ग्रामीण रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया। मंत्री ने कहा कि खादी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। खादी से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए बहुत से रोजगार अवसर उपलब्ध होने के साथ खादी के प्रयोग में राष्ट्रीयता का अहसास है। आज भारतीय खादी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान है। सतपाल सैनी ने मंत्री भरत सिंह चौधरी को स्मृति चिन्ह भेंट किया।

केयू यूएसएम के 21 विद्यार्थी प्रतिष्ठित आईटी कंपनी इंडिया ट्रेनर्स में चयनित

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट संस्थान के 21 विद्यार्थियों का चयन आईटी क्षेत्र की कंपनी इंडिया ट्रेनर्स में 5 लाख रुपये के आकर्षक पैकेज पर हुआ है। इस अवसर पर कुवि कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने चयनित विद्यार्थियों एवं यूएसएम के विभागाध्यक्ष, शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि एक साथ 21 विद्यार्थियों के प्रतिष्ठित आईटी कंपनी इंडिया ट्रेनर्स में चयन संस्थान के साथ-साथ विश्वविद्यालय के लिए बडे. गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की यह सफलता संस्थान के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। यह सफलता विभाग की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यावहारिक प्रशिक्षण और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए पाठ्यक्रम का भी प्रत्यक्ष परिणाम है। इस अवसर पर यूएसएम के विभागाध्यक्ष प्रो. अनिल मित्तल ने कहा कि यूएसएम हमेशा विद्यार्थियों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने पर बल देता रहा है जिसके परिणामस्वरूप एक साथ 21 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के संयोजक डॉ. विवेक कुमार ने बताया कि प्लेसमेंट सेल द्वारा समय-समय पर विभिन्न कंपनियों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है।

रोहित सरदाना मेमोरियल अवार्ड प्रतिष्ठित पत्रकार अमित पांडेय को दिया जाएगा: प्रो. सोमनाथ सचदेवा

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने बुधवार को कुलगुरु कार्यालय में रोहित सरदाना स्मृति व्याख्यान एवं रोहित सरदाना मेमोरियल अवार्ड समारोह के पोस्टर का विमोचन करते हुए कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में रोहित सरदाना की अमिट छाप रही है। उनका नाम एक प्रमुख और प्रभावशाली टीवी एंकर एवं पत्रकार के रूप में लिया जाता है। कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि रोहित सरदाना अपने करियर की शुरूआत रेडियो और छोटे चैनलों से की, लेकिन बाद में वे राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए। उनकी पत्रकारिता में उत्कृष्टता, निर्भीकता, स्पष्टता एवं न्यूज का प्रस्तुतीकरण अत्यधिक प्रभावशाली था। इसलिए भारतीय पत्रकारिता में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। इस अवसर पर कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने घोषणा करते हुए कहा कि केयू सीनेट हॉल में 30 अप्रैल 2026 कोआयोजित होने वाले रोहित सरदाना स्मृति व्याख्यान एवं अवार्ड कार्यक्रम में पहला रोहित सरदाना अवार्ड राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार एवं न्यूज 18 के एंकर अमित पांडेय को दिया जाएगा। केयू जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान व लोक सम्पर्क विभाग के निदेशक प्रो. महासिंह पूनिया ने बताया कि रोहित सरदाना अवार्ड के तहत प्रशस्ति पत्र, 21 हजार रुपये की राशि एवं अवार्ड भेंट किया जाएगा।

लोक कलाओं के संरक्षण के लिए हरियाणा कला परिषद् का विशेष अभियान

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों के लिए रचनात्मकता से भरपूर कार्यक्रमों की सौगात

हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई ऊर्जा देने की दिशा में हरियाणा कला परिषद् ने एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरूआत की है। परिषद् के निदेशक विवेक कालिया ने बताया कि परिषद् प्रदेश की लोक परंपराओं को न केवल संरक्षित करने बल्कि उन्हें नई पीढ़ी तक सजीव रूप में पहुंचाने के लिए निरंतर सक्रिय है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा की लोक कलाएं–जैसे लोक नृत्य, लोक गीत और लोक नाटक–प्रदेश की आत्मा हैं, जिन्हें समय के साथ सहेजना और आगे बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए परिषद् द्वारा एक व्यापक प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से पारंपरिक कलाओं को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। कालिया ने आगे बताया कि परिषद् की यह पहल केवल संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी बनेगी। जब बच्चे इन लोक कलाओं से जुड़ेंगे, तो वे न केवल अपनी सांस्कृतिक पहचान को समझेंगे, बल्कि उनमें रचनात्मकता और आत्मविश्वास का भी विकास होगा। इसी कड़ी में, आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बच्चों के लिए विशेष रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में चित्रकला, रंगमंच, लोक नृत्य और अन्य कलात्मक विधाओं के माध्यम से बच्चों को अपनी प्रतिभा को निखारने और मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। यह आयोजन न केवल मनोरंजन का साधन होगा, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि परिषद् द्वारा जल्द ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जहां कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। चयनित कलाकारों को प्रस्तुति हेतु अग्रिम राशि प्रदान की जाएगी, जिससे वे बेहतर तैयारी और गुणवत्ता के साथ अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। यह पहल कलाकारों के लिए प्रोत्साहन का कार्य करेगी और उन्हें आर्थिक एवं रचनात्मक सहयोग प्रदान करेगी। श्री कालिया ने विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा कला परिषद् का यह अभियान प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान दिलाने के साथ-साथ युवा प्रतिभाओं को एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। यह प्रयास हरियाणा की लोक कलाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

प्रदेश के 13 बाढ़ संभावित जिलों में 14 मई को होगा राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार 14 मई, 2026 को 13 बाढ़ संभावित जिलों में बाढ़ आपदा की स्थिति पर राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास आयोजित करेगी।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज यहां जानकारी दी कि यह अभ्यास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के समन्वय से वर्ष 2026-27 के वार्षिक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश मॉक अभ्यास कैलेंडर के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार यह मॉक अभ्यास चार चरणों में आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण 6 मई, 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'ओरिएंटेशन और समन्वय सम्मेलन' होगा, जिसमें राज्य और जिला स्तर के अधिकारी व हितधारक शामिल होंगे।

द्वितीय चरण 12 मई को 'टेबल टॉप एक्सरसाइज' होगी, जहां विभिन्न प्रतिक्रिया परिदृश्यों पर चर्चा की जाएगी और रणनीतियों का परीक्षण किया जाएगा। तृतीय चरण सबसे महत्वपूर्ण चरण, यानी 'शारीरिक मॉक ड्रिल' 14 मई को होगी, जिसमें जमीन पर सभी संबंधित एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी होगी। डॉ. मिश्रा ने बताया कि यह अभ्यास 13 चिह्नित बाढ़ प्रभावित जिलों गुरुग्राम, अंबाला, फरीदाबाद, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत, पलवल, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर में आयोजित किया जाएगा। इन जिलों का चयन नदियों और नहरों से उनकी निकटता और बाढ़ के प्रति उनकी भौगोलिक संवेदनशीलता के कारण किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य राज्य, जिला और विभागीय स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओजीएस) की समीक्षा करना है। यह 'इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम' (आईआरएस) के तहत हितधारकों की भूमिकाओं को परिभाषित करने और उन्हें समग्र प्रतिक्रिया तंत्र में एकीकृत करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि यह ड्रिल जिला स्तर के आपातकालीन सहायता कार्यों के बीच समन्वय को मजबूत करेगी और आपदा स्थितियों के दौरान संचार प्रणालियों में सुधार लाएगी।

उन्होंने कहा कि मॉक अभ्यास के माध्यम से मीडिया, स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक भागीदारी के जरिए जन जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा।

6वें एशियन बीच गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन, हरियाणा की बेटी की कप्तानी में महिला टीम ने जीता गोल्ड मेडल तो पुरुष टीम ने जीता सिल्वर मेडल

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पँवार, जो हरियाणा एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं ने चीन के सान्या में आयोजित 6वें एशियन बीच गेम्स में भारतीय कबड्डी टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रसन्नता जाहिर की है और उन्होंने जीत के लिए खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी।

उल्लेखनीय है कि प्रतियोगिता में हरियाणा की बेटी की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जबकि पुरुष टीम ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 47-31 के अंतर से पराजित कर गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं पुरुष टीम को फाइनल में ईरान के खिलाफ 44-31 से हार का सामना करना पड़ा।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि में हरियाणा की बेटियों का विशेष योगदान रहा। चरखी दादरी जिले के गांव काकड़ौली हट्टी की बेटी एवं गांव बिलावल की पुत्रवधू रितु श्योराण पुत्री सूरजभान, हिसार जिले के गांव भिवानी रोहिल्ला की मनीषा कुमारी पुत्री राजपाल तथा गांव हसनगढ़ की निकिता पुत्री अनिल ने महिला टीम में शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया। पुरुष वर्ग में सोनीपत जिले के गांव कथूरा के नीरज नरवाल ने भी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। टीम के कोच राकेश कुमार और नसीब जांघू का मार्गदर्शन भी सराहनीय रहा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा की बेटियां आज खेलों के क्षेत्र में नई पहचान बना रही हैं। उन्होंने कहा कि यह जीत केवल एक पदक नहीं, बल्कि बेटियों के आत्मविश्वास, संघर्ष और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेश की बालिकाओं से आह्वान किया कि वे खेलों में आगे आएं और देश का नाम रोशन करें।

भर्तियों में अनियमितता बरतने पर अधिकारियों के खिलाफ दर्ज करें एफआईआर: राजेश नागर

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

हरियाणा के खाद्द्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने कहा कि गांव खरींडवा डीग पैकस लिमिटेड में नियमों को ताक पर रखकर कुछ कर्मचारियों की भर्ती की गई है। इन अनियमितता की रिपोर्ट एसिस्टेंड रजिस्ट्रार कोओपरेटिव सोसायटी ने उल्लेख किया है। इन अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक को इस पूरे मामले की जांच करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। हरियाणा के खाद्द्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर बुधवार को नए लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री राजेश नागर ने कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में एजेंडे में रखी गई 13 शिकायतों में से 7 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया और लंबित 6 शिकायतों पर तुरंत जांच करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। राज्य मंत्री ने गांव यारा निवासी अमित कुमार की शिकायत पर सुनवाई की और रजिस्ट्रार सहकारी समिति के एआर का पक्ष जाना। इस हाउस के समक्ष एआर ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि खरींडवा डीग पैक्स लिमिटेड में कुछ कर्मचारियों को गलत तरीके से भर्ती किया गया है। इस मामले के दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य मंत्री ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए और पुलिस को जांच के निर्देश दिए हैं। इस जांच की रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आए उसमें रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

राज्य मंत्री राजेश नागर ने विष्णु कॉलोनी निवासी सोम प्रकाश व गगनदीप की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कहा कि मकान के कब्जे के मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसडीएम लाडवा, डीएमसी, डीएसपी और दो गैर सरकारी सदस्यों को मिलकर कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी आगामी 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट देंगी, ताकि इस रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। राज्यमंत्री ने गांव झिंवरेहड़ी निवासी सोमी, नीलम व मनजीत की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कहा कि पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी महिलाओं को रिकवरी के लिए तंग नहीं करेंगे और महिलाओं से पैसा लेकर बैंक में जमा ना करवाने वाली आरोपी महिला से रिकवरी की जाए। इस मामले में पुलिस और बैंक प्रशासन महिलाओं की हर संभव मदद करना सुनिश्चित करेंगे। राज्य मंत्री राजेश नागर ने सेक्टर-2 निवासी सरोज बाला की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कहा कि एचएसवीपी और वन विभाग के अधिकारी जल्द ही दुकान के प्लाट में आने वाले पेड़ों को कटवाना सुनिश्चित करेंगे। अगर कानून के अनुसार पेड़ नहीं कटे तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण प्रार्थी को दूसरा प्लाट देने का प्रस्ताव मुखालय भेजना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सुशांत सिटी निवासी ईश्वर सिंह द्वारा आरडब्ल्यूए की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए कहा कि डीटीपी सुशांत सिटी के अधिकारियों के साथ मिलकर कॉलोनी निवासी की समस्या का समाधान करना सुनिश्चित करेंगे। हालांकि आरडब्ल्यूए के प्रधान ईश्वर सिंह की मांग थी कि प्रशासनिक अधिकारी उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस सुशांत सिटी का लाइसेंस रद्द करना चाहिए था।

अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य ने मेहमानों का स्वागत करते हुए हाउस के एजेंडों की शिकायतों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन, भाजपा जिलाध्यक्ष तिजेंद्र सिंह गोल्डी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

राज्यमंत्री राजेश नागर ने सरपंच व अन्य नागरिकों की शिकायत पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिए कि बरसातों से पहले तंगोर गांव की तरफ जाने वाली 200 मीटर की सड़क को ऊंचा उठाकर पानी निकासी की समस्या से निजात दिलवाई जाए। इसके साथ ही पिछले 7-8 वर्षों से इसी सड़क का निर्माण ना करने के मामले में जांच की जाए। इस जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। इसी समस्या के दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष तिजेंद्र सिंह गोल्डी और कमेटी सदस्य रविंद्र सांगवान ने ठोल झांसा सड़क के निर्माण कार्य में देरी करने और घटिया सामग्री का प्रयोग करने के मामले में लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन से जवाब तलब किया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य मंत्री ने संबंधित एजेंसी को तुरंत प्रभाव से ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं एजेंसी की अर्नेस्ट मनी करीब दो करोड़ रुपए की राशि को नई सड़क का निर्माण करने में प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण किया जाए।

राज्य मंत्री राजेश नागर ने लाडवा निवासी सोनू नारंग की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग के दो इंस्पेक्टरों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में अभी तक भी प्रार्थी को संतोषजनक जवाब व न्याय नहीं मिल पाया है।

संपादकीय 594 कि.मी. की दूरी पर, मेरठ से प्रयागराज वाला 10 घंटों का सफर अब सिर्फ 6 घंटों में– गंगा एक्सप्रेसवे के जरिये मोदी ने बदल दी यू पी की तस्वीर

भारत की सभ्यता और संस्कृति की जीवनदायिनी माँ गंगा के तट पर बसा उत्तर प्रदेश आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरदोई में आयोजित एक भव्य समारोह में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर उत्तर प्रदेश को एक ऐसी सौगात दी है, जो न केवल प्रदेश की भौगोलिक दूरियों को पाटेगी, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को भी सुगम और समृद्ध बनाएगी। मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे वास्तव में विकास की एक नई धारा है जो पश्चिमी, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश को एकसूत्र में पिरोती है। यह परियोजना केवल एक सड़क नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के उस भविष्य की रूपरेखा है जिसकी कल्पना दशकों से की जाती रही थी। लगभग 36,230 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह एक्सप्रेसवे छह लेन का है और आवश्यकता पड़ने पर इसे आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। मेरठ के बिजौली से प्रयागराज तक फैला यह महामार्ग मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूँ, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज – इन बारह जिलों और उनके 519 गाँवों से होकर गुजरता है। इन जिलों में पीढ़ियों से जो विकास की प्रतीक्षा थी, उसे इस एक्सप्रेसवे के रूप में एक ठोस आधार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण के अवसर पर कहा कि जिस प्रकार माँ गंगा उत्तर प्रदेश और इस देश की जीवनदायिनी रही है, उसी प्रकार आधुनिक विकास के इस दौर में माँ गंगा के निकट से गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के विकास की नई जीवनरेखा बनेगा। यह कथन केवल एक राजनीतिक भाषण नहीं, बल्कि एक गहरी सोच का प्रतिबिंब है। गंगा जैसे ही अपने तटवर्ती क्षेत्रों को जीवन देती है, वैसे ही यह एक्सप्रेसवे अपने आस-पास के जिलों में उद्योग, व्यापार और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेगा। इस परियोजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरठ से प्रयागराज के बीच की यात्रा में लगने वाले समय में भारी कमी आना। जो दूरी पहले 10 से 12 घंटे में तय होती थी, वह अब मात्र छह से आठ घंटे में पूरी हो सकेगी। एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। समय की यह बचत केवल यात्रियों की सुविधा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे माल-परिवहन भी सुगम और तीव्र होगा, जिसका सीधा लाभ व्यापारियों, उद्योगपतियों और किसानों को मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे को एक बहुआयामी परियोजना के रूप में तैयार किया गया है। शाहजहाँपुर जिले में 3.5 किलोमीटर लंबी एक आपातकालीन एयरस्ट्रिप का निर्माण किया गया है, जहाँ भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान आपात स्थिति में उतर सकते हैं। यह सुविधा इस एक्सप्रेसवे को एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति बनाती है। यह न केवल नागरिक आवागमन के लिए उपयोगी है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के अन्य एक्सप्रेसवे पर ऐसे सफल अभ्यास किए जा चुके हैं। हापुड़ के ब्रजघाट पर गंगा नदी पर एक किलोमीटर लंबा पुल और रामगंगा नदी पर 720 मीटर लंबा पुल इस एक्सप्रेसवे की अभियांत्रिकी उत्कृष्टता का प्रमाण है। इन पुलों से यात्रा करते हुए नदियों का जो मनोरम दृश्य दिखेगा, वह इस यात्रा को केवल एक परिवहन अनुभव नहीं, बल्कि एक सुखद स्मृति भी बनाएगा। आर्थिक दृष्टि से यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर है। इसके आस-पास लगभग 2,635 हेक्टेयर भूमि पर एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स गलियारों का विकास किया जाएगा। इससे नए उद्योग स्थापित होंगे, आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी और उत्पादन लागत में कमी आएगी। किसानों को शहरी बाजारों और निर्यात केंद्रों तक सीधी पहुँच मिलेगी, जिससे उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा। रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और युवाओं को प्रदेश में ही अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। यहाँ यह भी स्मरण कराना आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश आज देश के उन अग्रणी राज्यों में से है जो एक्सप्रेसवे नेटवर्क के मामले में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और अब गंगा एक्सप्रेसवे – ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश को एक ऐसे आधुनिक प्रदेश के रूप में स्थापित कर रहे हैं जो अपने विशाल जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार के बावजूद कनेक्टिविटी के मामले में किसी से पीछे नहीं। हालाँकि, किसी भी बड़ी परियोजना की सफलता केवल उसके उद्घाटन से ही नहीं मापी जाती। यह एक्सप्रेसवे तभी अपने वास्तविक उद्देश्य में सफल होगा जब इस पर यात्री सुविधाएँ, महिलाओं की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम, साफ शौचालय, उचित प्रकाश व्यवस्था और नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। विस्थापित ग्रामीणों के उचित पुनर्वास और मुआवजे का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक्सप्रेसवे का निर्माण। जब विकास की परिभाषा में हर वर्ग और हर क्षेत्र की भलाई शामिल हो, तभी वह टिकाऊ और समावेशी कहलाता है। कुल मिलाकर, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। जिस प्रकार माँ गंगा सदियों से इस धरती को जीवन, आस्था और समृद्धि प्रदान करती आई है, उसी प्रकार यह एक्सप्रेसवे आने वाले दशकों तक करोड़ों लोगों की उन्नति और सुविधा का माध्यम बनेगा। यह परियोजना इस बात का प्रमाण है कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो और प्रशासनिक दृढ़ता हो, तो भारत के किसी भी कोने को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क नहीं है – यह नए भारत की उस सोच का प्रतीक है जो कनेक्टिविटी को ही विकास की आत्मा मानती है।

भगवान श्री नृसिंह प्राकट्योत्सव; अहंकार की पृष्ठभूमि पर लिखी गई सर्वनाश की परिभाषा

डॉ. उमेश चन्द्र शर्मा (हि.स)

भगवान के ही सेवक अहंकार के वशीभूत होकर जब अनाधिकार चेष्टा एवं अमर्यादित आचरण करते हुए, सिद्ध महात्माओं को अपमानित करने लगते हैं और प्रभु दर्शन में बाधक बन जाते हैं, तब भगवान श्री हरि दंडस्वरूप उन्हें शापित करवाकर और उनकी अहंकार मूलक मनोवृत्ति का नाश कर उनके अंतःकरण को निर्मल स्वरूप प्रदान करते हैं किंतु भगवान द्वारा किए गए ऐसे दंड विधान के मूल में भी उनकी कृपा ही छिपी होती है, जिसे प्राप्त कर जीव कृतकृत्य हो जाता है।

स्वयं प्रकाश परमात्मा जिनके पावन नामों का उच्चारण करने वाला पुरुष सनातन मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है, वे ही पुराण पुरुषोत्तम भगवान सम्पूर्ण विश्व के आत्मा, विश्व स्वरूप और सबके स्वामी हैं, वे अपने प्रेमी भक्तों को आत्मा का दिव्य आनंद प्रदान करने एवं दूषित वृत्तियों के विनाश हेतु कभी श्रीराम, श्रीकृष्ण और कभी नृसिंह रुप में इस धरा धाम पर प्रकट होकर जहां अपने निजजनों को प्रेमानंद प्रदान करते हैं, वहीं पाशविक वृत्तियों का नाश कर धर्म राज्य की स्थापना करते हुए जनमानस को निर्भयता प्रदान करते हैं।

दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने ब्रह्माजी से दुर्लभ वरदान प्राप्त कर सप्त द्वीपों के अखंड राज्य सहित इन्द्रासन पर अधिकार प्राप्त कर लिया तथा समस्त लोकों को जीतकर वह दिग्विजयी दैत्यराज सबका एकछत्र सम्राट बनकर स्वच्छंदता पूर्वक विषयों का भोग करते हुए और स्वयं को ईश्वर घोषित कर धर्म पथिकों पर अत्याचार करने लगा, परिणामस्वरूप उसकी आतंकपूर्ण, निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी वृत्तियों से मृत्युलोक सहित अन्य सभी लोक भयाक्रांत हो गए और सब तरफ हाहाकार मचने लगा किंतु जब अपनी पापमयी कुत्सित वृत्तियों से वह देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु और धर्म को अपमानित तथा भगवान से द्वेष करने लगा, तब वरदान जनित शक्ति से संपन्न उस आतंकवादी योद्धा का भगवान नृसिंह द्वारा वध कर दिया गया।

दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के अत्याचार, आतंक और स्वेच्छाचारिता के मूल में अहंकार वश की गई अनाधिकार चेष्टा के साथ ही सेवक धर्म की अवहेलना से उपजा यथार्थ भी था, जिसके परिणामस्वरूप प्रभु प्रेरित होकर सनकादि मुनियों ने प्रभु के दो सेवकों जय और विजय को दैत्य कुल में जन्म लेने का श्राप दिया था। सनकादिकों से शापित जय विजय ही दैत्यों के कुल में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्में और दैत्य समुदाय से मसीहा के रूप में सम्मानित हो गए किंतु उनकी अहंकारी वृत्ति ने अंततः उन्हें पराभव की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। दैत्याधिपति हिरण्यकशिपु विकट तपोसाधना के बल पर भगवान ब्रह्माजी से दुर्लभ वरदान प्राप्त करने में तो सफल हुआ किंतु वह वरदान लोक हितार्थ नहीं होकर अपने अहंकार की परिपुष्टि करने वाले थे इसलिए वे अंततः उसके विनाश का ही कारण बने।

भगवान कभी किसी को मारते नहीं बल्कि उसके लोक निंदित कर्मों के लिए उचित दंड विधान सुनिश्चित कर उसे स्वधर्म पालन की ओर अग्रसर करते हैं, वे अपने निज जनों को भी उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए उन्हें क्षमा नहीं करते हैं बल्कि दंड के माध्यम से उन्हें अपनी भूल का एहसास कराते हुए उनकी दोषपूर्ण वृत्तियों का नाश कर उनके हृदय को निर्मल स्वरूप प्रदान करते हैं। इस तरह भगवान के ऐसे दंड विधान में भी उनके निजजनों का सर्वतोमुखी हित ही समाहित होता है। यही कारण था कि भगवान श्री विष्णु के सेवकों जय और विजय द्वारा जब सनकादि मुनियों के प्रति उद्दंडतापूर्वक एवं अमर्यादित व्यवहार किया गया तो उन्हें उन महात्माओं द्वारा ही शापित कराकर वैकुंठ लोक से निष्कासित किया गया। जय विजय का हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के दैत्य कुल में जन्म ग्रहण करना तथा उनके द्वारा निंदनीय कर्मों के बाद नियत समय में उनकी वैकुंठ वापसी प्रभु कृपा की अप्रतिम मिसाल है। भगवान विष्णु के इस अवतार के मूल में केवल प्रह्लाद की रक्षा ही नहीं थी बल्कि उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति, प्रभु के प्रति सर्वस्व समर्पण और अटूट आस्था भी थी, जिसके वशीभूत होकर भगवान श्री हरि विष्णु को अवतार लेने हेतु बाध्य होना पड़ा।

भगवान नृसिंह के प्राकट्य होने और हिरण्यकशिपु के पराभव ने इस बात को रेखांकित किया है कि सत्ता के अहंकार में लिप्त होकर लोकजीवन को आतंकित एवं भयाक्रांत करने वाले निरंकुश, अत्याचारी और दुष्ट शासक का अंत सुनिश्चित है।

ब्रह्मा के वरदान से आत्ममुग्ध हुआ महाबली हिरण्यकशिपु भयाक्रांत कर देने वाले अपने शासन में आतंक, अत्याचार और उत्पीड़न की नित नई परिभाषाएं लिखने लगा, परिणामस्वरूप उससे प्रजा दुःख, ग्लानि एवं अवसाद से भर गई और पृथ्वी सहित तीनों लोकों में हाहाकार मच गया किंतु उस वक्त उस दुष्ट के अत्याचार, धर्म की सभी सीमा रेखाओं को लांघ गए, जब अहंकार के मद में वह अपने ही भगवद् परायण पुत्र और भगवान के प्रिय भक्त प्रह्लाद को मौत के घाट उतारने हेतु उद्यत हो गया, तब भगवान श्री विष्णु खंब तोड़ कर नृसिंह रूप में प्रकट हुए और दैत्यराज हिरण्यकशिपु के अत्याचार, आतंक एवं स्वेच्छाचारिता का अंत कर धर्म राज्य की स्थापना की तथा प्रह्लाद सहित संपूर्ण लोकजीवन को अभयत्व प्रदान किया। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों में यह अवतार पौराणिक काल की ऐसी अद्भुततम घटना थी, जिसने साधना के अहंकार को नेस्तनाबूद कर दिया।

दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने तप के बल पर दिव्य शक्तियां प्राप्त कर उनके दुरुपयोग को ही अपनी सफलता माना था, किंतु जब वह दंडित किया गया तो यह मिथक स्वयंमेव खंड खंड हो गया कि साधन सिद्ध पुरुष ही परम शक्ति है, जिसे कभी कोई चुनौती नहीं दे सकता।

नृसिंह अवतार के माध्यम से भगवान श्री विष्णु ने एकतरफ जहां दैत्यराज हिरण्यकशिपु की स्वैच्छाचारिता, अमर्यादित आचरण और अत्याचारपूर्ण क्रियाकलापों पर रोक लगाई, वहीं दूसरी तरफ स्वधर्म पालन में रत अपने भक्त प्रह्लाद की रक्षा कर उन्हें अभयत्व भी प्रदान किया। यह भगवान का अपने निज जनों पर कृपा का ही एक तरीका है। वस्तुतः भगवान श्रीहरि के नृसिंह रुप में आक्रोश अवतार का उद्देश्य केवल हिरण्यकशिपु का वध नहीं था बल्कि अहंकार के व्यामोह में अपनी मयार्दाओं का हनन कर प्रजाजनों को दारुण दुःख दिए जाने और उन पर अत्याचार किए जाने वाले एक दुष्ट शासक को दंड देकर सुधारने की एक प्रक्रिया थी, साथ ही उसमें अपने भक्त की रक्षा कर उसे अभयत्व प्रदान करने का महाविधान भी समाहित था।

(लेखक हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

आज का राशिफल

मेषः आज का दिन खासतौर पर सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अनुकूल रहेगा। कार्यभार में कमी आने से आप राहत महसूस करेंगे। भविष्य को लेकर आपके मन में उत्साह बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और मधुरता देखने को मिलेगी। *(सिटी दर्पण)*

वृषभः व्यापार विस्तार में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। आप गूढ़ विषयों या रिसर्च से जुड़े कार्यों में रुचि लेंगे। जरूरी कामों को समय पर पूरा करना बेहतर रहेगा। भाई-बहनों का सहयोग आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। *(सिटी दर्पण)*

मिथुनः कार्यक्षेत्र में आज अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आलस्य के कारण आपके कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। तकनीकी और आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी है। *(सिटी दर्पण)*

कर्कः आपकी मेहनत और जिम्मेदारी निभाने के लिए आपको सराहना या पुरस्कार मिल सकता है। आलस्य छोड़कर काम पर ध्यान केंद्रित करें, सफलता निश्चित है। समस्याओं का समाधान मिलने से मानसिक शांति मिलेगी। सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ेगी। *(सिटी दर्पण)*

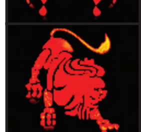
सिंहः आज आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए लोगों से संपर्क बनेंगे। पुरानी यादें आपको खुशी देंगी। परिवार के साथ समय बिताना सुकून देगा। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आर्थिक परेशानियों से राहत मिलने की संभावना है। *(सिटी दर्पण)*

कन्याः आप अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे। आय के स्रोत मजबूत होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर रहेंगे। पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिल सकती है। *(सिटी दर्पण)*

तुलाः विदेश यात्रा की योजना बन सकती है। ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर बनाए रखें। विरोधियों को हल्के में लेना नुकसानदेह हो सकता है। निजी जानकारी साझा करने में सावधानी बरतें। व्यस्त दिनचर्या के बीच स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिकः कार्यक्षेत्र में आप अपने प्रोजेक्ट्स को सफलता से पूरा करेंगे। एकाग्रता के साथ काम करने पर बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। समाज सेवा या जनहित के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। साझेदारी में नए काम की शुरूआत संभव है। *(सिटी दर्पण)*

धनुः व्यस्तता के बावजूद आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। पारिवारिक विवाद सुलझने के संकेत हैं। प्रभावशाली लोगों से आपके संबंध मजबूत होंगे। बच्चों के साथ समय बिताना आपको खुशी देगा। लंबे समय से रुकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। *(सिटी दर्पण)*

मकरः आज अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। आपकी दूरदर्शिता से व्यापार में लाभ होगा। सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी के साथ मतभेद संभव है। किसी रिश्तेदार की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें। *(सिटी दर्पण)*

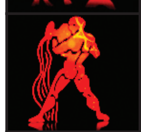
कुंभः विद्यार्थियों को अपने करियर को लेकर चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य से कमजोर रह सकता है, इसलिए सतर्क रहें। जीवनसाथी के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है। अहंकार से बचें, वरना रिश्तों में दरार आ सकती है। उच्च अधिकारियों को नाराज करने से बचें। *(सिटी दर्पण)*

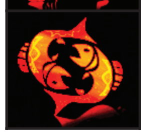
मीनः आज आप व्यापारिक समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त रहेंगे। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। जीवनसाथी के साथ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा। आपकी दिनचर्या संतुलित और व्यवस्थित रहेगी। शाम के समय स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर महसूस हो सकता है। *(सिटी दर्पण)*

नए ज़िम्मेदार ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम का निर्माण

श्री एस. कृष्णन

ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक राष्ट्रीय ढाँचा स्थापित करने की दिशा में भारत की पहल अवसर और जोखिम के संगम से उत्पन्न हुई है। बीते एक दशक में डिजिटल गेमिंग का तेजी से विस्तार हुआ है, जिसे बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन अपनाने, किफायती इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीक का उपयोग करने और उस पर निर्भर रहने वाली युवा आबादी का समर्थन मिला है। इस विकास ने नवाचार, कौशल विकास, रचनात्मक उद्योगों और रोजगार सृजन के लिए सार्थक अवसरों का सृजन किया है। मनोविनोद के लिए गेमिंग और संगठित प्रतिस्पर्धी प्रारूपों ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता भी प्रदर्शित की है।

इन अवसरों के साथ-साथ, ऑनलाइन मनी गेमिंग–विशेष रूप से सट्टेबाजी और दांव लगाने वाले (यानी बेटिंग वेजरिंग) प्लेटफॉर्मों के अनियंत्रित विस्तार ने गंभीर सामाजिक और आर्थिक चिंताओं को भी जन्म दिया। ऐसे अनेक सेवा प्रदाता राज्य सीमाओं के पार या विदेशी क्षेत्रों से संचालित होते थे, जो घरेलू सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज करते थे और कानूनों को लागू करना कठिन बनाते थे। दबाव बनाने वाले विज्ञापनों और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करने वाले डिजाइन फीचर्स ने कमजोर उपयोगकर्ताओं में लत जैसी प्रवृत्तियों और वित्तीय नुकसान को बढ़ावा दिया। वित्तीय संकट, डिजिटल भुगतान प्रणालियों के दुरुपयोग और अस्पष्ट अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन की रिपोर्ट्स ने धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अस्थिरता से जुड़े जोखिमों को उजागर किया। इन परिस्थितियों ने एक ऐसे राष्ट्रीय ढाँचे की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो व्यक्तियों–विशेषकर युवाओं–की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए गेमिंग इकोसिस्टम के वैध हिस्सों को जिम्मेदारी से विकसित होने में सक्षम बनाए।

ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स नामक संगठित प्रतिस्पर्धी प्रारूपों जैसे वैध गेमिंग क्षेत्रों की सहायता के लिए एकीकृत संस्थागत ढाँचे का अभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण था। डेवलपर्स के पास श्रेणीकरण की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी, जिसका पहले से अनुमान लगाया जा सके और उपयोगकर्ताओं को अक्सर वैध मनोरंजन और अवैध सट्टेबाजी के बीच फर्क समझने में कठिनाई होती थी। अतः इसका उद्देश्य केवल हानिकारक गतिविधियों पर रोक लगाना नहीं, बल्कि एक संतुलित ढाँचा भी स्थापित करना था, जो उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे और जिम्मेदार नवाचार को भी संभव बनाए।

ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025, (पीआरओजीए) इसी संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसे डेवलपर्स, ई-स्पोर्ट्स संगठनों, कानूनी विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी पेशेवरों और सामाजिक संगठनों के हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है। प्राप्त प्रतिक्रियाओं में लगातार पारदर्शी श्रेणीकरण, पूर्वानुमेय अनुपालन दायित्वों और वैध प्रारूपों के लिए व्यवस्थित व सरल मान्यता प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर जोर दिया गया। हितधारकों ने अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई मजबूत करते हुए वैध मनोरंजक और प्रतिस्पर्धी गेमिंग को बढ़ावा देने का समर्थन किया।

संचालन स्तर पर, यह ढाँचा परस्पर संबद्ध तीन चरणों–अवधारण, मान्यता और पंजीकरण–पर आधारित एक व्यवस्थित श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये चरण क्रमिक रूप से कार्य करते हैं और इन्हें पीआरओजीए तथा उसके नियमों में दी गई वैधानिक परिभाषाओं के साथ समझना आवश्यक है।

अवधारण एक नियामक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से किसी भी गेम की जांच और उसका श्रेणीकरण किया जाता है। यह प्रत्येक ऑनलाइन गेम के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि केवल सीमित और निर्धारित परिस्थितियों में ही आवश्यक होता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ई-स्पोर्ट्स की मान्यता से पहले अवधारण अनिवार्य होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिस्पर्धी प्रारूप वैधानिक सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं और सट्टेबाजी के तत्वों से मुक्त रहते हैं। इसके अलावा, अवधारण आमतौर पर उन स्थितियों में आवश्यक होता है, जब किसी गेम के ऑनलाइन मनी गेमिंग की परिभाषा के दायरे में आने की आशंका हो, जब अधिसूचित ऑनलाइन सोशल गेम्स की श्रेणियों के लिए श्रेणीकरण जरूरी हो, जब शिकायतों या खुफिया सूचनाओं से प्रतिबंधित गतिविधियों को सक्षम करने वाले संभावित वित्तीय तत्वों का संकेत मिले, या जब भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण (ओजीएआई) जनहित में जांच का निर्देश दे। अवधारण प्रारंभिक श्रेणीकरण को संभव बनाकर, अवैध वित्तीय मॉडलों को गेमिंग इकोसिस्टम में प्रवेश करने से रोकता है, जबकि वैध प्रारूपों को नियामक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है।

अवधारण के बाद, पात्र प्रारूपों को मान्यता दी जा सकती है। ई-स्पोर्ट्स की मान्यता राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के अंतर्गत विनियमित होती है, जिसमें संगठित मल्टीप्लेयर गेमप्ले, पूर्व-निर्धारित प्रतिस्पर्धात्मक नियम और परिणाम केवल मानसिक कौशल, शारीरिक दक्षता या रणनीतिक निर्णय लेने जैसे कारकों पर आधारित होना आवश्यक है। प्रतिभागिता शुल्क की अनुमति केवल प्रतियोगिता से संबंधित प्रशासनिक खर्चों और प्रदर्शन-आधारित पुरस्कार संरचनाओं को समर्थन देने के लिए ही दी जा सकती है। हालांकि, किसी भी रूप में सट्टेबाजी या दांव लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है। मान्यता से पहले अनिवार्य अवधारण यह सुनिश्चित करता है कि मान्यता प्राप्त ई-स्पोर्ट्स प्रारूप सभी वैधानिक सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं।

इसके समानांतर, यह ढाँचा ऑनलाइन सोशल गेम्स के पंजीकरण के लिए एक मार्ग स्थापित करता है, जो वित्तीय सट्टेबाजी के लिए नहीं, बल्कि मुख्यतः मनोरंजन और सामाजिक सहभागिता के उद्देश्य से बनाए गए होते हैं। ऑनलाइन सोशल गेम्स की केवल उन्हीं श्रेणियों का ही पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी, जिन्हें सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किया गया हो। जहाँ श्रेणीकरण की निश्चितता होना आवश्यक है, वहाँ पंजीकरण से पहले अवधारण किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें सट्टेबाजी के तत्व मौजूद नहीं हैं।

इस श्रृंखला का अंतिम चरण पंजीकरण है, जो नियामक दृश्यता प्रदान करता है तथा संतुलित निगरानी और लागू की जा सकने वाली जवाबदेही सुनिश्चित करता है। पंजीकरण आमतौर पर ई-स्पोर्ट्स की मान्यता के बाद होता है या फिर ऑनलाइन सोशल गेम्स की अधिसूचित श्रेणियों पर लागू होता है। यह उन मामलों में भी निर्देशित किया जा सकता है, जहाँ निर्धारण के परिणाम औपचारिक निगरानी की आवश्यकता दर्शाते हैं या जहाँ ओजीएआई जनहित में ऐसी निगरानी को आवश्यक समझता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजीकरण पूरे प्लेटफॉर्म पर नहीं, बल्कि प्रत्येक ऑनलाइन गेम सेवा प्रदाता के अलग-अलग खेलों पर लागू होता है, जिससे अनुपालन यथोचित बना रहता है और साथ ही प्राधिकरणों को अधिकृत खेलों का एक विश्वसनीय रिकॉर्ड बनाए रखने में सहायता मिलती है।

यह वर्तमान ढाँचा प्रतिक्रियात्मक प्रवर्तन से आगे बढ़कर सक्रिय और निवारक शासन की ओर परिवर्तन दशार्ता है। अनुकूल अवधारण प्रारंभिक फिल्टर के रूप में कार्य करता है, मान्यता वैधता का स्पष्ट फर्क स्थापित करती है, और पंजीकरण नियामक दृश्यता प्रदान करते हुए सही निगरानी और लागू की जा सकने वाली जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

साथ ही, अवैध ऑनलाइन मनी गेमिंग के खिलाफ कार्यान्वयन को, विशेष रूप से विदेशी ऑपरेटरों को लक्षित करते हुए समन्वित ब्लॉकिंग, जांच-आधारित ओजीएआई की कार्रवाई और वित्तीय व्यवधान के उपायों के माध्यम से मजबूत किया गया है। यह दो-स्तरीय दृष्टिकोण ढाँचे की मूल विचारधारा: वैध संस्थाओं के लिए हल्के फुल्के नियमन तथा अवैध संचालकों के खिलाफ सख्त कार्यान्वयन को प्रतिबिंबित करता है।

कार्यान्वयन के अलावा, यह ढाँचा जिम्मेदार इकोसिस्टम के विकास के लिए भी अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार करता है। स्पष्ट नियामक मार्ग वैध गेमिंग के विकास, प्रतिस्पर्धी अवसंरचना और सहायक डिजिटल सेवाओं में निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। ई-स्पोर्ट्स की मान्यता संगठित प्रतियोगिताओं और पेशेवर भागीदारी को सक्षम बनाती है, जबकि विनियमित श्रेणियाँ विकास, अनुपालन, साइबर सुरक्षा और इवेंट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों में सहायता देती हैं।

पीआरओजीए के माध्यम से शुरू किया गया यह परिवर्तन बिखरी हुई प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़कर पूर्वानुमेय शासन की ओर बदलाव को दशार्ता है। निवारक श्रेणीकरण, वैध मान्यता और जवाबदेह पंजीकरण को एक साथ जोड़कर यह ढाँचा एक स्थिर वातावरण तैयार करता है, जहाँ नवाचार जनहित की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जिम्मेदारी के साथ विकसित हो सकता है।

(लेखक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार में सचिव हैं।)

दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को अधिकृत करने की एक और कोशिश

मनोज कुमार मिश्र (हि.स)

केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ दिल्ली नगर निगम ने 1731 में से 1511 अनधिकृत कालोनी के करीब दस लाख परिवार को मालिकाना हक देने का फैसला किया है। दिल्ली की अधिकांश जमीन का मालिकाना हक दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पास है। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 21 अप्रैल को साझा संवाददाता सम्मेलन करके इसकी जानकारी दी।

इससे पहले 23 अक्तूबर, 2019 को तत्कालीन केन्द्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत नाम मात्र का शुल्क लेकर कुछ अपवाद को छोड़ कर सरकारी और निजी जमीन पर बनी कालोनियों को निवासियों को मालिकाना हक देकर उसे नियमित किया जाएगा। उसी की अगली कड़ी में मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। यह भी कहा कि जहां है, जैसा है -के आधार पर कालोनियां नियमित की जाएगी।

देशभर से रोजगार और बेहतर भविष्य की तलाश में दिल्ली आने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली को विकसित करने की जिम्मेदारी लेने वाली डीडीए इस काम में कब की फेल हो चुकी है। डीडीए लोगों को रहने के लिए घर देना तो दूर अपनी जमीन की हिफाजत तक नहीं कर पाई। डीडीए की हजारों एकड़ जमीन पर भू-माफिया सरकारी कर्मचारियों और नेताओं के साथ मिलकर लगातार अनधिकृत कालोनी बसा रहे हैं। पहले तो नेता ऐसे लोगों को वोट और नोट के लिए संरक्षण देते थे, अब तो अनेक माफिया चुनाव जीत कर निगम पार्षद, विधायक और सांसद बनने लगे हैं। वोट की राजनीति में कोई भी दल किसी भी अनधिकृत कालोनी को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है। आज तक इस तरह की कालोनी को बसाने वाले एक भी भू-माफिया पर कारवाई नहीं हुई है। यही हाल अवैध झुग्गियों का है।

यह नियम बन गया है कि किसी झुग्गी परिवार को बिना वैकल्पिक जगह दिए नहीं हटाया जाएगा। बावजूद इसके दिल्ली के मुख्य इलाकों से हटाकर दिल्ली की सीमा पर बसाने पर भी विवाद होता रहा है। पूर्व नौकरशाह और केन्द्र सरकार में मंत्री रहे जगमोहन को 2004 के लोकसभा चुनाव में झुग्गी हटाने को मुद्दा बना कर हरा दिया। खुद जगमोहन का कहना था कि उनके खिलाफ कांग्रेस के ही नहीं भाजपा का एक वर्ग सक्रिय था। जबकि वास्तव में झुग्गी बस्तियों को व्यवस्थित तरीके से नए स्थान पर बसाने और यमुना नदी में गंदगी जाने से रोकने का जैसा अभियान जगमोहन ने शुरू किया था, वैसा उसके बाद अभी तक दोबारा नहीं हो पाया।

करीब 365 गांव की जमीन पर 1483 वर्ग किलोमीटर की दिल्ली बसी है। 1911 में राजधानी बनने के बाद इसका आखिरी बार विस्तार 1911 में हुआ जब मेरठ जिले के यमुना पार के 65 गांव दिल्ली के इलाके में शामिल किए गए। पहली संपन्न दिल्ली आज की सिविल लाइंस और उत्तरी दिल्ली है जो पुरानी दिल्ली से लगा हुआ था। अंग्रेजों ने नई दिल्ली यानी लुटियन दिल्ली बनाई। देश के विभाजन के समय पाकिस्तान से आए विस्थापितों को आज के दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली के लाजपत नगर, राजेन्द्र नगर आदि कालोनियां में सरकार ने प्लाट देकर बसाया। उन्होंने अपने उद्यम से दक्षिणी दिल्ली को सबसे समृद्ध इलाका बना दिया। रोजगार आदि के लिए देश के दूसरे राज्यों से लोगों का आना हर रोज बढ़ता ही गया। भू-माफिया ने नेताओं, सरकारी कर्मचारियों और पुलिस से मिलीभगत करके गांवों की खाली जमीन पर अनधिकृत कालोनी और झुग्गियां बसाने का अभियान चलाया। उन्हें नोट मिले और नेताओं को नोट के साथ वोट भी मिले।

दिल्ली को विकसित करने के लिए 1957 में बनाया गया दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपनी भूमिका कभी पूरी नहीं की। उसके अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार के खेल में अव्वल भूमिका निभाते आ रहे हैं। जरूरतमंदों को उचित कीमत पर घर देने के बजाए अपनी जमीन पर अवैध कालोनी बसाने में सहयोगी बने रहे। यह कैसे संभव है कि हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया और डीडीए के अधिकारियों को इसका पता नहीं चला। पहली बार कांग्रेस ने अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए 1071 में 54 कालोनियां को नियमित किया। इसमें कांग्रेस नेता हरकिशन लाल भगत ने यमुना पार की लक्ष्मीनगर, शकरपुर आदि कालोनियों को नियमित करवाया। यही काम बाहरी दिल्ली में सज्जन कुमार ने कराए। झुग्गी वालों को जेजे कालोनी में मकान देने के अलावा मुना पार और बाहरी दिल्ली में मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, त्रिलोकपुरी, कोंडली, सीमापुरी, नंदनगरी, सीलमपुरी, गोकुलपुरी इत्यादि अनेक पुनर्वास कालोनी बसा दी। 1976-77 में आपातकाल में लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए 514 रुपए प्रति वर्गमीटर विकास शुल्क देकर 607 कालोनियों के नियमित करने की घोषणा की गई। वास्तव में 567 कालोनियां ही नियमित हो पाई और वह भी बिना विकास शुल्क के।

कांग्रेस नेता चतर सिंह कहते हैं कि 1977 में तो इन कालोनियों के निवासियों ने जनता पार्टी को वोट किया लेकिन बाद में लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे। इन्हीं नियमित और अनियमित अनधिकृत कालोनियों और पुनर्वास बस्तियों के निवासियों के बूते ही महानगर परिषद के आखिरी चुनाव में कांग्रेस जीती। उस चुनाव के बाद भाजपा नेता मदनलाल खुराना ने पहली बार इन बस्तियों में भाजपा के लिए राजनीतिक जमीन तैयार की। इसी बीच में दिल्ली को विधानसभा मिली और 1993 में विधानसभा का पहला चुनाव हुआ। चुनाव में भाजपा जीती और मदनलाल खुराना मुख्यमंत्री बने। अपने वायदे के हिसाब से एरियल सर्वे करवाकर 1071 कालोनियों को नियमित करने की विधानसभा में घोषणा की। एक तो केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी और दूसरे जैन हवाला कांड में नाम आने पर खुराना ने इस्तीफा दे दिया। फिर साहिब सिंह और आखिरी चार महीने सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री रही। बिना कालोनी नियमित किए भाजपा सरकार की 1998 में विदाई हो गई।

दिसंबर 1998 में शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस की दिल्ली में सरकार बन गई। इस बीच में कालोनियों की संख्या बढ़ गई। पहले भू-माफिया नेताओं को साथ लेकर अवैध कालोनी बसाते थे। अब तो कालोनी बसाने वालों में कई पैसे के बल पर विधानसभा पहुंच गए। एक समय ऐसा आया कि दिल्ली की कांग्रेस सरकार के शहरी विकास मंत्री डाक्टर अशोक कुमार वालिया को उनके ही दल के विधायकों ने विधानसभा में बयान नहीं देने दिया। उन्होंने सदन में बताया कि जिन 1071 कालोनी की सूची तैयार की गई है उनमें से 762 के ही ले आउट प्लान और फाइल उपलब्ध हो पाया है। बाद में यह संख्या 810 हो पाई यानी करीब ढाई सौ कालोनी का वजूद दी नहीं है। फर्जी तरीके से यह संख्या लगातार बढ़ाई जाती रही। यह बढ़कर 1639 हो गई।

2008 के चुनाव से पहले दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आधे से अधिक बसावट वाली 1218 कालोनी को नियमित करने का अस्थाई प्रमाण पत्र दिलवाए। बाद में कालोनी की संख्या पर हंगामा हो गया। एक-एक कालोनी का सर्वे किया गया तो पता चला कि 43 कालोनी का वजूद ही नहीं है और 137 कालोनी में बसावट दस फीसदी से कम है। 1018 कालोनी विवाद रहित है। 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले 895 को नियमित करने की घोषणा की गई। इसके लिए निजी जमीन पर बनी कालोनी के लिए दो सौ रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से और सरकारी जमीन पर बनी कालोनी के लिए 575 रुपए विकास शुल्क लेना तय किया गया। लेकिन कालोनी नियमित नहीं हो पाई।

अगली सरकार आम आदमी पार्टी (आप) की बनी। पहली सरकार 49 दिन चली। फिर दिल्ली में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से आआपा की सरकार बनी। इन कालोनियों और पुनर्वास बस्तियों में एकतरफा वोट आआपा को दिया। केजरीवाल सरकार ने इन कालोनियों में रजिस्ट्री शुरू करवाने का फैसला किया लेकिन वह भी कोरा वायदा ही रहा। लेकिन इनके निवासियों पर मुफ्त की रेवड़ियां (फ्री बिजली-पानी आदि) ही उनके लिए कारगर रही। उसके बाद हर चुनाव में इन कालोनी को नियमित करने का मुद्दा उठता रहा। केन्द्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार आने पर यह मुद्दा फिर से उठने लगा। 2019 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम उदय योजना के तहत इन कालोनी को नियमित करने का फैसला लिया। अब उस पर अमल हो रहा है।

शहरी योजना के जानकार और नगर निगम की निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे जगदीश ममगांई सरकार की ताजा घोषणा को छलावा से ज्यादा कुछ मामने को तैयार नहीं हैं। 2019 में तो इन कालोनियों को नियमित करने की बात कही जाती थी अब तो केवल मालिकाना हक देने की बात कही जा रही है। ज्यादातर कालोनी ग्राम सभा की खेती की जमीन पर बनी है। जमीन खरीद कर घर बनाने वाले पहले ही मालिक हैं। अगर मालिकाना हक दिलाना है तो सरकारी जमीन, वन विभाग की जमीन और रेलवे की जमीन पर बनी कालोनी के दिलवाए। सभी जमीन का मालिकाना हक पहले सरकार के पास हो फिर उसे नियमित करने के लिए अगला कदम उठाया। केवल निजी जमीन पर बनी कालोनी का मालिकाना हक मिलने से भी उस कालोनी में विधायक फंड से विकास कार्य नहीं हो सकता है। उन्हें बैंक से कर्ज नहीं मिल सकता है और न ही मकान का नक्शा पास हो सकता है। केवल लोगों को भुलावे में रखने के लिए पहले डीडीए ने आउट सोर्सिंग के माध्यम 2019 में फार्म भरवाए। लोगों में भरोसा न होने से अपेक्षित डेढ़ लाख में से चालीस हजार ने भी फार्म नहीं भरे। इस बार दिल्ली नगर निगम के माध्यम से फार्म भरवाए जा रहे हैं।

सरकार चाहे जो दावा करे लेकिन सभी अनधिकृत कालोनी को नियमित करना आसान नहीं है। जो कालोनी रेलवे, सेना या जंगल की जमीन पर हैं, उनको नियमित करना ज्यादा कठिन है। सवाल है कि पहले से बसी सभी कालोनी में सीवर कैसे डले। सामुदायिक विकास से जुड़े काम कैसे हों। पानी की लाइन सभी में कैसे डले। कैसे फायर टेंडर कालोनी तक पहुंचे। इन कामों के लिए जिसके भी घर टूटेंगे, वह विरोधी बन जाएगा और अवैध कालोनी को वैध करने वाले दल को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि इस सिलसिले पर कहीं तो रोक लगानी पड़ेगी। आज 70 फीसदी दिल्ली में अनधिकृत निर्माण है। इसे रोकने के लिए कोई तो ठोस उपाय करना होगा।

(लेखक, जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

भगवंत मान सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत घुटना प्रत्यारोपण की 4,600 सर्जरी, कैशलेस इलाज से हजारों लोगों को फिर से चलने-फिरने की क्षमता मिली

कई वर्षों के दर्द से राहत—पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत मुफ्त घुटना सर्जरी से मरीजों को नई ज़िंदगी

फाइल फोटो

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

कई लोगों के लिए चलना एक सामान्य बात है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दो कदम चलना भी रोज की जंग बन जाता है।

पंजाब में अब यह जंग धीरे-धीरे राहत में बदल रही है, क्योंकि घुटनों के दर्द से पीड़ित हजारों मरीज भगवंत मान सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत जीवन बदल देने वाली सर्जरी करवा रहे हैं। यह योजना आधुनिक इलाज को मुफ्त और व्यापक रूप से उपलब्ध बना रही है।

उम्रदराज सुखविंदर कौर के लिए यह इलाज तुरंत राहत लेकर आया। उन्होंने कहा, दो-तीन साल से मेरे घुटनों में दर्द था। कुछ दिन तो मैं चल भी नहीं पाती थी। अब सर्जरी के बाद मैं बहुत खुश हूं। स्वास्थ्य कार्ड ने मुझे मेरी ज़िंदगी वापस दे दी है। अब मैं बिना दर्द के चल सकूंगी।

67 वर्षीय परमजीत कौर के लिए कुछ समय पहले तक चलना लगभग असंभव हो गया था। एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना भी दर्दनाक था और कुछ मिनट खड़े रहना भी मुश्किल था। लगभग एक साल तक उनकी ज़िंदगी सीमित चलने-फिरने और दर्द में बीती, जिसका मुख्य कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस था।

उनकी ज़िंदगी में बदलाव तब आया जब उनके बेटे जसविंदर सिंह को सोशल मीडिया के जरिए इस योजना के बारे में पता चला। उन्होंने बताया, मुझे मुख्यमंत्री सेहत योजना के बारे में ऑनलाइन जानकारी मिली। मैंने कुछ ही दिनों में दस्तावेज तैयार किए। रजिस्ट्रेशन के बाद सर्जरी हो गई। डॉक्टर बहुत सहयोगी थे और अब मेरी माता जी काफी बेहतर महसूस कर रही हैं। आज परमजीत कौर उन हजारों लोगों में शामिल हैं, जिन्हें घुटना प्रत्यारोपण के मुफ्त इलाज के जरिए फिर से चलने-फिरने की आजादी मिली है। तीन महीनों में, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत लगभग 4,600 घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी की जा चुकी हैं। यह उन मरीजों की बढ़ती संख्या को दर्शाती है, जो पहले महंगे इलाज के कारण सर्जरी टालते रहते थे।

डॉक्टरों का कहना है कि अस्पतालों में यह बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। बरनाला सिविल अस्पताल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. करन चोपड़ा ने कहा, हम घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण के मामलों में तेजी देख रहे हैं। ज्यादातर मरीज ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित होते हैं, जो कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाता है और जकड़न व तेज दर्द पैदा करता है। उन्होंने बताया कि घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी में खराब हो चुके जोड़ को धातु और प्लास्टिक के हिस्सों से बदला जाता है, जिससे चलने-फिरने में सुधार आता है और दर्द कम होता है। उन्होंने कहा, पहले हम महीने में लगभग 80 सर्जरी करते थे, अब यह संख्या 120 से 130 तक पहुंच गई है।

इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण है–इलाज का सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना। पहले एक घुटना बदलने की लागत 50,000 से 1 लाख रुपये तक होती थी, जिसके कारण लोग वर्षों तक सर्जरी टालते रहते थे। डॉ. चोपड़ा ने कहा, पहले लोग खर्च के कारण हिचकिचाते थे। अब आधार, वोटर आईडी और स्वास्थ्य कार्ड के जरिए इलाज पूरी तरह कैशलेस है। मरीजों को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता।

ऐसी कहानियां पूरे पंजाब से सामने आ रही हैं। बठिंडा में रणधीर सिंह ने एम्स में सर्जरी करवाई, जबकि तरनतारन में राजविंदर कौर का इलाज इसी योजना के तहत जिला अस्पताल में हुआ। उनके परिवारों का कहना है कि इस आर्थिक राहत ने उन्हें बिना किसी झिझक के इलाज कराने में मदद की। राजविंदर की बेटी सहजप्रीत ने कहा, मेरी माता जी बहुत दर्द में थीं और घर का काम भी नहीं कर पाती थीं। स्वास्थ्य कार्ड की वजह से हमें खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ी। इस योजना के लिए हम सरकार के आभारी हैं।

पंजाब में जो बदलाव दिखाई दे रहा है, वह केवल सर्जरी की संख्या में बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि दर्द के प्रति सोच में बदलाव है–जहां अब खर्च के कारण इलाज टाला नहीं जाता और चलने-फिरने की आजादी अब दूर नहीं रही। अस्पतालों में अब लाचारी की आवाजों की जगह फिर से चलते कदमों की आहट सुनाई देने लगी है।

स्नेहिल मुलाकात से छत्तबीड़ चिड़ियाघर में गूंजी बच्चों की मुस्कानें

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

बच्चों की खिलखिलाती मुस्कानों और खुशियों से आज छत्तबीड़ चिड़ियाघर का माहौल रौनक से भर गया, जब सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने यहां नाजुक परिस्थितियों में रह रहे बच्चों से स्नेहपूर्ण और यादगार मुलाकात की। बच्चों ने चिड़ियाघर का दौरा करते हुए खुलकर खुशियां साझा कीं, जबकि मंत्री ने भी उनके साथ बैठकर प्यार से बातचीत करते हुए उनके दिल की बातें ध्यान से सुनीं। इस दौरान मंत्री ने बच्चों के साथ बैठकर दोपहर का भोजन भी किया, जिससे बच्चों में खुशी और अपनापन और अधिक मजबूत हुआ तथा कार्यक्रम को एक पारिवारिक माहौल मिला।

इस अवसर पर डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि प्रोजेक्ट मुस्कुराहट केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए उम्मीद की मजबूत किरण है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने माता-पिता या सहारा खो दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने सपनों से वंचित न रहे।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा, मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा कौशल विकास जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे बच्चों को एक सुरक्षित और सहयोगी वातावरण मिल सके।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार इन बच्चों के भविष्य को मजबूत आधार देने के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। बच्चों को 23 वर्ष की आयु पूरी होने पर 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर जीवन की शुरूआत कर सकें। इसके अलावा, स्कूली शिक्षा को निरंतर जारी रखने के लिए प्रति वर्ष 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता और वयस्क होने तक 4,000 रुपये प्रति माह स्पॉन्सरशिप भी दी जा रही है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का उद्देश्य तात्कालिक सहायता के साथ-साथ इन बच्चों को शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से एक मजबूत और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर अग्रसर करना है।

मंत्री ने कहा कि योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की पहचान, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तक हर चरण को सुव्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा रहा है। साथ ही निरंतर निगरानी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर बच्चे को पूरा सहयोग मिले।

उन्होंने आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के कारण 43 बच्चे अनाथ हुए और 4 बच्चे बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिन्हें योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इनमें से 42 बच्चों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता और उच्च शिक्षा के लिए सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा संपत्ति की सुरक्षा, कॉलेजों में विशेष सीटें और फीस माफी जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने नगर निगम कमिश्नरों और एडीसी (जी एवं यूडी) को मलेरिया और डेंगू की रोकथाम हेतु समय पर फॉगिंग सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली तथा स्थानीय निकायों से संबंधित कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने आज राज्यभर के सभी नगर निगम कमिश्नरों और अतिरिक्त उपायुक्तों (जनरल एवं शहरी विकास) को मलेरिया, डेंगू तथा अन्य वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर फॉगिंग अभियान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि डेंगू और मच्छरों के माध्यम से फैलने वाली अन्य बीमारियां जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं और यदि इन्हें प्रभावी ढंग से नियंत्रित न किया जाए तो कीमती जानों का नुकसान हो सकता है। जनस्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री अरोड़ा ने तत्काल फॉगिंग अभियान शुरू करने के सख्त निर्देश जारी किए और यह सुनिश्चित करने को कहा कि ये गतिविधियां नियमित रूप से जारी रहें तथा अक्टूबर तक चलने वाले पीक सीजन से पहले ही पूरी तरह लागू कर दी जाएं। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को स्थिति पर लगातार निगरानी रखने और उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र उनके कार्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि जवाबदेही और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

स्वतंत्रता संग्रामियों तथा उनके आश्रितों को 11,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है : मोहिंदर भगत

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार स्वतंत्रता संग्रामियों तथा उनके परिवारों की भलाई के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। इस संबंध में आज स्वतंत्रता संग्रामिया, रक्षा सेवाएं भलाई एवं बागबानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पंजाब के स्वतंत्रता संग्रामियों, उनकी विधवाओं, अविवाहित एवं बेरोजगार बेटियों तथा अविवाहित बेरोजगार पुत्रों को 11,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।

मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्रामियों ने देश की आजादी के लिए महान योगदान दिया है और उनकी कुर्बानियों को सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार उनके सम्मान एवं भलाई के लिए निरंतर प्रयासरत है।

श्री मोहिंदर भगत ने कहा कि पंजाब सरकार हर वर्ग की भलाई के लिए तेजी से कार्य कर रही है और स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्रामियों की देश के प्रति सेवा और त्याग युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पंजाब सरकार उनके मान-सम्मान को कायम रखने को प्राथमिकता दे रही है।

रेलवे पंजाब में माल ढुलाई गलियारे की ड्रोन निगरानी शुरू करेगा: रवणीत सिंह बिट्टू

एजेंसी
चंडीगढ़

पंजाब में पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे को निशाना बनाकर पिछले तीन महीनों में किये गये दो विस्फोटों के मद्देनजर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बुधवार को कहा कि रेलवे प्रदेश में 24 घंटे गश्त तेज करेगा और पटरियों पर निगरानी बढ़ायेगा।

बिट्टू ने शंभू और राजपुरा के बीच विस्फोट स्थल का दौरा किया एवं स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने राज्य में बार-बार रेलवे बुनियादी ढांचे को निशाना बनाये जाने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और आश्वासन दिया कि सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के लिए सख्त एवं तत्काल उपाय किए जाएंगे।

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित खालिस्तान समर्थक आतंकी मॉड्यूल (टोली) ने सोमवार देर रात पटियाला में शंभू के पास माल ढुलाई गलियारे पर विस्फोट किया।

पंजाब पुलिस ने मंगलवार को बताया कि विस्फोटकों में धमाका करने की कोशिश में एक संदिग्ध की मौत हो गई, जबकि गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया।

रेल राज्य मंत्री ने पत्रकारों को पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे (ईडीएफसी) पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि रेलवे गलियारे पर 24 घंटे गश्त तेज करेगा और निगरानी क्षेत्र का व्यापक विस्तार करेगा।

उनका कहना था कि फिलहाल अंबाला मंडल के पंजाब क्षेत्र में 173 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तथा और कैमरे लगाए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि रेलवे गलियारे के सुनसान और संवेदनशील हिस्सों पर विशेष ध्यान देगा, जहां ड्रोन निगरानी समेत उन्नत निगरानी विधियों की मदद ली जायेगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, प्रमुख रेलवे कर्मी पटरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर गश्त करेंगे। बिट्टू ने कहा, हम ड्रोन तैनात करेंगे क्योंकि लंबी दूरी तक निगरानी रखने के लिए केवल सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त नहीं होंगे। हम सौर कैमरे भी लगा रहे हैं।

मंगलवार को विस्फोट स्थल का दौरा करने वाली विशेष पुलिस महानिदेशक (रेलवे) शशि प्रभा द्विवेदी ने भी माल ढुलाई गलियारे के आसपास सीसीटीवी लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। बिट्टू ने बताया कि माल ढुलाई गलियारे पर लगभग 35 किलोमीटर की दूरी के भीतर तीन महीने के अंतराल में यह दूसरा विस्फोट है। उन्होंने कहा कि पंजाब में शांति और सद्भाव भंग करने के प्रयास में 200 से अधिक समूह सक्रिय हैं। फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद में 23 जनवरी को एक और विस्फोट हुआ था जिसमें एक ट्रेन का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया एवं एक रेलवे अधिकारी घायल हो गया। जहां पहला विस्फोट एनएच-44 से लगभग 800 मीटर की दूरी पर हुआ था, वहीं नवीनतम विस्फोट स्थल उसी राजमार्ग से लगभग 300 मीटर की दूरी पर हुआ है, जिससे अधिकारियों का यह मानना है कि शरारती तत्व संभवतः रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने के लिए राजमार्ग से आसान पहुंच मार्गों का फायदा उठा रहे हैं।

सीमावर्ती इलाकों में 585 स्थानों पर 2291 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए

पंजाब ने सीमा पार से चल रही आपराधिक सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए सुरक्षा की दूसरी कतार को किया मजबूत

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब की गैंगस्टरों के खिलाफ लड़ाई अब केवल मुठभेड़ों और गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह अब राज्य की सीमाओं तक फैल चुकी है, जहां एक शांत लेकिन बेहद रणनीतिक जंग लड़ी जा रही है।

गैंगस्टरों ते वार अभियान के तहत पंजाब पुलिस सुरक्षा की दूसरी कतार–एक गहरी, तकनीक-आधारित सुरक्षा व्यवस्था–को तेजी से मजबूत कर रही है, जिसका उद्देश्य सीमा पार से जुड़े आपराधिक नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है।

जहां सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) अंतरराष्ट्रीय सीमा की रक्षा करता है, वहीं पंजाब पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि यदि कोई तस्करी की सामग्री राज्य में प्रवेश कर भी जाए, तो वह आगे न बढ़ सके।

इस संबंध में किए गए प्रबंधों को आंकड़े भी स्पष्ट रूप से दशार्ते हैं।

सीमावर्ती पट्टी के 585 स्थानों पर 2291 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे संवेदनशील गांवों और रास्तों पर निगरानी का एक मजबूत जाल बिछाया गया है। इसके अलावा, सीमावर्ती जिलों के 41 थानों को भी सीसीटीवी कवरेज के दायरे में लाया गया है, जिन्हें निगरानी और त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार किया गया है।

लेकिन यह केवल निगरानी बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे प्रभावी बनाने की रणनीति भी है।

जमीनी स्तर पर अब अधिक सख्त और अप्रत्याशित तरीके से रियल-टाइम खुफिया जानकारी के आधार पर नाके लगाए जा रहे हैं। वाहनों की जांच अब रूटीन नहीं रही, बल्कि लक्षित और सूचना-आधारित हो गई है। विशेष रूप से उन जिलों में एंटी-ड्रोन निगरानी को तेज किया गया है, जहां ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले सामने आए हैं।

अमृतसर देहाती के एसएसपी सुहैल कासिम मीर ने कहा, सुरक्षा की दूसरी कतार वह स्थान है जहां आपराधिक श्रृंखला को तोड़ा जाता है। जहां पहली परत सीमा को सील करती है, वहीं दूसरी कतार हमारे क्षेत्र में किसी भी उल्लंघन को तुरंत रोक देती है। हमारे नाके अब साधारण चेक पोस्ट नहीं रहे, बल्कि खुफिया जानकारी के आधार पर लगाए जाते हैं और पूरी तरह सत्यापित सूचना के आधार पर स्थापित किए जाते हैं।

उन्होंने आगे कहा, गांव स्तर की रक्षा कमेटीयों और स्थानीय नेटवर्क अब सुरक्षा ढांचे का हिस्सा बन चुके हैं, जिससे जमीनी गतिविधियों पर नजर बनी रहती है। हम लगातार ढांचा, निगरानी प्रणाली, तैनाती और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत कर रहे हैं, ताकि यह परत आपराधिक गतिविधियों को रोकने और तुरंत समाप्त करने में मददगार साबित हो।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने कहा कि दूसरी परत की मजबूती राज्य की एंटी-गैंगस्टर रणनीति का केंद्र है। उन्होंने कहा, हम पुलिसिंग में गहराई ला रहे हैं। हमारा ध्यान पूरे नेटवर्क–सीमा पार से सप्लाई से लेकर अंतिम डिलीवरी तक–को तोड़ने पर केंद्रित है। सुरक्षा की दूसरी कतार यह सुनिश्चित करती है कि यदि कोई कोशिश भी की जाती है, तो उसे शुरूआती चरण में ही पहचान लिया जाए और तुरंत विफल कर दिया जाए।

पंजाब की पुलिस व्यवस्था पर नजर रखने वालों के लिए यह एक स्पष्ट बदलाव का संकेत है। यह बदलाव दशार्ता है कि अब अपराध होने के बाद कार्रवाई करने की बजाय, उसे पहले ही रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

नशीले पदार्थों और हथियारों को गिराने वाले हर ड्रोन को रोकना, हर संदिग्ध वाहन की पहचान करना और सीसीटीवी के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखना उस पूरे नेटवर्क को कमजोर करता है, जो गैंगस्टरों की सहायता करता है, जो अक्सर विदेशों से इन गतिविधियों को संचालित करते हैं।

इस पहल का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सीमावर्ती गांव अब कमजोर कड़ी नहीं रहे, बल्कि पुलिसिंग के साझेदार बन रहे हैं। स्थानीय खुफिया जानकारी को धीरे-धीरे पुलिस प्रणाली में शामिल किया जा रहा है। गांव स्तर की निगरानी और सामुदायिक नेटवर्क अब अहम सूचनाएं प्रदान कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा की दूसरी परत और मजबूत हो रही है।

यह रणनीति चरणबद्ध, सोच-समझकर बनाई गई और बेहद प्रभावी है। पहले सवाल होता था कि गोली किसने चलाई, लेकिन अब सवाल है–हथियार वहां तक पहुंचा कैसे?

गैंगस्टरों ते वार अभियान में तेजी आने के साथ, पंजाब की सुरक्षा की दूसरी कतार –एक अदृश्य दीवार, जो न केवल खतरे को रोकती है बल्कि उसके पीछे के नेटवर्क को भी समाप्त करती है–अब एक अहम मोर्चा बनकर उभर रही है।

संक्षिप्त-समाचार

एप्टस फार्मा ली. ने रेवेन्यू दोगुना किया

चंडीगढ़। बीएसइ एसएमइमें लिस्टेड एप्टस फार्मा ली. ने रेवेन्यू दोगुना किया है और 250 से ज्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाया और मल्टी-वर्टिकल विस्तार में तेजी लाई है। ग्रोथ और एग्जिक्यूशन के एक मजबूत दौर में एप्टस फार्मा ली. ने रेवेन्यू दोगुना करने और नेट प्रॉफिट में मजबूत ग्रोथ के साथ शानदार परफॉर्मेंस दी है, जो साइज और ऑपरेशनल ताकत दोनों को दिखाता है। 2010 में शुरू हुई यह कंपनी एक तेजी से बढ़ने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गई है, जो ब्रांड बिल्डिंग, प्रोडक्ट विस्तार और मार्केट में पैठ बनाने पर फोकस करती है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्रोनिक, एक्यूट और वेलनेस सेगमेंट में 250 से ज्यादा फॉमूर्लेशन तक काफी बढ़ गया है, जिसे लगातार इनोवेशन और एग्रेसिव लॉन्च का सपोर्ट मिला है। इसका बिजनेस रणनीतिक रूप से मुख्य वर्टिकल में फैला हुआ है, जिसमें प्रिस्क्रिप्शन सेगमेंट भी शामिल है, जो मजबूत डॉक्टर एंगेजमेंट के जरिए कोर रेवेन्यू बढ़ाता है; ओटीसी वर्टिकल, जो कंज्यूमर हेल्थकेयर और वेलनेस पर फोकस करता है; ग्लोबल वर्टिकल, जो एक्सपोर्ट और उससे जुड़े सर्विस रेवेन्यू से योगदान देता है; और ओर्बिट डिवीजन, एक स्केलेबल फ्रैंचाइज-लेड मॉडल, जो मार्केट में तेजी से पहुँच रहा है और कम पहुँच वाले इलाकों में पहुँच बढ़ा रहा है।

ओप्पो ने लॉन्च की सेल्फी चैंपियन एफ33 सीरीज

चंडीगढ़। भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए ओप्पो इंडिया ने आज चंडीगढ़ में नई एफ33 सीरीज लॉन्च की है। इस सीरीज में ओप्पो एफ33 प्रो 5जी और ओप्पो एफ33 5जी स्मार्टफोन शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि यह एफ-सीरीज की अब तक की सबसे नई और बेहतर सीरीज है। इसमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कैमरा, 7,000एम.ए.एच की बड़ी बैटरी, आईपी69के सुरक्षा, कलरओएस16 और 5++ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। ओप्पो एफ33 प्रो 5जी में 50मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड फ्रंट कैमरा है, जो एक साथ ज्यादा लोगों को फोटो में शामिल कर सकता है। इसमें एआई ग्रुपफी और 0.6एक्स ऑटो-स्विच फीचर है, जिससे ग्रुप सेल्फी लेना आसान हो जाता है। इसके पीछे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जो पोर्ट्रेट फोटो को बेहतर बनाता है। वहीं ओप्पो एफ33 5जी में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 50 मेगापिक्सल + 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। दोनों फोन में 6.57 इंच की अमोलेड स्क्रीन, 120 हट्र्ज. रिफ्रेश रेट और मीडियाटेक डाइमेंशन 6360 मैक्स प्रोसेसर मिलता है। 12 जीबी तक रेम और कूलिंग सिस्टम फोन को स्मूथ चलाने में मदद करते हैं। मजबूती के मामले में यह फोन आईपी69के, आईपी68 और आईपी66 सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जिससे यह पानी, धूल और गर्मी से सुरक्षित रहता है।

'बैक टू सोर्स' मोहाली ने पारंपरिक गर्मियों में ठंडक देने वाले समर कूलर्स पेश किए

मोहाली। सुरक्षा, सफाई, सामग्री की शुद्धता और खाना पकाने के स्वस्थ तरीकों के प्रति प्रतिबद्ध, 'बैक टू सोर्स' ने तेज गर्मी से निपटने के लिए गर्मियों में ठंडक देने वाले पारंपरिक भारतीय 'समर कूलर्स' और फर्मेंटेड प्रोबायोटिक ड्रिंक्स की एक खास और बेहतरीन रेंज पेश की है। इन अनोखे ड्रिंक्स को मोहाली के जुबली जंक्शन सेक्टर 66 में बीटीएस के आउटलेट पर प्रदर्शित किया गया। मीडिया के साथ जानकारी साझा करते हुए, 'बैक टू सोर्स' की फाउंडर डायरेक्टर पूजा अग्रवाल और ऑपरेशंस हेड ध्रुव अहलूवालिया ने ब्रांड के साफ-सुथरे, सोच-समझकर खाने के सिद्धांत पर रोशनी डाली, जो प्राकृतिक और समय की कसौटी पर परखी हुई पारंपरिक सामग्री पर आधारित है। पूजा अग्रवाल ने कहा कि हमने इन ड्रिंक्स को उत्तरी भारत की तेज गर्मी का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया है; ये नए पेश किए गए ड्रिंक्स हाइड्रेशन, पोषण और पाचन संबंधी फायदों का मेल हैं। इस खास और नई रेंज के मुख्य आकर्षणों में 'गोंद कतीरा एल्मोंड मिल्क कूलर', 'ज्वार बादाम मिल्क शेक' और 'पाइनएप्पल टेपाचे' शामिल हैं। पूजा ने बताया कि 'गोंद कतीरा एल्मोंड मिल्क कूलर' प्राचीन भारतीय नुस्खों से प्रेरित है, और इसमें भिगोई हुई खाने योग्य गोंद का इस्तेमाल किया गया है, जिसे ताजे बादाम दूध और प्राकृतिक मिठास के साथ मिलाकर एक ठंडक देने वाला और पौष्टिक अनुभव प्रदान किया जाता है। पूजा ने आगे कहा कि इसी तरह, 'ज्वार बादाम मिल्क शेक' में बाजरा-आधारित दूध को बादाम के साथ मिलाया गया है, ताकि बिना भारीपन महसूस कराए लगातार ऊर्जा मिलती रहे, जो इसे गर्म मौसम के लिए आदर्श बनाता है। 'पाइनएप्पल टेपाचे', जो अनानास के छिलकों से बना एक हल्का फर्मेंटेड ड्रिंक है, गर्मियों के इन अनोखे कूलर्स में एक प्राकृतिक रूप से फिजी और ताजगी भरा ग्लोबल टच जोड़ता है।

स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकताओं का योगदान सराहनीय है: डॉ. रमन गुप्ता

रूपनगर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के दिशा-निदेर्शों के तहत, सिविल सर्जन डॉ. रमन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में सिविल अस्पताल रूपनगर में 'आशा दिवस' मनाया गया।इस अवसर पर शहरी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ आशा कार्यकताओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया।इस कार्यक्रम के दौरान, डॉ. रमन कुमार गुप्ता ने 'आशा दिवस' पर आशा कार्यकताओं को बधाई दी और कहा कि आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, मातृ मृत्यु दर में कमी, माताओं और बच्चों के टीकाकरण और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने में आशा कार्यकताओं का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना कार्ड के पंजीकरण में आशा कार्यकताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉ. रुपिंदरजीत सिंह गिल ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9वीं और 23वीं तारीख को उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान करने और उनकी जांच सुनिश्चित करने में आशा कार्यकताओं की भूमिका सराहनीय है।उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग और जनता के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करती हैं और केवल उनके प्रयासों के कारण ही स्वास्थ्य सेवाएं जनता तक पहुंच पा रही हैं। इस अवसर पर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. नवरूप कौर, डॉ. हरलीन कौर, डॉ. नीरज, डॉ. गुरसेवक सिंह, जिला जनसंचार अधिकारी गुरमीत कौर, उप जनसंचार अधिकारी रितु, राकेश सिंह और एलएचवी राजिंदर कौर भी उपस्थित थे।

ब्रिटेन में ईरानी दूतावास के संदेश पर राजदूत तलब

विदेश मंत्रालय ने कहा- यह सब अस्वीकार्य व भड़काऊ

एजेंसी (हि.स.)

लंदन

ब्रिटेन स्थित ईरानी दूतावास के अपने देशवासियों के नाम सोशल मीडिया पर जारी संदेश को विदेश मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने इस संदेश को ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए राजदूत सैयद अली मूसावी को तलब किया। ब्रिटेन ने कहा कि ऐसा बयान पूरी तरह अस्वीकार्य और भड़काऊ है। यह संदेश दूतावास ने हाल ही में जारी किया है। इसमें ब्रिटेन में रह रहे ईरानियों से अपने देश के लिए जान कुर्बान करने की अपील की गई है।

ब्रिटेन के अखबार डेली मेल में इस संदेश का खुलासा होने पर कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया। ब्रिटिश सरकार ने इसे अस्वीकार्य बताया है। ईरानी दूतावास ने इसे देशभक्ति का प्रतीक बताया है। रिपोर्ट के अनुसार ईरानी दूतावास ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर यह संदेश जारी किया। संदेश में दूतावास ने ब्रिटेन में रह रहे प्रवासियों से 'खुद को कुर्बान करने' का आान किया था। ब्रिटेन की आतंकवादरोधी पुलिस ने पुष्टि की है कि वह उस सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रही है, जिसमें 'गर्वित ईरानी हमवतनों' से शहादत के कार्यक्रम में शामिल होने का आान किया गया था। दूतावास के आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर फारसी भाषा में की गई पोस्ट में लिखा गया, आइए, हम सब मिलकर, एक-एक करके, अपने शरीर को कुर्बान कर दें, क्योंकि यह अपने देश को दुश्मन के हवाले करने से कहीं बेहतर है।

इस संदेश पर कूटनीतिक चिंता बढ़ने पर मंगलवार को मध्य-पूर्व मामलों के मंत्री हैमिश फॉल्कनर ने ईरानी राजदूत सैयद अली मूसावी को विदेश मंत्रालय में तलब किया। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि यह कदम 'सोशल मीडिया पर ईरानी दूतावास की अस्वीकार्य और भड़काऊ टिप्पणियों' के जवाब में उठाया गया। इसमें कहा गया, मंत्री ने साफ कर दिया कि ये हरकतें और टिप्पणियां पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। दूतावास को किसी भी तरह का ऐसा संचार तुरंत बंद कर देना चाहिए, जिसकी व्याख्या ब्रिटेन या

फोटोः हि.स.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंसा को बढ़ावा देने के तौर पर की जा सकती हो। ब्रिटिश सरकार का यह स्पष्ट रुख है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और ब्रिटिश लोगों की सुरक्षा के लिए हम सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। उधर, ईरानी दूतावास ने इस बात पर जोर दिया है कि 'जान फिदा' या 'जान कुर्बान करने' वाला कार्यक्रम किसी भी तरह की शत्रुता को बढ़ावा नहीं देता है। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के चीफ ऑफ स्टाफ कैमरन खानसारिनया ने कहा, यह ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा है। यह एक कड़ी चेतावनी है कि ब्रिटिश धरती पर और ज्यादा आक्रामकता की साजिश रची जा रही है। इजराइल ने भी इस पोस्ट की कड़ी आलोचना की है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ईरानी शासन ब्रिटेन में अपने दूतावास का इस्तेमाल आतंकवादियों की भर्ती के लिए कर रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने पिछले सप्ताह किंग्स स्पीच के दौरान कहा था कि वह ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) को जल्द ही आतंकवादी संगठन घोषित करेंगे। अमेरिका और कनाडा पहले ही आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं।

ईरान से कथित तौर पर जुड़ा इस्लामी संगठन 'हरकत अशहाब अल-यामीन अल-इस्लामिया' पिछले हफ्ते के अंत में उत्तर-पश्चिमी लंदन के हैरो स्थित केंटन यूनाइटेड सिनेगॉग में आगजनी की घटना की जिम्मेदारी भी ले चुका है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां इस संगठन के ईरानी शासन से जुड़े होने के आरोपों की जांच कर रही हैं। लंदन स्थित ईरानी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा, दुनिया भर में बसे ईरानी लोग हमेशा से अपनी मातृभूमि और उसकी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा को लेकर बेहद संजीदा रहे हैं और वे हमेशा ऐसे ही रहेंगे।

बांग्लादेश में माफिया सरगना टिटोन की गोली मारकर हत्या

ढाका पुलिस को अंडरवर्ल्ड के गुर्गों पर शक

एजेंसी (हि.स.)

ढाका

बांग्लादेश की राजधानी ढाका के न्यू मार्केट इलाके में मंगलवार रात माफिया सरगना खोंडोकर नईम अहमद टिटोन (50) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ढाका पुलिस को शक है कि टिटोन की हत्या अंडरवर्ल्ड के सदस्यों ने की है। हजारीबाग के जिगातोला स्थित सुल्तान गंज के केयम फखरुद्दीन का बेटा टिटोन ढाका में दहशत का पर्याय रहा है। पुलिस के अनुसार टिटोन देश के 23 खूंखार अपराधियों की सूची में दूसरे स्थान पर था।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, न्यू मार्केट थाना के उप निरीक्षक मो. शहादत हुसैन ने बताया कि पुलिस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (पीआईबी) ने फिंगरप्रिंट एनालिसिस के जरिए शव की पहचान की। ढाका के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एनएन मो. नजरुल इस्लाम ने बताया कि गोली लगने के बाद टिटोन को ढाका

फोटोः हि.स.

मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि 2001 में जारी की गई 23 खूंखार अपराधियों की सूची में टिटोन का नाम भी शामिल था। उसने जेल में लंबा समय बिताया। पिछले साल 13 अगस्त को जमानत पर रिहा हुआ था। जमानत की अवधि खत्म होने के बाद से वह फरार था। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि यह हत्या अंडरवर्ल्ड के सदस्यों ने की होगी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह घटना रात करीब आठ बजे न्यू मार्केट के पीछे ढाका विश्वविद्यालय के शाहनवाज हॉल के सामने हुई। दो हमलावर एक मोटरसाइकिल पर आए और अंधाधुंध गोलियां चलाईं। जख्मी होकर टिटोन सड़क पर गिर गया। स्थानीय लोगों ने हमलावरों का पीछा भी किया पर वह हाथ नहीं आ सके। टिटोन को मेडिकल कॉलेज पहुंचाने में सहायता करने वाले मो. मेजबाह रहमान ने बताया कि हमलावरों ने टोपी और मास्क पहन रखे थे। ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित पुलिस चौकी प्रभारी इंस्पेक्टर मो. फारूक ने बताया कि शव पर कई गोलियों के निशान थे। एक गोली सिर सिर के आर-पार हो गई थी। सहायक पुलिस आयुक्त (न्यू मार्केट जोन) मो. नसीम ए गुलशन ने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया है। आसपास के इलाके से सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए हैं।

नेपाल सरकार राजदूतों की नियुक्ति खुली प्रतिस्पर्धा से करने की तैयारी में

एजेंसी (हि.स.)

काठमांडू

नेपाल सरकार ने राजदूतों की नियुक्ति खुली प्रतिस्पर्धा के माध्यम से करने की तैयारी शुरू कर दी है। विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई चर्चा में पिछले सोमवार को यह संकेत दिया था कि इस संबंध में जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। खनाल के अनुसार, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से सहमति ले ली है। अगर ऐसा होता है तो बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद यह पहला अवसर होगा, जब खुली प्रतिस्पर्धा के जरिए राजदूत नियुक्त किए जाएंगे। इससे पहले केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार ने वर्ष 2018 में राजनीतिक कोटे से नियुक्त होने वाले राजदूतों के लिए भी मापदंड तय किया था। राजदूत नियुक्ति संबंधी निर्देशिका के अनुसार, कुल रिक्त राजदूत पदों में कम से कम 50 प्रतिशत नियुक्ति विदेश सेवा और शेष

50 प्रतिशत राजनीतिक नियुक्ति के जरिए किए जाने का प्रावधान है। पिछली सरकारों ने कभी भी खुली प्रतिस्पर्धा के माध्यम से राजदूत नियुक्त नहीं किए हैं। अब तक विदेश मंत्रालय में कार्यरत करियर डिप्लोमेट्स और सत्तारूढ़ दल द्वारा चुने गए लोगों को ही राजदूत बनाया जाता रहा है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बार भी मंत्री खनाल से आग्रह किया है कि 50 प्रतिशत से अधिक राजदूत करियर डिप्लोमेट्स में से नियुक्त किए जाएं। खुली प्रतिस्पर्धा के लिए जारी होने वाले विज्ञापन में इच्छुक उम्मीदवारों की आयु, अनुभव और शैक्षिक योग्यता जैसी जानकारियां मांगे जाने की तैयारी की जा रही है।

महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली साइबर थाने में शिकायत दर्ज

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली के मंदिर मार्ग साइबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कथित फर्जी वीडियो साझा कर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अजय पाल शर्मा की छवि धूमिल करने का प्रयास किया। शिकायतकर्ता अभिषेक दुबे का दावा है कि यह वीडियो संभवतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तकनीक की मदद से तैयार किया गया। इसका उद्देश्य भ्रामक सूचना फैलाना और चुनावी माहौल को प्रभावित करना हो सकता है। दुबे ने संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटवाने का भी अनुरोध किया है। तृणमूल कांग्रेस और सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

दक्षिण लेबनान में इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह की बड़ी सुरंग नष्ट, दर्जनों आतंकी मारे गए

एजेंसी (हि.स.)

लेबनान/तेल अवीव

इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने दक्षिण लेबनान में हमला कर आतंकी समूह हिजबुल्लाह की बड़ी सुरंग को उड़ा दिया। इस हमले में दर्जनों आतंकवादी मारे गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले की पुष्टि की है। नेतन्याहू ने एक्स पर वीडियो साझा कर यह जानकारी दी।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा, आज हमने हिजबुल्लाह की एक बहुत बड़ी सुरंग को उड़ा दिया। हम उनके आतंकी ढांचे को तबाह कर रहे हैं। हमले में दर्जनों आतंकियों को मार गिराया गया है। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। आईडीएफ ने कहा कि दो किलोमीटर लंबी यह सुरंग दक्षिण लेबनान के कंतारा में डिवीजन 36 में थी। इसकी गहराई जमीन से 25 मीटर नीचे थी। इस सुरंग का निर्माण ईरान की

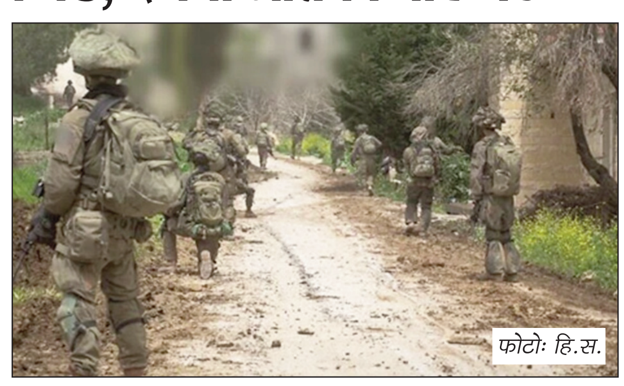

फोटोः हि.स.

मदद से हुआ था। आईडीएफ ने बताया कि मंगलवार को 450 टन विस्फोटक की मदद से इस सुरंग को नष्ट कर दिया गया है। यह सुरंग पथरीली ग्रेनाइट चट्टान में खोदी गई थी। सुरंग के अंदर 30 कमरों थे। इस सुरंग में हथियारों का बड़ा जखीरा छुपा हुआ था। इसकी रक्षा के लिए दर्जनों आतंकवादी तैनात थे। हमले में सभी आतंकी मारे गए।

टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, आईडीएफ ने बताया कि मंगलवार को हिजबुल्लाह ने दक्षिण लेबनान में तैनात इजराइली सैनिकों पर ड्रोन से हमला किया। एक दिन पहले ड्रोन हमले में एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया था। आईडीएफ के अनुसार, मंगलवार को ही दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के एक ड्रोन हमले में रक्षा मंत्रालय का सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर आमेर हुजिरात (44) मारा गया। इस हमले में ठेकेदार का बेटा भी छर्रे लगने से घायल हो गया है।

संक्षिप्त-समाचार

शुरूआती कारोबार में शेयर बाजार में तेजी का रुख, सेंसेक्स और निफ्टी उछले

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरूआती कारोबार के दौरान मजबूती का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। बुधवार के कारोबार की शुरूआत भी बढ़त के साथ हुई थी। बाजार खुलने के बाद कुछ देर तक लिवालों और बिकवालों के बीच मामूली खींचतान भी हुई, जिसके कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में मामूली उतार-चढ़ाव भी होता रहा। हालांकि पहले 20 मिनट के कारोबार के बाद ही खरीदारों ने लिवाली का जोर बना दिया, जिससे इन दोनों सूचकांकों की मजबूती लगातार बढ़ने लगी। सुबह 10 बजे तक का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी 0.76 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। बुधवार प्रातः 10 बजे तक का कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से मारुति सुजुकी, आईटीसी, आयशर मोटर्स, मैक्स हेल्थकेयर और टेक महिंद्रा के शेयर 4.14 प्रतिशत से लेकर 1.73 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 1.89 प्रतिशत से लेकर 0.75 प्रतिशत की कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। अभी तक के कारोबार में स्टॉक मार्केट में 2,617 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हो रही थी। इनमें से 1,942 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि 675 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 20 शेयर लिवाली के सपोर्ट से हरे निशान में बने हुए थे। दूसरी ओर 10 शेयर बिकवाली के दबाव में लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।

गुवाहाटी में छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम गलतफहमी के चलते हिरासत के बाद रिहा

गुवाहाटी/रायपुर। गुवाहाटी में एक मामले की जांच के लिए आई छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस की टीम को ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोपों की गलतफहमी के बाद दिसपुर पुलिस ने हिरासत में लियाा। जानकारी के अनुसार रायपुर से आई पुलिस टीम गुवाहाटी में एक डिजिटल अरेस्ट केस की जांच के सिलसिले में पहुंची थी। इस दौरान टीम पर एक व्यक्ति से मामले को निपटाने के नाम पर धन की मांग करने का आरोप लगाया गया। हालांकि, छत्तीगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद गुवाहाटी पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। बताया गया है कि 24 घंटे के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस टीम गुवाहाटी से बीते मंगलवार को रवाना हो गयी। छत्तीसगढ़ पुलिस पर आरोप लगाया गया था कि मांगी गई रकम नहीं देने तक संबंधित व्यक्ति को बंधक बनाकर रखा गया। पीड़ित की शिकायत के आधार पर दिसपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूरी टीम को हिरासत में ले लिया। हालांकि, दिसपुर पुलिस ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। दिसपुर पुलिस ने आरोपित पुलिसकर्मियों द्वारा पीड़ित से वसूली गई रकम भी बरामद करने का दावा किया। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस ने बताया है कि यह मामला रायपुर (छत्तीसगढ़) के टिकरापारा थाने में दर्ज डिजिटल अरेस्ट केस से जुड़ा है। मामले में टीआई रवींद्र यादव सहित एक एएसआई, एक हवलदार और अन्य पुलिसकर्मी गुवाहाटी गए थे। आरोप है कि रायपुर पुलिस ने पैसे लेकर आरोपितों को छोड़ दिया। असम पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस टीम पर गंभीर आरोप लगाए। गुवाहाटी पुलिस का दावा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक आरोपित को पकड़ने के बाद दो अन्य आरोपितों को कथित तौर पर पैसे लेकर छोड़ दिया। इसी आरोप में गुवाहाटी पुलिस ने चारों पुलिसकर्मियों को हिरासत में ले लिया। रायपुर के पुलिस उपायुक्त संदीप पटेल ने आज बताया है कि टीम गुवाहटी में आरोपितों को गिरफ्तार करने गई थी। टीम ने आरोपितों को हिरासत में लेकर उनसे ठगी गई रकम की रिकवरी शुरू की थी। रिकवरी रकम को घूस बताकर आरोपितों के रिश्तेदारों और मोहल्लेवालों ने पुलिसकर्मियों को घेरा और गुवाहटी पुलिस को सूचना दी।

ट्रक से टकराई कार, एक की मौत, छह घायल

मोरीगांव (असम)। मोरीगांव जिले के जागीरोड इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर हुए एक सड़क हादसे में कार में सवार एक युवक की मौत हो गयी। कार में कुल सात व्यक्ति सवार थे। घायलों अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि बुधवार राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर फ्लाईओवर के सामने एक सड़क दुर्घटना हुई। सड़क किनारे एक ट्रक खराब होने के कारण खड़ा था। इसी बीच, नगांव की तरफ से गुवाहाटी की तरफ आ रही एक स्वीफ्ट डिजायर कार ने खराब ट्रक के पिछले हिस्से में टक्कर मार दी। जिसके परिणामस्वरूप, कार में सवार सात यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक व्यक्ति की मौत हो गयी। घायलों की पहचान अशादुल अली नगांव, रसीदुल इस्लाम नगांव, जाबेद अली बरपेटा, इनामुल हक नगांव, रसीदुल इस्लाम नगांव, अशिकुल इस्लाम नगांव एवं एक अज्ञात व्यक्ति (जो बेहोश था और कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं था) के रूप में की गयी है। घायल व्यक्तियों को तुरंत इलाज के लिए नाखोला एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने एक व्यक्ति अशिकुल इस्लाम को मृत घोषित कर दिया।

तिलक के बाद प्रेमिका की धमकी, शादी करो वरना जान दे दूंगी

सीवान। सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के छेनी छापर गांव में बुधवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब पंजाब के लुधियाना से पहुंची एक युवती ने अपने प्रेमी के घर पर जमकर हंगामा कर शादी की तैयारी ठप करा दी। मिली जानकारी के अनुसार, लुधियाना निवासी अंजलि जायसवाल और छेनी छापर के अजीत कुमार दुबे के बीच पिछले एक साल से प्रेम संबंध चल रहा था। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन मौका मिलते ही वह चुपके से गांव लौट आया और दूसरी लड़की से शादी रचाने की तैयारी में जुट गया। मंगलवार की रात युवक का तिलक भी चढ़ गया, लेकिन इसकी भनक लगते ही प्रेमिका ने रातों-रात ट्रेन पकड़ ली और बुधवार सुबह सीधे प्रेमी के दरवाजे पर पहुंचकर बखेड़ा खड़ा कर दिया। सूचना मिलते ही मैरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सामने लाने की कोशिश की, लेकिन हंगामे के बीच परिजन उसे लेकर फरार हो गए। मौके पर भारी भीड़ जुट गई और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। हंगामे के दौरान युवती के साथ कथित तौर पर मारपीट भी की गई, जिससे आक्रोशित होकर उसने पास के कुएं में कूदकर जान देने की कोशिश की। हालांकि, स्थानीय लोगों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। प्रेमिका का साफ कहना है कि उसने शादी का झांसा देकर मेरे साथ सब कुछ किया, अब उसे मुझसे शादी करनी ही होगी, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के बीच मुठभेड़, ऑपरेशन जारी, जवान सतर्क

एजेंसी (हि.स.)

पश्चिमी सिंहभूम

पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो-गोइलकेरा थाना क्षेत्र के घने जंगलों में बुधवार को सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसकी आधिकारिक पुष्टि एसपी अमित रेनू ने की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार, रूटुगुटू जंगल में यह मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब कोबरा 209 बटालियन और अन्य सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन चला रही थी। यह अभियान कुख्यात माओवादी और एक करोड़ रुपये के इनामी कमांडर मिसिर बेसरा की तलाश में चलाया जा रहा था।

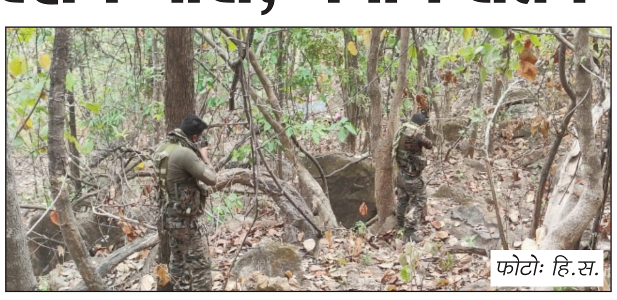

फोटोः हि.स.

सूत्रों की मानें तो पिछले दो दिनों से सुरक्षा बल गोइलकेरा थाना क्षेत्र के बोरोई और तूनबेड़ा गांवों के आसपास सघन कॉम्बिंग अभियान चला रहे थे। इसी दौरान जवानों की गतिविधियों पर नजर रख रहे माओवादी रूटुगुटू के जंगलों में सामने आ गए, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक, मुठभेड़ रुक-रुक कर जारी रही और खबर लिखे जाने तक फायरिंग फिलहाल थम गई थी। हालांकि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है और इलाके में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। एसपी अमित रेनू ने कहा कि सुरक्षा बल पूरी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं और ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य शीर्ष माओवादी नेताओं को पकड़ना या निष्क्रिय करना है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर आसपास के गांवों में सतर्कता बढ़ा दी गई है और ग्रामीणों को जंगलों की ओर न जाने की सलाह दी गई है। नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

पारिवारिक विवाद में पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या, आरोपित पति फरार

बूंदी। जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र के ठीकरी कला गांव में पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे की है। ठीकरी कला निवासी हेमराज और उसकी पत्नी रामीबाई के बीच पिछले दो दिनों से विवाद चल रहा था। इसी दौरान विवाद बढ़ने पर हेमराज ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से सिर और गर्दन पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने घायल रामीबाई को 108 एम्बुलेंस की सहायता से तालेड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की तीन बेटियां हैं। घटना की सूचना पर तालेड़ा पुलिस उप अधीक्षक राजेश टेलर मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्ट्या मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने वैज्ञानिक तरीके से जांच की है।पुलिस के अनुसार मृतका के बच्चों से भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जिसके आधार पर आरोपित हेमराज को संदिग्ध माना गया है। घटना के बाद से ही आरोपित फरार है और उसका मोबाइल फोन बंद है।

ममता बनर्जी ने भवानीपुर में बूथों का निरीक्षण कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप जड़े

एजेंसी (हि.स.)

कोलकाता

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान आज भवानीपुर में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। यहां से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में हैं। उन्होंने सुबह कई बूथों का दौरा कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। ममता कालीघाट स्थित अपने आवास से निकलकर चेतला और पद्मपुकुर रोड इलाके में पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने कई मतदान केंद्रों के बाहर रुककर स्थिति का जायजा लिया और पार्टी कार्यकताओं से बातचीत भी की। बाद में उन्होंने चक्रबेड़िया क्षेत्र के एक बूथ का भी निरीक्षण किया।

फोटोः हि.स.

इस दौरान मीडिया से बातचीत में ममता ने मतदान प्रक्रिया के दौरान बाहरी पर्यवेक्षकों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ लोग बाहर से आकर मतदाताओं में भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले बिना परामर्श के किए जा रहे हैं। ममता ने कहा, कई पर्यवेक्षक राज्य के बाहर से आये हैं। वे बीजेपी के आदेश पर काम कर रहे हैं। कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। हमने कोर्ट की अवमानना का नोटिस भेजा है, फिर भी कई बाहरी पर्यवेक्षकों को यहां लाया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग तृणमूल कांग्रेस को खुलेआम परेशान कर रहा है। न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं हो रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी पर्यवेक्षक मतदाताओं के बीच भय और दहशत फैला रहे हैं।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत एशिया में भी मिला-जुला कारोबार

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से आज मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि डाउ जॉन्स फ्यूचर्स आज बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान मिला-जुला कारोबार होता रहा। एशियाई बाजार में भी आज मिला-जुला कारोबार हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बूम की आशंका के कारण अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान टेक शेयरों में जोरदार गिरावट का रुख बना रहा। इसकी वजह से वॉल स्ट्रीट के ओवरऑल कारोबार पर भी निगेटिव असर पड़ा। डाउ जॉन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 49,141.93 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह एसएंडपी 500 इंडेक्स ने 0.49 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 7,138.80 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डेक 223.30 अंक यानी

फोटोः हि.स.

0.90 प्रतिशत टूट कर 24,663.80 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं डाउ जॉन्स फ्यूचर्स आज फिलहाल 0.17 प्रतिशत की मजबूती के साथ 49,223.42 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के कारोबार के बाद मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। एफटीएसई इंडेक्स 0.11 प्रतिशत की मजबूती के साथ 10,332.79 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसके विपरीत सीएसी इंडेक्स ने 0.47 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 8,104.09 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 0.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,018.26 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

इतिहास जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने की थी आत्महत्या

हिटलर के अंत के साथ खत्म हुआ एक क्रूर अध्याय

एजेंसी (हि.स.)

इतिहास में 30 अप्रैल की तारीख एक अहम और भयावह मोड़ के रूप में दर्ज है। इसी दिन 1945 में जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में आत्महत्या कर ली थी। बताया जाता है कि जब सोवियत सेना बर्लिन को चारों ओर से घेर चुकी थी, तब हिटलर ने अपने भूमिगत बंकर में खुद को गोली मार ली। उनके साथ उनकी पत्नी इवा ब्राउन ने भी आत्महत्या कर ली। यह बंकर जमीन से करीब 50 फीट नीचे स्थित था, जहां हिटलर ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नीतियों ने दुनिया को गहरे संकट में डाल दिया था। विशेष रूप से यहूदियों के खिलाफ चलाए गए उनके नरसंहार अभियान ने मानव इतिहास पर अमिट काला धब्बा छोड़ा। हिटलर की मौत के साथ ही नाजी शासन का अंत तेजी से करीब आ गया और यूरोप में युद्ध समाप्ति की

निधन

1030 - भारत में कई मंदिरों को लूटने वाले महमूद गजनवी का निधन। 1837 - हरि सिंह नलवा - महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष। 2011 - दोरजी खांडू - अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। 2020 - ऋषि कपूर - भारतीय फि ल्म अभिनेता, फि ल्म निमार्ता और निर्देशक थे। 2020 - चुनी गोस्वामी - प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर थे। 2021 - रोहित सरदाना - भारतीय समाचार वक्ता थे।

प्रक्रिया शुरू हुई। 30 अप्रैल का दिन आज भी इस बात की याद दिलाता है कि सत्ता का दुरुपयोग और कट्टर विचारधारा किस तरह पूरी दुनिया को विनाश की ओर धकेल सकती है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र

1999 - लेविंस्की-क्लिंटन मामले को दुनिया के सामने लाने वाले पत्रकार माइकल इशिकॉफ को अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका न्यूज वीक का 'नेशनल मैंगनीज अवार्ड' प्रदान किया गया। 1999 - हिन्द महासागर के द्वीप कोमोरोस में सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा। 2000 - आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग के आहवान के साथ जी -77 शिखर सम्मेलन हवाना में सम्पन्न। 2001 - फिलीपींस में एस्त्रादा समर्थकों द्वारा तख्ता पलट का प्रयास। 2002 - पाकिस्तान में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के अगले 5 वर्षों के कार्यकाल में वृद्धि के लिए जनमत संग्रह सम्पन्न। 2004 - फजुला (ईराक) में हिंसा में 10 अमेरिकी सैनिक मारे गये। 2005 - नरेश के असाधारण अधिकार बरकरार रखते हुए नेपाल में इमरजेंसी समाप्त। 2006 - 2011 क्रिकेट विश्वकप की मेजबानी भारतीय उपमहाद्वीप को मिली। 2007 - नेत्रहीन पायलट माइल्स हिल्टन ने विमान से आधी दुनिया का चक्कर लगाकर रिकार्ड बनाया। 2008 - चालक रहित विमान लक्ष्य का उड़ीसा के बालासोर ज़िले के चाँदीपुर समुद्र तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 2010 - हिन्दी चलचित्रों के सदाबहार अभिनेता देव आनंद को शुक्रवार को मुंबई में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से तथा प्राण को फाल्के आइकॉन से सम्मानित किया गया। 2017- नेपाल के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की पर महाभियोग का प्रस्ताव।

जन्म

1870 - दादा साहब फाल्के - भारत के प्रसिद्ध फि ल्म निमार्ता-निर्देशक एवं पटकथा लेखक। 1896 : आनंदमयी मां का जन्म। 1909 - आर. शंकर - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ तथा केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। 1927 - फातिमा बीबी - भारत में सर्वोच्च न्यायालय की भूतपूर्व न्यायाधीश थी। 1949 - एंटोनियो गुटेरेस - संयुक्त राष्ट्र संघ के नौवें महासचिव हैं। 1966 - बीसेट्टी वेंकट सत्यवती - आंध्र प्रदेश की महिला राजनीतिज्ञ हैं। 1967 - मीनाक्षी लेखी - भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिज्ञ और सक्रिय राजनेता हैं।

चैंपियंस लीग में गोल वर्षा: पीएसजी ने सेमीफाइनल का पहला चरण 5-4 से जीता

पीएसजी बनाम बायर्न में गोलों की आतिशबाजी, पेरिस का रोमांचक प्रदर्शन

एजेंसी (हि.स.)
पेरिस

फुटबॉल की दुनिया में अक्सर ऐसी रातें आती हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। मंगलवार की रात 'पार्क डेस प्रिंसेस' स्टेडियम में कुछ ऐसा ही हुआ। चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) और बायर्न म्यूनिख के बीच खेला गया पहला चरण फुटबॉल प्रेमियों के लिए किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। कुल नौ गोल और अंतिम क्षणों तक बना रोमांच, यह मैच चैंपियंस लीग के नॉकआउट इतिहास में सबसे अधिक गोल वाले मैचों में से एक बन गया है। मौजूदा चैंपियन पीएसजी ने बायर्न म्यूनिख को 5-4 से हराकर फाइनल की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाया है।

मैच का परिणाम भले ही पीएसजी के पक्ष में रहा, लेकिन यह मुकाबला इतना कड़ा था कि अंत में कोच लुइस एनरिक ने भी इसे एक 'अभूतपूर्व' अनुभव बताया। उन्होंने मैच के बाद कहा, हम जीतने के हकदार थे, हम हारने के हकदार थे, हम ड्रॉ के हकदार थे। मैंने अपने कोचिंग करियर में इससे तीव्र और कड़ा मुकाबला कभी नहीं देखा। यह मैच केवल जीत-हार के लिए नहीं, बल्कि गोलों की झड़ी के लिए याद रखा जाएगा। बायर्न म्यूनिख के हैरी केन ने 17वें मिनट में पेनल्टी के जरिए गोल करके अपनी टीम को शुरूआती बढ़त दिलाई थी। ऐसा लगा कि बायर्न हावी हो जाएगी, लेकिन पीएसजी ने अपने घरेलू मैदान पर शानदार वापसी की। ख्विचा क्वारात्सखेलिया ने 24वें मिनट में शानदार गोल करके स्कोर बराबर किया और फिर 33वें मिनट में जोआओ नेवेस के गोल ने पेरिस को बढ़त दिला दी। मैच का पहला हाफ गोलों से भरा रहा। बायर्न के माइकल ओलिस ने 41वें मिनट में बराबरी का

गोल दागा, लेकिन हाफ टाइम से ठीक पहले ओसमान डेम्बेले ने पेनल्टी पर गोल करके पीएसजी को 3-2 की बढ़त के साथ ब्रेक में भेजा। दूसरे हाफ में पीएसजी और भी आक्रामक हो गई। क्वारात्सखेलिया (56वें मिनट) और डेम्बेले (58वें मिनट) ने अपने दूसरे-दूसरे गोल दागकर पीएसजी को 5-2 की विशाल बढ़त दिला दी। ऐसा लग रहा था कि मैच बायर्न के हाथों से निकल चुका है, लेकिन जर्मन टीम ने हार नहीं मानी। 65वें मिनट में डेयोत उपामाकानो और 68वें मिनट में लुई डियाज ने गोल करके मैच को 5-4 पर लाकर खड़ा कर दिया। अंतिम मिनटों में पीएसजी की रक्षापंक्ति ने दबाव को झेला और विलीयन पैचो ने अंतिम क्षणों में एक महत्वपूर्ण गोल बचाया, जिससे टीम अपनी बढ़त बचाने में सफल रही। यह चैंपियंस लीग के नॉकआउट इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा गोल वाला मैच बन गया है। इससे पहले 2020 में बायर्न म्यूनिख ने बार्सिलोना को 8-2 से हराया था, जिसमें बायर्न की अहम भूमिका थी। इस रोमांचक मुकाबले के पीछे दोनों टीमों की रणनीतियां भी चर्चा का विषय रहीं। बायर्न म्यूनिख के मुख्य कोच विन्सेंट कोम्पनी के निलंबित होने के कारण टीम स्टैंड से निर्देश देख रही थी और उनकी जगह सहायक कोच आरोन डैंक्स ने टीम की कमान संभाली। बायर्न ने 'हाई डिफेंसिव लाइन' (रक्षापंक्ति को ऊपर रखना) की रणनीति अपनाई थी, जिसका पीएसजी ने बखूबी फायदा उठाया। क्वारात्सखेलिया और डेम्बेले की गति ने बायर्न के रक्षात्मक ढांचे को बार-बार भेदकर पीएसजी को काउंटर-अटैक में बढ़त दिलाई। दूसरी ओर, पीएसजी के कोच लुइस एनरिक ने अपनी टीम की मानसिकता की जमकर तारीफ की।

हमने वास्तविकता का सामना किया, लेकिन पहली हार के बाद हताश नहीं हैं: जेम्स होप्स

एजेंसी (हि.स.)
मुल्लांपुर

पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाजी कोच जेम्स होप्स ने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मौजूदा सत्र में उनकी टीम की पहली हार से उसे वास्तविकता का पता चला लेकिन स्पष्ट किया कि इससे टीम के अंदर किसी तरह की निराशा नहीं है। तालिका में शीर्ष पर काबिज पंजाब किंग्स को मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स से छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच से पहले वह प्रतियोगिता की एकमात्र अजेय टीम थी।

होप्स ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, यह वास्तविकता का सामना करने जैसा है। हम शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मैच जीत रहे हैं और यह बहुत अच्छा है। हर कोई खुश है और माहौल अब भी बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा, यह हमारा आठवां मैच था और यह हमारी पहली हार है। हमारे ड्रेसिंग रूम में किसी तरह की निराशा का माहौल नहीं है। पंजाब किंग्स का अगला मैच रविवार को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस से होगा और होप्स ने कहा कि उनका ध्यान छोटी-मोटी कमियों को दूर करने पर होगा। उन्होंने कहा, आप आईपीएल में बिना कोई मैच हारे आगे नहीं बढ़ सकते। अब हमारे पास गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच खेलने से पहले कुछ दिन का समय है और इससे हमें फिर से एकजुट होने में मदद मिलेगी। हम अभ्यास के दौरान अपनी कुछ कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच कुमार संगकारा तालिका में शीर्ष पर काबिज टीम के खिलाफ मिली जीत से बेहद खुश थे और उन्होंने कहा कि इससे उनकी टीम को काफी राहत मिली है। पंजाब किंग्स अभी 13 अंक लेकर शीर्ष पर काबिज है जबकि राजस्थान रॉयल्स के 12 अंक हैं और वह तीसरे स्थान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भी इतने ही अंक हैं लेकिन वह बेहतर नेट रन रेट के कारण दूसरे स्थान पर है। संगकारा ने कहा, यहां आकर तालिका में शीर्ष पर काबिज टीम के खिलाफ खेलना आसान नहीं था। यह एक अच्छी जीत है। जीतना और थोड़ी राहत पाना हमेशा अच्छा होता है। उन्होंने बल्लेबाजों के सामूहिक प्रयास विशेषकर इंपैक्ट सब्सीट्यूट के रूप में आए बल्लेबाज शुभम दुबे की 12 गेंदों में 31 रन की प्रभावशाली पारी की विशेष रूप से प्रशंसा की। संगकारा ने कहा, मैंने आज दुबे के बारे में सोचा, जो इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट के रूप में क्रीज पर उतरा। ऐसी स्थिति में अच्छा प्रदर्शन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको यह नहीं पता होता है कि आप खेलेंगे या नहीं।

अफगानिस्तान की महिला शरणार्थी टीम को फीफा टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति मिली

एजेंसी (हि.स.)
वाशिंगटन

विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने अफगानिस्तान की महिला शरणार्थी टीम को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दे दी है। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय टीम की महिला खिलाड़ियों ने तालिबान शासन के कारण पांच साल पहले अपना देश छोड़ दिया था और तब से वह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेलने की अनुमति मिलने का इंतजार कर रही थी। ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में मंगलवार को हुई फीफा परिषद की बैठक में अफगानिस्तान की महिला शरणार्थी टीम को मान्यता देने के लिए फीफा के नियमों में संशोधन करने पर सहमति बनी। अफगानिस्तान की महिला टीम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अफगान महिला यूनाइटेड नाम से भाग लेगी।अफगानिस्तान की महिला टीम के लिए हालांकि ब्राजील में 2027 में होने वाले महिला विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने के लिए बहुत देर हो चुकी है लेकिन वह लॉस एंजिलिस में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों के क्वालीफाइंग में भाग ले सकती है।

मुंह ढककर बहस करने पर खिलाड़ी को मिल सकता है लाल कार्ड

- फुटबॉल के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव
- अनुशासन और गरिमा को प्राथमिकता: रेफरी के फैसलों पर विरोध को लेकर सख्त गाइडलाइंस

एजेंसी (हि.स.)
वैंकूवर

चैंपियंस लीग मैच के दौरान विनीसियस जूनियर के खिलाफ की गई कथित नस्लीय टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ बोर्ड (आईएफएबी) ने एक नए नियम को मंजूरी दी है जिससे खिलाड़ियों को दूसरे खिलाड़ी से मौखिक बहस करते समय मुंह ढकने पर लाल कार्ड से दंडित किया जाएगा।

ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में मंगलवार को हुई बैठक में आईएफएबी ने सर्वसम्मति से इस नियम को मंजूरी दी। यह नियम 11 जून से शुरू होने वाले विश्व कप फुटबॉल में लागू होगा। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने इस नियम का प्रस्ताव तब रखा था जब रियाल मैड्रिड के विनीसियस जूनियर ने फरवरी में चैंपियंस लीग मैच के दौरान बेनफिका के जियानलुका प्रेस्टियानी पर मुंह ढककर नस्लीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। यूरोपीय फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था यूईएफए ने पिछले सप्ताह प्रेस्टियानी पर छह मैचों का प्रतिबंध लगा दिया था। अगर प्रेस्टियानी को अर्जेंटीना की विश्व कप टीम में चुना जाता है तो उन्हें पहले दो मैचों से बाहर रहना पड़ सकता है। इस प्रतिबंध के खिलाफ हालांकि अपील की जा सकती है। आईएफएबी ने बयान में कहा, किसी विरोधी खिलाड़ी के खिलाफ बहस के दौरान मुंह ढकने वाले किसी भी खिलाड़ी को लाल कार्ड से दंडित किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के नियम तय करने वाली संस्था ने यह भी घोषणा की कि रेफरी के फैसले के विरोध में मैदान छोड़ने वाले किसी भी खिलाड़ी को लाल कार्ड दिखाया जा सकता है। यह नियम उन टीम अधिकारियों पर भी लागू होगा जो खिलाड़ियों को मैदान छोड़ने के लिए कहते हैं। आईएफएबी ने कहा कि इन संशोधन के बारे में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले विश्व कप में भाग लेने वाली सभी 48 टीमों को बता दिया जाएगा। इसके साथ ही फीफा ने विश्व कप के पीले कार्ड संबंधी नियमों में बदलाव किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महत्वपूर्ण मैचों के लिए कम खिलाड़ियों को निलंबित किया जाए। नए नियम के अनुसार विश्व कप के दौरान किसी खिलाड़ी को मिला पीला कार्ड दो बार उसके रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा।

फीफा ने एक बयान में कहा, फीफा परिषद ने फीफा विश्व कप 2026 के नियमों में एक संशोधन किया है, जिसके अनुसार किसी खिलाड़ी को ग्रुप चरण में मिला एक पीला कार्ड नाकआउट चरण में मान्य नहीं होगा। इसी तरह से क्वार्टर फाइनल में मिला एक पीला कार्ड अगले मैचों के लिए मान्य नहीं होगा। विश्व कप में इससे पहले यदि किसी खिलाड़ी को दो अलग-अलग मैचों में पीला कार्ड दिखाया जाता था तो उसे एक मैच का प्रतिबंध झेलना पड़ता है, लेकिन पिछले टूर्नामेंटों में क्वार्टर फाइनल चरण के बाद एक पीले कार्ड को रद्द कर दिया जाता था। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि सेमीफाइनल में पीला कार्ड मिलने के कारण किसी भी खिलाड़ी को फाइनल से बाहर नहीं होना पड़ेगा।

ड्रेसिंग रूम में 'वेपिंग' करते पकड़े गए रियान पराग, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान विवादों में घिरे

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के मौजूदा सत्र में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग एक गंभीर विवाद में फंस गए हैं। मुल्लांपुर में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान पराग को टीम के ड्रेसिंग रूम में 'वेपिंग' (ई-सिगरेट का उपयोग) करते हुए टीवी कैमरों में कैद किया गया। यह फुटेज सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे न केवल खिलाड़ी की छवि पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि बीसीसीआई और आईपीएल प्रबंधन के लिए भी स्थिति असहज हो गई है। यह घटना केवल खेल की मयार्दा का उल्लंघन नहीं, बल्कि कानूनी दायरे में भी आती है। भारत सरकार ने 2019 में ई-सिगरेट निषेध अधिनियम के तहत इनके उत्पादन, बिक्री, वितरण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। कानून के अनुसार, इस अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर एक साल तक

की कैद और एक लाख रुपये तक का जुमार्ना हो सकता है। बीसीसीआई और आईपीएल से जुड़े अधिकारियों ने इस कृत्य को अत्यधिक 'लापरवाही' करार दिया है। एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया, कई खिलाड़ी ई-सिगरेट का सेवन करते हो सकते हैं, लेकिन ड्रेसिंग रूम जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में कैमरे की निगरानी में ऐसा करना बेहद जोखिम भरा है। पराग को खुलेआम ऐसा करते पकड़े जाने के बाद बीसीसीआई को मजबूरन उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ सकती है। हालांकि, राजस्थान रॉयल्स की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस घटना ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों की 'निजता' के पुराने विवाद को भी फिर से हवा दे दी है।

दर्पण करियर

सहायक आचार्य के 107 पदों पर भर्ती का संशोधित नोटिस जारी, पुराने अभ्यर्थियों को भी दोबारा करना होगा आवेदन

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बीएड विषय में सहायक आचार्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया को एक बार फिर शुरू करते हुए संशोधित विज्ञापन संख्या 51 जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जारी इस नए नोटिफिकेशन के तहत कुल 107 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 मई निर्धारित की गई है, जबकि आवेदन पत्र में संशोधन करने की सुविधा 30 मई तक उपलब्ध रहेगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 28 जुलाई 2026 को किया जाएगा।

कौन कर सकता है आवेदन

इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे, जिन्होंने 31 अगस्त 2022 तक एनसीटीई रेगुलेशन-2014 के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी कर ली थी। यानी केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जो निर्धारित समयसीमा तक आवश्यक डिग्री और योग्यता हासिल कर चुके हैं।

इन अभ्यर्थियों को दोबारा करना होगा आवेदन

खास बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, उन्हें भी नए सिरे से आवेदन करना अनिवार्य होगा। हालांकि, ऐसे उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आयोग ने उनकी सुविधा के लिए पुराने आवेदन नंबर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भेज दिए हैं, ताकि वे आसानी से दोबारा आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकें।

पहले भी विज्ञापित हो चुकी है यह भर्ती

गौरतलब है कि यह भर्ती पहले भी दो बार जारी की जा चुकी थी, लेकिन पात्रता को लेकर विवाद और न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण इसे रद्द करना पड़ा था। अब नई पात्रता शर्तों को तय करने के बाद आयोग ने फिर से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग के उपसचिव डॉ. संजय कुमार सिंह के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की गलती से बचा जा सके।

ग्रेजुएट्स के लिए शानदार मौका, यूनियन बैंक में 1865 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आधिकारिक वेबसाइट पर अप्रेंटिस की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। बैंक विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए कुल 1865 रिक्तियों की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 29 अप्रैल 2026 से 19 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान, कॉलेज या विश्वविद्यालय (जैसे AICTE/UGC से मान्यता प्राप्त) से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही, आपकी ग्रेजुएशन का रिजल्ट 1 अप्रैल 2026 या उससे पहले घोषित हो चुका होना चाहिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपकी स्नातक डिग्री बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी आपने 01 अप्रैल 2022 या उसके बाद ग्रेजुएशन पास किया हो। अगर आपकी डिग्री इससे पहले की है, तो आप इस भर्ती के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। यह आयु सीमा सभी श्रेणियों के लिए समान है (हालांकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिल सकती है)।

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले NATS पोर्टल पर रजिस्टर करके अपनी Student Enrollment ID लें। BFSI SSC की साइट पर जाकर Union Bank के लिंक पर क्लिक करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी और NATS ID भरें। फोटो, सिग्नेचर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करें। अपनी कैटेगरी के अनुसार ऑनलाइन फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें।

कितना मिलेगा स्टाइपेंड

अप्रेंटिसशिप के दौरान उम्मीदवारों को हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो उनकी पोस्टिंग के स्थान के अनुसार तय होगा। यदि आपकी नियुक्ति ग्रामीण या सेमी-अर्बन (अर्ध-शहरी) क्षेत्र में होती है, तो आपको 15,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। वहीं शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग होने पर 18,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, और अगर आपकी नियुक्ति मेट्रो सिटी में होती है, तो आपको 20,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा।

आवेदन शुल्क

वर्ग	आवेदन शुल्क	इंटिमेशन फीस	कुल शुल्क + 18% GST
सामान्य/ओबीसी पुरुष	600	200	944
सामान्य/ओबीसी महिला	400	200	708
एससी/एसटी	0	200	236
पीडब्ल्यूबीडी	0	200	236
ट्रांसजेंडर	0	200	236

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कुल रिक्तियां
उत्तर प्रदेश	335
आंध्र प्रदेश	303
महाराष्ट्र	196
तेलंगाना	164
कर्नाटक	131
मध्य प्रदेश	116
तमिलनाडु	95
बिहार	60
गुजरात	58
ओडिशा	58
पश्चिम बंगाल	56
दिल्ली (ठउळ)	48
केरल	39
झारखंड	34
राजस्थान	32
हरियाणा	30
असम	29
छत्तीसगढ़	25
पंजाब	21
उत्तराखंड	10
चंडीगढ़	6
गोवा	5
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2
जम्मू और कश्मीर	2
सिक्किम	2
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
हिमाचल प्रदेश	1
लद्दाख	1
लक्षद्वीप	1
मेघालय	1
नागालैंड	1
पुदुचेरी	1
त्रिपुरा	1
कुल	1865

यूपीएससी सीएसई की प्रारंभिक परीक्ष 24 मई को होगी फोकस्ड पढ़ाई और सही टाइम मैनेजमेंट बेहद जरूरी

संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 की आधिकारिक तिथि की घोषणा कर दी है, जो 24 मई, 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में चयन की प्रक्रिया का पहला चरण है। यह केवल ज्ञान का ही नहीं, बल्कि धैर्य, संयम, निर्णय क्षमता, समय-प्रबंधन और मानसिक संतुलन की भी परीक्षा होती है। पूरे वर्ष की आपकी मेहनत सफल हो, इसके लिए इन जरूरी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

पहले से पढ़े हुए विषयों को करें मजबूत

इस समय किसी नए टॉपिक की शुरूआत करने से बचें। अपनी पूरी ऊर्जा अपने बनाए हुए नोट्स और बार-बार पढ़े गए अध्यायों पर केंद्रित करें। स्मार्ट रिवीजन करें, यानी उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें, जो परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा, परीक्षा से पहले कम-से-कम पिछले आठ से 10 वर्षों के प्रश्न-पत्रों की प्रवृत्ति को एक बार फिर से समझें, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आयोग किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। इससे प्रश्नों की भाषा, विकल्पों की संरचना और भ्रम उत्पन्न करने वाले पैटर्न को समझने में मदद मिलती है।

मॉक टेस्ट का उपयोग समझदारी से करें

अंतिम दिनों में अत्यधिक नए मॉक टेस्ट देना विशेष लाभकारी नहीं होता, खासकर तब जब वे आपके आत्मविश्वास को प्रभावित करने लगें। यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उनमें की गई गलतियों का विश्लेषण करें और उन्हें सुधारने पर ध्यान दें। यह समझना आवश्यक है कि प्रारंभिक परीक्षा में सभी प्रश्नों के सही उत्तर किसी को भी नहीं आते। इसलिए यह रणनीति स्पष्ट रखें कि किन प्रश्नों को पूरी निश्चितता के साथ करना है, किनमें विकल्प-उन्मूलन तकनीक अपनानी है और किन्हें छोड़ना है।

प्रश्न चयन की स्पष्ट रणनीति बनाएं

सही संतुलन ही सफलता की कुंजी है। प्रश्न-पत्र हाथ में आते ही घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन शुरूआत हमेशा आसान प्रश्नों से करें। कठिन प्रश्नों पर अधिक समय तक अटकना पूरे संतुलन को बिगाड़ सकता है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 'निम्नलिखित में से कौन-सा सही है', 'कौन-सा गलत है', 'केवल', 'सभी', जैसे शब्दों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि कई बार गलती ज्ञान की कमी से नहीं, बल्कि प्रश्न को जल्दबाजी में गलत समझ लेने से होती है। ओएमआर शीट भरते समय पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। कमजोर विषयों का बुनियादी अभ्यास अवश्य करें। गणित, तर्कशक्ति और बोधगम्यता को न्यूनतम सुरक्षित स्तर तक मजबूत करें। केवल महत्वपूर्ण टॉपिक्स और रिवीजन पर ध्यान दें। पर्याप्त नींद लें और हल्का, सुपाच्य भोजन करें। सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें।

पंचकूला नगर निगम चुनाव 2026: मेयर पद के लिए 6 उम्मीदवार और पार्षद के लिए 87 उम्मीदवार मैदान में

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

पंचकूला नगर निगम चुनाव 2026 के तहत नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) और नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेयर पद के लिए 6 उम्मीदवार और पार्षद पद के लिए 87 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। रिटर्निंग ऑफिसर संयम गर्ग ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मेयर पद के लिए कुल 6 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इनमें इनेलो के मनोज अग्रवाल, आम आदमी पार्टी के राजेश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के शाम लाल बंसल, कांग्रेस की सुधा भारद्वाज और आजाद उम्मीदवार के तौर पर करनैल सिंह बांगड और चौधरी चंदन सिंह शामिल हैं।

उन्होने बताया कि नगर निगम के 20 वार्डों में सदस्यों के चुनाव के लिए 87 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जिसमें- वार्ड नंबर-1 से आम आदमी पार्टी की अमृत कौर, भारतीय जनता पार्टी की परमजीत कौर और कांग्रेस की पायल सोढी शामिल हैं। वार्ड नंबर-2 से कांग्रेस की चारू चावला, बीजेपी की परमजीत कौर और निर्दलीय उम्मीदवार जया चानना। वार्ड नंबर-3 से कांग्रेस के रजनीश सिंगला, बीजेपी के सुरेश कुमार वर्मा और निर्दलीय बेनु राव। वार्ड नंबर-4 से बीजेपी के भारत हितैषी और कांग्रेस के राजीव चैधरी। वार्ड नंबर-5 से बीजेपी के जय कुमार कौशिक, इनेलो के तरूण साहनी, कांग्रेस के विजय कुमार शर्मा और आम आदमी पार्टी के विशाल। वार्ड नंबर-6 से आम आदमी पार्टी के गगन चावला, कांग्रेस के दर्शन लाल, बीजेपी के पार्थ गुप्ता और निर्दलीय प्रवीण कुमार गोयल। वार्ड नंबर-7 से इनेलो के गुरदीश, बीजेपी के ज्योति प्रसाद, कांग्रेस के पंकज, आम आदमी पार्टी के राकेश मलिक और निर्दलीय दीपक चावरिया, प्रेम कुमार और भानू प्रताप। वार्ड नंबर-8 से कांग्रेस की उषा रानी, बीजेपी के राजकुमार जैन, आम आदमी पार्टी के विनोद कुमार, इनेलो के हरिंद्र और निर्दलीय प्रदीप तिवारी, राजीव कुमार और सन्नी। वार्ड नंबर-9 से आम आदमी पार्टी के दिनेश ढांडा, इनेलो के नवल किशोर जयसवाल, कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह, बीजेपी के हरेंद्र मलिक, निर्दलीय ममता रविकांत स्वामी और सुखबीर सिंह। वार्ड नंबर-10 से इनेलो के अंकुश कुमार, कांग्रेस के बलजीत सिंह, आम आदमी पार्टी के मंजेश, बीजेपी के शेखर और निर्दलीय कार्तिक कौशल, धनंजय कुमार गुप्ता, राजेश कुमार और सौरव चौधरी शामिल है।

वार्ड नंबर-11 से बीजेपी की अनुराधा पुरी और कांग्रेस की अंजू। वार्ड नंबर-12 से कांग्रेस के जगजीत सोई, बीजेपी के राकेश जगोता, आम आदमी पार्टी के संजीव कुमार और निर्दलीय ओमवती पूनिया। वार्ड नंबर-13 से कांग्रेस के अक्षय चौधरी, बीजेपी के दीपक गर्ग और आम आदमी पार्टी के विशाल भारद्ववाज। वार्ड नंबर-14 से कांग्रेस के पीयूष गौतम, बीजेपी के राकेश गोयल और आम आदमी पार्टी के सुमित कुमार।

वार्ड नंबर-15 से आम आदमी पार्टी की पिंकी, बीजेपी की प्रियंका, कांग्रेस की सरस्वती देवी और निर्दलीय मोनिका, राजेंद्र कौर और रितु। वार्ड नंबर-16 से बीजेपी की निर्मला देवी, आम आदमी पार्टी की रोशनी देवी, कांग्रेस की सुनिता और निर्दलीय जतिंद्र कौर, नैना, रितु परमार और सुनिता बागडी। वार्ड नंबर-17 से आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार (वकील), इनेलो के आशीष कुमार रंगा, कांग्रेस के मुकेश कुमार, बीजेपी के सुदेश कुमार और निर्दलीय अशोक कुमार। वार्ड नंबर-18 से कांग्रेस की अमनदीप कौर और बीजेपी की पूजा रानी। वार्ड नंबर-19 से कांग्रेस की नजमा, बीजेपी की मनीषा रानी और निर्दलीय रजविंद्र कौर और वार्ड नंबर-20 से इनेलो के गुरदास सिंह बैहर, बीजेपी के गौतम सिंह, कांग्रेस के विकास और निर्दलीय रोहित चौधरी और सचिन गुप्ता शामिल हैं।

स्वच्छता बनाए रखने में प्रशासन को सहयोग देने की नागरिकों से की अपील

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

नगर निगम पंचकूला की संयुक्त आयुक्त सिमरनजीत कौर द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत शहर के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य शहर में स्वच्छता व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का आकलन करना तथा आवश्यक सुधारों की पहचान करना था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता, रखरखाव और उपयोगिता की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान शौचालयों में पाई गई कमियों—जैसे सफाई की कमी, पानी की अनुपलब्धता तथा मरम्मत संबंधी खामियों—को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने मौके पर ही संबंधित ठेकेदार को तुरंत प्रभाव से इन्हें ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शौचालयों की गुणवत्ता और स्वच्छता में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने शहर में कूड़ा प्रबंधन प्रणाली, सड़क एवं नालियों की सफाई, डस्टबिन की उपलब्धता और उनके नियमित उपयोग की भी समीक्षा की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि कूड़ा निर्धारित स्थानों पर ही डाला जाए और समय-समय पर उसका उचित निस्तारण किया जाए। निरीक्षण के दौरान कुछ गलियों में सीवरेज चैंबर टूटे हुए पाए गए, जिससे आमजन को असुविधा के साथ-साथ दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई थी। इस पर उन्होंने संबंधित कार्यकारी अभियंता को तुरंत प्रभाव से इन चैंबरों की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई, जबकि कुछ स्थानों पर सुधार की आवश्यकता भी चिन्हित की गई। संयुक्त आयुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी रखें और कमियों को शीघ्र दूर करें। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे स्वच्छता बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें और अपने आसपास के वातावरण को साफ-सुथरा रखने की जिम्मेदारी निभाएं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत शहर को बेहतर रैंक दिलाने के लिए प्रशासन और जनता के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। इस अवसर पर सीएसआई अनिल नैन, एसबीएम से प्रदीप, एएसआई अशोक और आईइसी टीम के सदस्य भी मौजूद थे।

ध्वनि प्रदूषण के समाधान के लिए नियमित जागरूकता अभियान जरूरी: सुशील डोगरा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

ध्वनि प्रदूषण चंडीगढ़ की नहीं पूरे देश की गंभीर समस्या है। इस समस्या को स्वीकार सभी करते हैं लेकिन इसके समाधान को लेकर जागरूकता का अभाव है। उक्त विचार चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति के वैज्ञानिक सुशील डोगरा ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय नॉइज जागरूकता दिवस के अवसर पर सेक्टर-आठ स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में प्रयोग फाउंडेशन तथा सर्वप्रेम फाउंडेशन द्वारा ध्वनि प्रदूषण के विरूद्ध शुरू किए गए जागरूकता अभियान ह्यध्वनि-द पीसह्न को लांच करने के बाद विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। सुशील डोगरा ने कई उदाहरणें देते हुए विद्यार्थियों को बताया कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए बकायदा नियम व कानून बने हुए हैं। परीक्षा के दिनों में होने वाली परेशानी से छुटकारा पाने के लिए बच्चे डायल 112 पर सूचित कर सकते हैं। उन्होंने प्रयोग फाउंडेशन तथा सर्वप्रेम फाउंडेशन के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस अभियान को नियमित रूप से चलाया जाए तो सिटी ब्यूटीफुल को ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। सुशील डोगरा ने कार्यक्रम में शामिल स्कूली बच्चों तथा अन्य प्रतिभागियों को ध्वनि प्रदूषण न फैलाने को लेकर शपथ भी दिलाई। स्कूल में 300 से अधिक विद्यार्थी इस मुहिम का हिस्सा बने। कार्यक्रम के दौरान ईएनटी रोग विशेषज्ञ डॉ.प्राची बराक ने एक प्रस्तुति के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण के कारण बच्चों में हो रही बीमारियों तथा इसके बचाव के बारे में बताया। स्कूल प्रिंसिपल मनतोष पाल सिंह ने बच्चों में हैडफोन लगाकर पढ़ाई करने की आदत पर अपनी रखते हुए बताया कि कैसे अशोक का पेड़ ध्वनि प्रदूषण को रोकने में सहायक होता है। आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए डॉ.रोमिका वढेरा ने बताया कि कैसे यह प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई गई। इस आयोजन में सेवानिवृत्त प्रिंसिपल आराधना ओझा, डॉ.अशोक वढेरा तथा साहित्यकार सीमा गुप्ता ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। इस अवसर पर प्रयोग फाउंडेशन चंडीगढ़ के अध्यक्ष नितेश महाजन, फायर अवेयरनेस एन्ड सेफ्टी एसोसिएशन के अध्यक्ष जसजोत सिंह अलमस्त, ध्वनि द पीस की प्रोजेक्ट कोआर्डिनेट डॉ.कविता शर्मा, संजय ओझा, सृजन आदि गणमान्य मौजूद थे।

नगर निगम चुनाव-2026: पंचकूला में 550 ईवीएम मशीनों की प्रथम रैंडमाइजेशन सम्पन्न

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

राज्य चुनाव आयोग द्वारा नामित सामान्य पर्यवेक्षक एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री डी. सुरेश, उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सतपाल शर्मा, रिटर्निंग अधिकारी श्री संयम गर्ग तथा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की उपस्थिति में लघु सचिवालय के सभागार में नगर निगम चुनाव-2026 के लिए ईवीएम मशीनों की प्रथम रैंडमाइजेशन प्रक्रिया सम्पन्न हुई। इस प्रक्रिया में रिजर्व मशीनों सहित कुल 550 ईवीएम का चयन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सतपाल शर्मा ने बताया कि रैंडमाइजेशन एक पारदर्शी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक उम्मीदवार चुनावी प्रक्रिया से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो।

उन्होंने जानकारी दी कि नगर निगम चुनाव-2026 के अंतर्गत 20 वार्डों के लिए 204 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो वोटिंग मशीनें स्थापित की जाएंगी—एक मेयर पद के लिए और दूसरी पार्षद पद के लिए—जिससे मतदाता दो अलग-अलग वोट डाल सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जिला में ईवीएम मशीनों की समय-समय पर फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी मशीनें पूरी तरह से कार्यशील हैं। चुनावों में प्रयुक्त मशीनों के चयन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए रैंडमाइजेशन प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

बैठक में उपस्थित उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से पालन तथा चुनावी खर्च के नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मेयर पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम 30 लाख रुपये तथा पार्षद पद के उम्मीदवार के लिए 7.50 लाख रुपये खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। प्रत्येक उम्मीदवार को 1 मई, 4 मई और 7 मई को अपने व्यय रजिस्टर की जांच करवाना अनिवार्य होगा।

संक्षिप्त-समाचार

जिला की मंडियों में सुचारू रूप से चल रहा है गेंहू की खरीद और उठान का कार्य

पंचकूला। जिला में रबी सीजन 2026-27 के दौरान गेंहू की खरीद एवं उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला की मंडियों में से अब तक 35163 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई और 23996 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा रायपुररानी, बरवाला और पंचकूला स्थित अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि रायपुररानी अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 4562 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कोरपोरेशन द्वारा 12968 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई। इसी प्रकार बरवाला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 7743 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोशन द्वारा 8385 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई। इसके अलावा पंचकूला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 1505 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई। उन्होने बताया कि मंडियों में खरीद के साथ साथ उठान का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। रायपुररानी अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 2962 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कोरपोरेशन द्वारा 6867 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया। इसी प्रकार बरवाला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 6352 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोशन द्वारा 7137 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया। पंचकूला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 678 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया।

पीजीआई चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी दिवस 2026 मनाया गया

चंडीगढ़। पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआई) के इम्यूनोपैथोलॉजी विभाग ने 29 अप्रैल 2026 को पीजीआई चंडीगढ़ के NINE ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी दिवस 2026 सफलतापूर्वक मनाया। यह कार्यक्रम सोसाइटी फॉर लैबोरेटरी इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोपैथोलॉजी के तत्वावधान में इस थीम के साथ आयोजित किया गया था: इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच इम्यून सिस्टम, स्वस्थ जीवनशैली की आदतों, टीकाकरण, ऑटोइम्यूनिटी और कैंसर इम्यूनिटी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना था। इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ के विभिन्न स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, और यह युवा मस्तिष्कों में वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देने वाला एक संवादात्मक शैक्षिक मंच साबित हुआ। डॉ. रंजना डब्ल्यू मिंज (इम्यूनोपैथोलॉजी विभाग की पूर्व प्रमुख) ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई और बच्चों को इम्यूनिटी, बीमारियों की रोकथाम और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करने के लिए इम्यूनोपैथोलॉजी विभाग द्वारा की गई पहल की सराहना की। उन्होंने छात्रों को स्वास्थ्य सेवा और निवारक चिकित्सा के संबंध में वैज्ञानिक जिज्ञासा और जागरूकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में इम्यूनिटी और स्वस्थ आदतों पर आधारित एक संवादात्मक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और पोस्टर-बनाने की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसने भाग लेने वाले छात्रों में भारी उत्साह पैदा किया। पोस्टर-बनाने की प्रतियोगिता ने इम्यूनिटी, टीकाकरण, स्वस्थ जीवनशैली, संक्रमण की रोकथाम और इम्यून विकारों से संबंधित विषयों पर छात्रों की रचनात्मकता और समझ को उजागर किया। प्रश्नोत्तरी और पोस्टर प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। आयोजन समिति में प्रो. बिमान सैकिया (संयोजक), डॉ. महेंद्र कुमार (आयोजन सचिव), और उनके साथ PGIMER के इम्यूनोपैथोलॉजी विभाग के फैकल्टी सदस्य, रेजिडेंट, शोधकर्ता और अन्य क्लिनिकल कर्मचारी शामिल थे। विभाग ने इस कार्यक्रम को शानदार सफलता बनाने में अपने सहयोग और योगदान के लिए शिक्षा विभाग, UT चंडीगढ़, भाग लेने वाले स्कूलों, शिक्षकों, छात्रों और मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

प्रशासन ने ग्रीष्मकाल के लिए जनस्वास्थ्य परामर्श जारी किया

चंडीगढ़। वर्तमान ग्रीष्मकालीन मौसम तथा खाद्य जनित बीमारियों के बढ़ते जोखिम को देखते हुए, खाद्य सुरक्षा विभाग, चंडीगढ़ द्वारा आम जनता को फलों की खरीद एवं उपभोग के दौरान निम्नलिखित सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है: सड़क किनारे ठेलों, रेहड़ी बाजारों एवं खुले में बिकने वाले कटे या छिले हुए फलों का सेवन न करें। ये धूल, मक्खियों तथा अन्य प्रकार के प्रदूषण के संपर्क में होते हैं। अत्यधिक पके हुए, दबे-खराब, क्षतिग्रस्त या असामान्य गंध/दिखावट वाले फल न खरीदें। सभी फलों को खाने से पहले स्वच्छ पेयजल से अच्छी तरह धोएं, भले ही उन्हें छीलना हो। केवल साफ-सुथरे एवं स्वच्छता बनाए रखने वाले दुकानदारों/विक्रेताओं से ही फल खरीदें। कटे हुए फलों का तुरंत सेवन करें। विशेषकर गर्म मौसम में इन्हें अधिक समय तक सुरक्षित न रखें।

पंचकूला से रजनीश गुलाटी, पियूष गुलाटी तथा अवनीशजोत कांग्रेस को अलविदा कह भाजपा में शामिल

पंचकूला। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं पंचकुला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन के विश्वास पात्र एवं मीडिया इंचार्ज रहे हेमंत किंगर द्वारा मुख्यमंत्री नायब सैनी तथा हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली की मौजूदगी में अपने साथियों सहित भाजपा में शामिल होने से भाजपा मेयर प्रत्याशी श्याम लाल को अपने विरोधियों पर बढ़त बनाते हुये उनके चुनाव प्रचार को लगातार मजबूती मिल रही है, उनके अलावा पंचकुला जिले से रजनीश गुलाटी, पियूष गुलाटी तथा अवनीशजोत ने भी कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा का झंडा उठा लिया है. पूर्व मंत्री राजकुमार बाल्मीकि द्वारा भी भाजपा में शामिल होने के बाद पंचकुला मेयर पद पर अनुसूचित जाति के वोटों का धुर्विकरण भी भाजपा के पक्ष में होने के आसार बन गए हैं। हरियाणा प्रदेश भाजपा कार्यालय पंचकमल में हरियाणा निकाय चुनाव संकल्प पुस्तिका का विमोचन करते हुये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को विश्वास दिलाया है कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन सरकार बनते ही संकल्प पत्र में शामिल सभी 21 वायदों को पूरा किया जायेगा।

आयुर्वेद रोगों के उपचार के साथ संपूर्ण जीवनशैली : प्रो. सतीश गंधर्व

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

एनआईए जयपुर के बीएएमएस बैच 2023-24 के विद्यार्थियों ने किया राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का दौरा

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, पंचकूला का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (मानद विश्वविद्यालय) जयपुर के बीएएमएस बैच 2023-24 के विद्यार्थियों ने दौरा किया। विद्यार्थियों ने एडमिन ब्लॉक, हर्बल गार्डन और अस्पताल में ओपीडी एवं आईपीडी के साथ पंचकर्म, फिजियोथेरेपी, फामेर्सी का अवलोकन किया।

शैक्षणिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के विभिन्न आयामों को व्यावहारिक रूप से समझा। छात्र-छात्राओं से संवाद करते हुए डीन इंचार्ज प्रोफेसर सतीश गंधर्व ने कहा कि आयुर्वेद केवल रोगों के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है। वर्तमान समय में जब जीवनशैली जनित रोग तेजी से बढ़ रहे हैं, तब आयुर्वेद की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने ने औषधीय पौधों के बारे में बताते हुए कहा कि पेड़-पौधे का आयुर्वेद में जड़ी-बूटियों के तौर पर होता है। संस्थान के हर्बल गार्डन में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे हैं, जोकि आयुर्वेद उपचार में कारगर हैं। उन्होंने छात्र-छात्राओं को पेड़-पौधों के संरक्षण का भी आह्वान किया।

प्रोफेसर सतीश गंधर्व ने बताया कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) संजीव शर्मा और डीन प्रोफेसर गुलाब चंद पमनानी के मार्गदर्शन में बीएएमएस के साथ पंचकर्म कोर्स संचालित किए जा रहे हैं और नए कोर्सों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। उप चिकित्सा अधीक्षक डॉ. गौरव गर्ग ने अस्पताल की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया कि संस्थान में 12 विशेष ओपीडी संचालित हैं। आईपीडी सुविधा भी है, जहां पर रोगियों की देखभाल और उपचार किया जा रहा है। संस्थान के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा रोगियों को परामर्श और उपचार किया जा रहा है। हर रोज संस्थान में 500 से ज्यादा रोगी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।

द्रव्य गुण विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मनीष पमनानी ने विद्यार्थियों को संस्थान का दौरा कराया। उन्होंने हर्बल गार्डन में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों के उपयोग के बारे में विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर एनआईए पंचकूला से शरीर रचना विभाग से विभागाध्यक्ष एवं मुख्य छात्रावास अधीक्षक प्रोफेसर प्रह्लाद रघु, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. समित मसंद तथा एनआईए जयपुर से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रितेश रमनानी और डॉ. तरुण शर्मा प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

स्व-गणना का अंतिम दिन आज: हरियाणा में वास्तविक आवास सूचीकरण व जनगणना अभियान 1 मई से होगा शुरू

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

गृह मंत्रालय, हरियाणा के जनगणना संचालन निदेशक डॉ. ललित जैन ने हरियाणा के सभी निवासियों से अपील की है कि वे 30 अप्रैल को स्व-गणना पूर्ण करें, क्योंकि यह इस सुविधा का अंतिम दिन है। उन्होंने सूचित किया कि हरियाणा में 2.45 लाख से अधिक घरों ने पहले ही स्व-गणना पूरी कर ली है, जो नया रिकॉर्ड स्थापित करता है व राज्य भर में मजबूत जन भागीदारी व जागरूकता को दशार्ता है। विशेष रूप से, युवाओं में स्व-गणना हेतु उल्लेखनीय उत्साह देखा गया। स्व-गणना एक सरल प्रक्रिया है पोर्टल पर जाकर 5-7 मिनट में पूर्ण की जा सकती है। पूर्ण होने पर नागरिकों को एक विलक्षण आईडी नंबर प्राप्त होगा, जिसे फील्ड विजिट के दौरान गणक के साथ साझा करना अनिवार्य है। डॉ. जैन ने बताया कि वास्तविक आवास सूचीकरण व जनगणना अभियान हरियाणा भर में 1 मई, 2026 से प्रारंभ होगा। उन्होंने आम जनता से अपने क्षेत्रों में आने वाले सभी गणकों व पर्यवेक्षकों को पूर्ण सहयोग देने व सही, सटीक व अपडेटिड जानकारी प्रदान करने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों द्वारा दी गई सभी जानकारी पूर्ण गोपनीय रखी जाएगी व किसी व्यक्ति या संस्था के साथ साझा नहीं की जाएगी। अभियान के महत्व पर जोर देते हुए डॉ. जैन ने कहा कि जनगणना राष्ट्रीय दायित्व है जिसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के विकास, नीति निर्माण व संसाधनों के समान वितरण में योगदान देता है। उन्होंने आगे सूचित किया कि जनगणना अधिकारियों को आवश्यक जानकारी देने से इंकार या उनके साथ असहयोग जनगणना अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

डीएवी कॉलेज यमुनानगर के विद्यार्थियों ने थापली नेचर कैंप में प्रकृति को नजदीक से जाना

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

डीएवी कॉलेज यमुनानगर के विद्यार्थियों ने हाल ही में थापली स्थित नेचर कैंप में तीन दिवसीय शैक्षणिक एवं प्रेरणादायक प्रवास के दौरान प्रकृति, पर्यावरण संरक्षण तथा अनुशासित जीवनशैली का गहन अनुभव प्राप्त किया। इस विशेष शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ प्रकृति के वास्तविक स्वरूप से जोड़ना, पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना तथा उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना था। तीन दिनों तक चले इस नेचर कैंप में विद्यार्थियों ने प्राकृतिक परिवेश के बीच रहकर पहाड़ों, जंगलों, स्वच्छ वातावरण और जैव विविधता को निकट से देखा तथा समझा। शिविर के दौरान विद्यार्थियों ने प्रातःकालीन भ्रमण, योग, समूह चर्चा, पर्यावरण संरक्षण विषयक गतिविधियों तथा स्वच्छता अभियानों में भाग लिया। विद्यार्थियों ने पेड़-पौधों के महत्व, जल संरक्षण, वन्य जीवन तथा संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

शिविर में विद्यार्थियों ने आधुनिक जीवनशैली की भागदौड़ से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन के महत्व को महसूस किया। मोबाइल और डिजिटल साधनों से कुछ समय दूरी बनाकर विद्यार्थियों ने आत्मचिंतन, सामूहिक सहयोग और अनुशासन का अभ्यास किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने टीम भावना, नेतृत्व क्षमता तथा आत्मनिर्भरता जैसे गुणों को भी विकसित किया। नेचर कैंप के अंतिम दिन विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह शिविर उनके जीवन का अत्यंत प्रेरणादायक अनुभव रहा। उन्होंने बताया कि प्रकृति के बीच बिताए गए ये तीन दिन उन्हें मानसिक शांति, नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच प्रदान करने वाले रहे। विद्यार्थियों ने कहा कि ऐसे शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए ताकि युवा पीढ़ी प्रकृति के महत्व को समझ सके।

आज प्रातः विद्यार्थियों ने विधायक हॉस्टल में सामूहिक रूप से नाश्ता किया। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। विधायक हॉस्टल में विद्यार्थियों का आत्मीय स्वागत किया गया तथा उन्हें अनुशासन, समय प्रबंधन और सामूहिक जीवनशैली के महत्व से भी अवगत कराया गया। विद्यार्थियों ने इस अवसर को यादगार बताते हुए कहा कि उन्हें नई जगह पर सामूहिक रूप से समय बिताने का अवसर मिला, जिससे आपसी सहयोग और मित्रता की भावना और मजबूत हुई। इस अवसर पर यूथ वेलफेयर कोऑर्डिनेटर श्री नरेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आज का युवा देश का भविष्य है और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने ह्लनेशन फर्स्टह्व का संदेश देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को अपने जीवन में अनुशासन, मेहनत, ईमानदारी और सेवा भाव को अपनाना चाहिए।

युवा कल्याण संयोजक ने विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व, समय के सदुपयोग, लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सोच तथा सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि युवा यदि सही दिशा में अपनी ऊर्जा का उपयोग करें तो समाज और राष्ट्र दोनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को नशामुक्ति, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक समरसता के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है कि युवा केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न रहें, बल्कि समाज और देश के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाएं। विद्यार्थियों को अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनना चाहिए तथा हर कार्य में देशहित को प्राथमिकता देनी चाहिए।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे और अपने विचार साझा किए। विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि निरंतर प्रयास, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक दृष्टिकोण से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। डीएवी कॉलेज प्रशासन ने इस सफल आयोजन के लिए सभी आयोजकों, मार्गदर्शकों तथा सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि भविष्य में भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु इस प्रकार के शैक्षणिक, सामाजिक और प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। यह तीन दिवसीय नेचर कैंप विद्यार्थियों के लिए केवल भ्रमण कार्यक्रम नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों, पर्यावरण चेतना, अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति का अनूठा पाठ साबित हुआ। विद्यार्थियों ने नई सीख, नए अनुभव और नई प्रेरणा के साथ इस शिविर को यादगार बताया।